Machine Translated by Google

X

परोसने के लिए उपज: पक्षियों के लिए काटे गए केले के साथ एक महिला।

X

पका और तैयार: एक ग्रामीण पक्षियों के लिए केले रख रहा है।

एक्स

फलती-फूलती प्रजातियाँ: ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल को असम के मोरीगांव जिले के मायोंग गांव में सुरक्षित आश्रय मिल गया है।

हॉर्नबिल हेवन

असम के मोरीगांव जिले के मायोंग गांव के लोग ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की एक छोटी सी कॉलोनी को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। उनका मानना है कि ये पक्षी शांति के अग्रदूत हैं

ऋतु राज कोंवर
rituraj.k@thehindu.co.in

मोरीगांव के मायोंग गांव में

लोग

असम के 20 जिलों के पुलिस महानिदेशकों ने ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए आदर्श आवास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जिससे इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों में मदद मिली है।
सामुदायिक संरक्षण पहल की बदौलत, अब गांव में ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल (एंथ्राकोसेरोस एल्बिरोस्ट्रिस) की एक छोटी कॉलोनी है। लगभग 30 की संख्या में यह छोटा झुंड इलाके में और उसके आसपास घोंसला बना रहा है और प्रजनन कर रहा है।

प्रकृति प्रेमी निपेन कहते हैं, "गांव में हॉर्नबिल कई सालों से रह रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 30 से ज़्यादा है। वे गांव वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं और हर कोई पक्षी कॉलोनी के संरक्षण में लगा हुआ है।" वे कहते हैं, "अच्छी बात यह है कि पक्षी हमारे गांव में बसेरा कर रहे हैं और प्रजनन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह आवास उपयुक्त लग रहा है।"

ग्रामीणों ने फलदार पौधे लगाने को प्राथमिकता दी है
पेड़ लगाए गए हैं ताकि हॉर्नबिल को आस-पास के इलाकों में भोजन मिल सके। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने पिछवाड़े में केले और पपीते के पेड़ लगाए हैं।
गांव वाले हॉर्नबिल को पवित्र मानते हैं और

ऐसा कुछ भी करने से बचें जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या परेशान कर सकता है। उनका मानना है कि हॉर्नबिल पूरे देश के लिए शांति और समृद्धि के अग्रदूत हैं
क्षेत्र।

मायोंग में माईबोंग इको रिसॉर्ट के पास बसी हॉर्नबिल कॉलोनी ने इस क्षेत्र में पक्षी प्रेमियों के आने-जाने में मदद की है। हॉर्नबिल कॉलोनी एक तरह का पर्यटक आकर्षण बन गई है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग, खास तौर पर पक्षी देखने वाले और प्रकृति प्रेमी, साल के अलग-अलग समय में सिर्फ़ पक्षियों को देखने के लिए आते हैं।

पर्यटकों और पक्षी-प्रेमियों के अलावा, देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र, ग्रामीणों द्वारा किए गए अद्वितीय संरक्षण प्रयासों का अध्ययन करने के लिए माईबोंग इको रिसॉर्ट का दौरा करते हैं।

ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल एक अत्यधिक अनुकूलनीय प्रजाति है, जो भारत में हिमालय की तराई, उत्तर-पूर्व और पूर्वी भागों में पाई जाती है।

उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में अपनी प्रमुख भूमिका के कारण इन्हें 'वन इंजीनियर' या 'वन के किसान' कहा जाता है। हॉर्नबिल उस वन के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं जिसमें वे घोंसले बनाते हैं।

X

समूह लंच: ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल का एक झुंड केले खा रहा है।

Machine Translated by Google

फ़्रेम में समाचार

एक्स

ऑर्डर पर बनाया गया: एक आदमी हॉर्नबिल के लिए सूखी घास से एक घोंसला बनाता है।

एक्स

गर्म और सुरक्षित: लड़के एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बनाते हैं।

एक्स

सभी एक पंक्ति में: जंगल मैना फल खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। मायोंग पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियों का घर है।

एक्स

ओस भरा नाश्ता: एक सनबर्ड गांव वालों द्वारा लगाए गए फूलों को खा रहा है।

एक्स

टप, टप: एक कठफोड़वा खाने के लिए कीड़ों को खोजता है।

Machine Translated by Google

ऑप्टिकल बायोसेंसर तेजी से मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाता है

द हिंदू ब्यूरो

मानव का एक नया संस्करण
एमपॉक्स ने ली जान
रिपोर्ट किए गए संक्रमण वाले लगभग 5%
लोगों में से
डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव में
कांगो की जनता तब से
2023 तक, उनमें से कई बच्चे हैं। तब से, यह

अन्य देशों में फैल गया।
इसके अलावा, एक अलग लेकिन
दुर्लभतः घातक एमपॉक्स वैरिएंट
एक प्रकोप के लिए जिम्मेदार था जो फैल
गया है
100 से अधिक देश
2022 से। एक उर-
सज्जन को तेजी से और की जरूरत है
अधिक लागत प्रभावी निदान उपकरण
रोकथाम के लिए
एमपॉक्स के प्रसार की संभावना के लिए
तैयारी करना
भविष्य की वैश्विक महामारी।
संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ताओं ने
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन
डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन,
और बोस्टन विश्वविद्यालय
अब एक विकसित किया है
ऑप्टिकल बायोसेंसर जो
मंकीपॉक्स का शीघ्र पता लगाना,
एमपॉक्स नामक वायरस उत्पन्न होता है।
यह प्रौद्योगिकी चिकित्सकों को रोग का निदान
करने में सक्षम बना सकती है
बीमारी उस बिंदु पर है
इंतज़ार करने की बजाय ध्यान रखें
प्रयोगशाला के परिणाम। अध्ययन था
नवंबर को प्रकाशित
14, 2024, बायोसेंसर और
बायोइलेक्ट्रॉनिक्स.

क्लिनिक में, एमपॉक्स
बुखार जैसे लक्षण,
दर्द, चकत्ते और घाव
कई लोगों के समान
अन्य वायरल संक्रमण। तो यह
चिकित्सकों के लिए यह आसान नहीं है
मंकीपॉक्स को पहचानें
इन अन्य बीमारियों से
बस देखकर
मरीज़।
पीसीआर परीक्षण महंगा है,
प्रयोगशाला की आवश्यकता है, और
इसमें कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं
परिणाम प्राप्त करें। बोस्टन यूनिवर्सिटी लैब
ने विकसित किया है
वायरस का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल
बायोसेंसर
इबोला रक्तस्रावी कारण
बुखार और COVID-19,
दूसरों के बीच में।
शोधकर्ताओं ने प्रयोग किया
से एकत्र किए गए नमूने
एक मरीज के घाव
प्रयोगशाला-पुष्टि
mpox. उन्होंने इनक्यूबेट किया
मोनोक्लोनल के साथ नमूने
मंकीपॉक्स एंटीबॉडी
जो प्रोटीन से बंधते हैं
वायरस की सतह। वायरस-एंटीबॉडी
कॉम्प्लेक्स
फिर छोटे में स्थानांतरित कर दिया
की सतह पर कक्ष
सेंसर पर सिलिकॉन चिप्स
जिन्हें ठीक करने के लिए इलाज किया गया
इन नैनोकणों.
चमकती सटीक लहर-
लाल और नीले रंग की लम्बाई
एक साथ प्रकाश
चिप्स के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ,
जिसके परिणामस्वरूप थोड़ा
अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ जब
वायरस-एंटीबॉडी नैनो-कण मौजूद थे।

रंगीन कैमरे का इस्तेमाल किया गया
इस छोटे संकेत का पता लगाएं और
व्यक्तिगत कणों की गिनती करें
उच्च संवेदनशीलता के साथ।
बायोसेंसर परख आसानी से एमपॉक्स
नमूनों में भेदभाव करता है
इन अन्य वायरसों से
दो मिनट के भीतर.

भारत में 35% डॉक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं

अध्ययन से पता चलता है कि काम के दौरान

स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा कई जोखिम कारकों के एक साथ आने के कारण पनपती है - भीड़भाड़, कम स्टाफ, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय, देखभाल की कथित या वास्तविक अपर्याप्तता, संचार में चूक

राजीव जयदेवन

एक सरकारी अस्पताल
चेन्नई में ताल
मैं एक दुखद घटना पर 13 नवंबर 2024,
एक डॉक्टर बार-बार
प्रदर्शन करते समय चाकू मारा गया
अपने कर्तव्यों का पालन करें।
क्रूर बलात्कार हत्या
कोलकाता में युवा डॉक्टर
अभी तीन महीने पहले ही,
एक परेशान करने वाली बात को रेखांकित करना
और लगातार मुद्दा: कार्यस्थल पर हिंसा

स्वास्थ्य देखभाल पेशे।
भारत भर के डॉक्टर
कार्यस्थल की सूचना दी है
हिंसा बढ़ती जा रही है
खतरा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा
2017 में किया गया एक अध्ययन
कैल एसोसिएशन ने पाया कि
पूरे विश्व में 75% से अधिक डॉक्टर
भारत ने अनुभव किया था
कार्यस्थल पर हिंसा, जबकि
लगभग 63% लोग ऐसा करने में असमर्थ थे
बिना किसी परेशानी के मरीजों को देखें
हिंसा का डर।
अध्ययन में पाया गया कि लगभग
70% डॉक्टरों को कार्यस्थल पर हिंसा का
सामना करना पड़ा
काम.मौखिक दुर्व्यवहार और
शारीरिक टकराव
आस-पास खड़े लोगों की ओर से ऐसी टिप्पणियां अक्सर
होती हैं, फिर भी यह केवल एक अंश है
घटनाओं का औपचारिक रूप से
रिपोर्ट.
आईएमए केरल में हमारी टीम
राज्य ने एक सर्वेक्षण कराया
अगस्त 2024 में शामिल
पूरे भारत में 3,885 डॉक्टर
— अपनी तरह का सबसे बड़ा —
जिसमें सुरक्षा उपायों में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर किया गया।

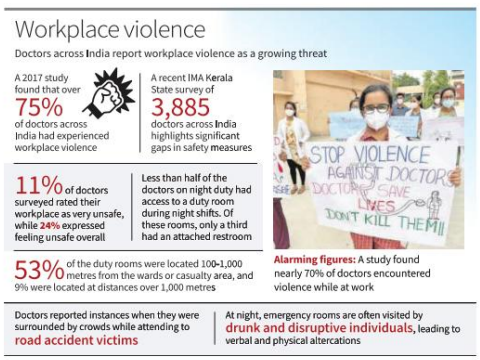

प्रतिभागियों ने
सुरक्षा, पर्याप्तता और सुरक्षा के संबंध
में अपने अनुभव साझा किए।
ड्यूटी रूम, और रात की ड्यूटी के जोखिम,
और समाधान की पेशकश की।
उत्तरदाताओं में से 60% से अधिक
महिलाएं थीं, जिनमें से कई
जिनमें से सामना करने की सूचना दी
शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार
काम के दौरान। सुरक्षा पैमाने पर, 11% ने
अपनी रेटिंग दी
कार्यस्थल को बहुत असुरक्षित बताया,
जबकि 24% ने समग्र रूप से असुरक्षित
महसूस किया।

Alarming figures: A study found nearly 70% of doctors encountered violence while at work

डीवाई द्वारा आयोजित किया गया था
भारतीय चिकित्सा संघ
और केरल पत्रिका के अक्टूबर अंक में प्रकाशित
हुआ
चिकित्सकीय पत्रिका।

प्रणालीगत समस्या

कार्यस्थल पर हिंसा
स्वास्थ्य सेवा अक्सर इसका संकेत है
गहरी प्रणालीगत समस्याएं.
हिंसा वहीं पनपती है जहां
कई जोखिम कारक सामने आते हैं
सर्वेक्षण में पाया गया कि,
इनमें अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाके शामिल हैं।
कर्मचारी कम होना, कम कर्मचारी होना, विरल होना
सुरक्षा उपाय, कथित या वास्तविक अपर्याप्तता

देखभाल, संचार
चूक, बढ़ते खर्च, शिकायत का अभाव

निवारण तंत्र,
और प्रभाव में व्यक्तियों की उपस्थिति

शराब या नशीली दवाओं का सेवन।
कुछ अस्पतालों में अनुभवहीन डॉक्टरों
को काम पर रखा जाता है।
उच्च जोखिम में अकेले तैनात
आकस्मिक चिकित्सा और आईसीयू जैसे क्षेत्र
रात की शिफ्ट के दौरान,
एक कठिन काम हो सकता है
वरिष्ठ बैकअप के बिना
साइट पर।
हमारे सर्वेक्षण से पता चला
एक और चिंताजनक वास्तविकता:
रात्रि ड्यूटी पर तैनात आधे से भी कम डॉक्टरों को
ड्यूटी रूम तक पहुंच थी

रात की शिफ्ट, और उनमें से,
केवल एक तिहाई के पास ही संलग्न शौचालय
था।
जब उपलब्ध हो, तो 53%
ड्यूटी रूम स्थित थे
दूर (100 से 1,000
मीटर) और 9% 1,000 मीटर से अधिक दूरी
पर स्थित थे
वार्डों से मीटर या
हताहत क्षेत्र।
बुनियादी सुविधाएं नजदीक
वार्डों में डॉक्टरों को मजबूर किया जाता है
अलग-थलग गलियारों और खराब रोशनी
वाले रास्ते से गुजरें
आधार.
जब ड्यूटी रूम थे
अनुपलब्ध या अपर्याप्त,
उदाहरण के लिए जब
दरवाजों पर ताले नहीं थे, डॉक्टरों
रात में वैकल्पिक विश्राम स्थल ढूंढने के लिए
मजबूर होना पड़ा,
सर्वेक्षण में पाया गया कि महिलाएं
डॉक्टरों ने खाली वार्ड बेड पर सोने की बात
स्वीकार की,
संभावित रूप से उन्हें उजागर करना
रात भर साइट पर रहने वाले धैर्यवान दर्शकों
के लिए।
डॉक्टर ने बताया कि
फोल्डेबल चाकू और काली मिर्च
उसके हैंडबैग में स्प्रे के कारण
सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
ty अक्सर de- था
अनुपस्थित या अनुपस्थित के रूप में लिखा गया
अपर्याप्त। कई युवा डॉक्टरों ने निराशा व्यक्त
की-
प्रशासकों पर नियंत्रण
उनकी सुरक्षा की अनदेखी
चिंताएं.
सर्वेक्षण के जवाब में डॉक्टरों ने ऐसे
मामलों की जानकारी दी जब उन्हें

भीड़ से घिरा हुआ
सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की देखभाल करते
समय या दुर्घटना क्षेत्र में प्रक्रियाएँ करते समय।

कमरे, विशेष रूप से
रात में, अक्सर लोग आते हैं
नशे में धुत और विघटनकारी व्यक्ति, जिसके
कारण मौखिक
और शारीरिक झड़पें।
डॉक्टर रिपोर्ट करने में हिचकिचाते हैं
ये घटनाएँ स्वास्थ्य के कारण होती हैं-
vy कार्यभार और सामाजिक या
प्रशासनिक दबाव के कारण हिंसा का चक्र
चलता रहा
लेंस जारी रखने के लिए.

सुधारात्मक उपाय

अध्ययन में सुझाव दिया गया कि
सरल को अपनाना
न्यूनतम निवेश के साथ उपाय करने से स्वास्थ्य
सुविधाओं में हिंसक घटनाओं में कमी आ सकती
है।
देखभाल के लिए
उदाहरण, भीड़ नियंत्रण
और प्राथमिकता निर्धारण से हिंसक
घटनाओं में कमी आ सकती है।
रोगी-देखभाल में असीमित संख्या में बाईस-
टेंडर्स
क्षेत्रों में संघर्ष की आशंका वाला माहौल बनता है।
समूहों को रोकने के लिए सख्त आगंतुक नीतियों
को लागू करना

चारों ओर एकत्र होने से
रोगियों और ध्यान भटकाने वाला या
चिकित्सा कर्मचारियों को डराना-धमकाना
भी एक लंबा रास्ता तय करना होगा
हिंसक घटनाओं में कमी लाना।
इससे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को ध्यान
केंद्रित करने में मदद मिलेगी
उनके मरीज़ों के बिना
दखल अंदाजी।
अकेले कानून से ही हो सकता है
प्रभावी प्रवर्तन और व्यापक उपायों के अभाव
में यह अपर्याप्त होगा

ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा उपाय। उदाहरण के
लिए, केरल
2012 में अस्पताल संरक्षण कानून बनाया
गया, जिसे अद्यतन किया गया
2023 में। हालाँकि, समस्या बनी हुई है। दुखद

युवा डॉ.
वंदना दास 2023 में
कोल्लम, केरल के मुख्य आकर्षण
केवल कानून की सीमाएं।

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) जैसे
पेशेवर संगठनों ने

डॉक्टरों के लिए संचार और सॉफ्ट कौशल
प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसमें शामिल हैं

तोड़ने के तरीके पर मार्गदर्शन
बुरी खबर।
लेकिन यहां तक कि सबसे अच्छा-
प्रशिक्षित पेशेवर प्रभावी ढंग से काम नहीं कर
सकते
भीड़भाड़, अपर्याप्त संसाधन वाली सेटिंग्स।
स्वास्थ्य सेवा में बढ़ती हिंसा

सेटिंग्स तत्काल मांग करती हैं-
दृढ़ एवं निर्णायक कार्रवाई
अस्पताल प्रशासकों और नीति निर्माताओं से
लेकर
अंतर्निहित कारणों से निपटें। आगे की प्रतीक्षा
में
समस्या का प्रमाण
कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता.
(राजीव जयदेवन, अध्यक्ष, अनुसंधान प्रकोष्ठ,
केरल)
राज्य आईएमए, और प्रथम
अध्ययन के लेखक)

स्नैपशॉट

सफेद कार हेडलाइट्स अधिक

पतंगों को चकाचौंध करने की संभावना

सफेद रोशनी, जैसे कि आधुनिक कार में होती है
हेडलाइट्स, पतंगों को खतरे में डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पक्षी अनियमित रूप से उड़ते हैं।
पतंगों को प्रकाश के छोटे-छोटे विस्फोटों के संपर्क में लाया गया, जिससे
कार की हेडलाइट्स, फिर उनकी उड़ान देखी
उन्होंने पाया कि सफ़ेद रंग का पैटर्न
आधुनिक कार में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोर-लेपित एल.ई.डी.
हेडलाइट्स ने पतंगों को चकाचौंध कर दिया और उनके
इस प्रकाश के संपर्क में आने वाले पतंगों की उड़ान 80% अधिक थी
अनियमित रूप से या प्रकाश की ओर उड़ने की संभावना,
अन्य रोशनी के संपर्क में आने वालों की तुलना में।

लॉस एंजिल्स में पहाड़ी शेर अधिक रात्रिचर बनना

ग्रेटर लॉस एंजिल्स में पहाड़ी शेर हैं
इससे बचने के लिए अपनी गतिविधियों को सक्रिय रूप से बदलना
साइकिल चालकों, पैदल यात्रियों, जॉगर्स, और के साथ बातचीत करना
एक अध्ययन में पाया गया है कि अन्य मनोरंजनकर्ता भी मनोरंजन के प्रति आकर्षित होते हैं।
पाया गया कि पहाड़ी शेर, उन क्षेत्रों में रहते हैं,
मानव मनोरंजन का स्तर अधिक था
अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में शेरों की तुलना में रात में सक्रिय रहने वाले
सुबह और शाम के समय ज़्यादा सक्रिय थे।
उन्होंने कहा कि उनके निष्कर्ष एक आशाजनक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
एक बड़े, घने जंगल में मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व
मानव आबादी.

दिन में नमी कम हो जाती है शहरी क्षेत्रों में ठंडक का लाभ

यद्यपि पेड़ तापमान को कम कर सकते हैं, फिर भी वे
वाष्पीकरण के कारण आर्द्रता में वृद्धि होती है।
तापमान में कमी और आर्द्रता में वृद्धि
एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम परिवर्तन होता है
गीले-बल्ब तापमान, जो एक माप है
संयुक्त गर्मी और आर्द्रता तनाव। दिन के समय
हरे भरे स्थान ठंडे लग सकते हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण
आर्द्रता से राहत का अहसास कम हो जाता है।
रात में, हरे भरे स्थान तापमान को कम कर सकते हैं
और मिट्टी में ऊष्मा भंडारण कम होने के कारण आर्द्रता में कमी आती है।

नेत्रदान और कॉर्निया प्रत्यारोपण

के बोल
विज्ञान
डी. बालसुब्रमण्यम

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी
अंधेपन की रोकथाम के लिए
(आईएपीबी) हर सेकंड को चिह्नित करता है
अक्टूबर माह का गुरुवार,
जो 14 अक्टूबर को पड़ता है
इस वर्ष, वर्ल्ड साईट के अनुसार
दिन. उद्देश्य वृद्धि करना है
सभी के लिए जागरूकता और समर्थन
सुनिश्चित करने के प्रयास
दुनिया भर में हर कोई दृष्टि से लाभ उठा सकता
है। इसमें चश्मा प्रदान करना भी शामिल है

जिनको इनकी ज़रूरत है,
क्षतिग्रस्त भागों का उपचार करना
आँख की, मान लीजिए, प्रतिस्थापन द्वारा
आँख में अपारदर्शी लेंस
(मोतियाबिंद) या कॉर्नियल प्रत्यारोपण की
पेशकश करके उसे बहाल करना
दृष्टि. कॉर्नियल अंधापन
अंधेपन का एक प्रमुख कारण है-
भारत में कॉर्नियल
प्रत्यारोपण में पुनर्स्थापन शामिल है-
किसी व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करना
क्षतिग्रस्त कॉर्निया के साथ
स्वस्थ ऊतक का उपयोग करके
दाता। हालाँकि, कई कारक दीर्घकालिक
प्रभाव डालते हैं
इस तरह के ग्राफ्ट की सफलता:
दाता ऊतक की गुणवत्ता,
कॉर्निया की स्थिति कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण
बात, दीर्घकालिक अनुवर्ती देखभाल।

कॉर्निया एक पतली,
स्पष्ट, गुम्बदाकार ऊतक
आँख की वह परत जो ढकती है
पुतली और परितारिका। कॉर्नियल
ऊतक को पारदर्शी बनाये रखने के लिए
विशेषीकृत किया जाता है, ताकि यह
प्रकाश को रेटिना की ओर अंदर की ओर
मोड़ता है
पीठ, जिसमें फोटो-रिसेप्टर कोशिकाएं
होती हैं जो हमारी मदद करती हैं
देखें। यदि किसी कारणवश कॉर्निया क्षतिग्रस्त
हो जाए, तो यह
अपवर्तन की यह क्षमता खो देता है
और प्रकाश अंदर आने दें, और व्यक्ति की
दृष्टि चली जाती है।
दृष्टि बहाल करने का साधन है
प्रत्यारोपण कॉर्निया
के माध्यम से।
ऑस्ट्रियाई नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. ई.के.
ज़िम ने

कॉर्नियल ब्लाइंडनेस अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। गेटी इमेजेज

पहला मानव कॉर्नियल
दाता से प्रत्यारोपण
1905 में आँख. भारत में,
पहला प्रत्यारोपण डॉ. मुथैया द्वारा किया गया
था
1948 में उनके नेत्र बैंक से
चेन्नई, और इंदौर के डॉ आरपी धोन-दा सफल
रहे
पहले को सफल बनाओ
1960 में कॉर्निया प्रत्यारोपण किया गया।
तब से, परिष्कार-
की सफलता दर और सफलता दर
कॉर्निया प्रत्यारोपण
छलांग में वृद्धि हुई और
सीमाएँ। स्पष्ट कॉर्नियल
ऊतक को विभाजित किया जा सकता है
छह परतों में, और आज का
शल्यचिकित्सक प्रत्यारोपण कर सकते हैं
संपूर्ण परत के बजाय केवल एक विशिष्ट
परतीय उप-परत
कॉर्निया। ये सर्जरी तेजी से ठीक होने की
अनुमति देती है और
प्रतिरक्षा अस्वीकृति की संभावना को कम करें

प्रत्यारोपण.
ये सभी विशेषताएं
कॉर्निया प्रत्यारोपण एक आसान विकल्प
है। हालाँकि, एक से अधिक बार
भारत में दस लाख लोग
अनुमान है कि यह ख़राब हो गया है
कॉर्नियल अंधेपन के कारण।
50 वर्ष से कम आयु के लोगों में अंधेपन का
मुख्य कारण है
वर्ष की आयु के अनुसार
राष्ट्रीय कार्यक्रम
अंधेपन और दृश्य हानि के नियंत्रण के लिए
भारत में पिछले कई वर्षों से

अनौपचारिक लक्ष्य रहा है
वार्षिक दर प्राप्त करने की
1,00,000 कॉर्नियल प्रत्यारोपण की जरूरत
है। हम अभी भी बहुत पीछे हैं
इस दर. ऊतक जैसे
कॉर्निया केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही दान
किया जा सकता है।

भारत में दर्ज की गई मौतें,
एक छोटा प्रतिशत कॉर्निया दान के लिए पात्र
है।
हालाँकि, हमें वर्तमान में कॉर्निया प्राप्त नहीं
होते हैं
सभी पात्र दाताओं से, विशेष रूप से
प्रक्रियागत देरी और सहमति के कारण

कानून.
इस समस्या से निपटने के लिए
सरकार एक योजना पर विचार कर रही है।
मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में
संशोधन करके
'अनुमानित सहमति'। यह
अर्थात सभी पात्र दाता
माना जाता है कि उन्होंने अपनी सहमति दे दी
है। हालाँकि, अनुमानित सहमति अवश्य होनी
चाहिए
यह कठोर नहीं होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है
इसमें परिवार से औपचारिक अनुमति भी
शामिल है
सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित करें —
एक 'नरम' विकल्प.
एक उदार दान, एक
मेहनती प्राप्तकर्ता जो देखभाल के साथ
पालन करता है, और
प्रणाली जो उन्हें सक्षम बनाती है
दोनों की जरूरत है
घंटा. यह महत्वपूर्ण है तो
सरकार का नारा: 'नेत्र दान', भारत के आदर्श
वाक्य के साथ तालमेल रखता है

नेत्र रोग विशेषज्ञ: 'पश-यंतु सर्वे जन:,' बोल-

से सहमति से संचालित
परिवार: 'सम्मति
'परिवरस्य।'
(यह आलेख 1974 में लिखा गया था)
तेजाह के साथ सहयोग
बालनट्रापु, एसोसिएट डायरेक्टर -
विज्ञान, स्वास्थ्य डेटा और स्टोरी टेलिंग,
एल.वी.
प्रसाद नेत्र संस्थान)

प्रश्न कोना

नमक क्रिस्टलीकरण

चिमनी का आकार कैसा होता है?
फर्श पर वेंट
मृत सागर का निर्माण कैसे हुआ?

गोताखोरों की एक टीम ने
पता चला कि मीटर-ऊँचा
चिमनी के आकार के वेंट
मृतकों की झील का तल
समुद्र का निर्माण किसके द्वारा होता है?
अविरल
खनिजों का क्रिस्टलीकरण
भूजल से
अत्यधिक उच्च नमक सामग्री
झील से बहता हुआ
मंजिल। शोधकर्ताओं
पता चला कि खारा
भूजल बहता है
चिमनी के माध्यम से
झील के तल पर। लेकिन
नमक कहां से आ रहा है
भूजल से?
आस-पास से
जलभृतों में प्रवेश करता है
खारे झील तलछट,
बहुत पुराना रिसाव
और चट्टान की मोटी परतें
मुख्य रूप से शामिल
खनिज हैलाइट। यह तब
झील में बहता है
नमकीन पानी से संपर्क करें
झील का पानी इसका कारण बनता है
घुले हुए लवण, विशेष रूप से
हैलाइट,
स्वतः स्फटिकित होना
से उभरने के बाद
झील का तल, छिद्रों का निर्माण करता है
पहली बार देखा गया।
इनमें कई गुना वृद्धि हो सकती है
एक ही सेंटीमीटर में
दिन. कई पतला
चिमनियाँ एक से दो थीं
मीटर ऊंचे हैं, लेकिन वे भी
से अधिक दिग्गज शामिल हैं
सात मीटर ऊँचा,
से अधिक व्यास
दो-तीन मीटर.

पाठकगण अपने प्रश्न भेज सकते हैं /
के उत्तर
questioncorner@thehindu.co.in

नि:शुल्क व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें https://whatsapp.com/channel/0029Van2VRb6RGJOKH6oBd0F
नि:शुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़ें https://t.me/+Bu7sen QdhlODg1

क्या रियाद शिखर सम्मेलन गाजा युद्ध पर प्रभाव डालेगा?

अरब राज्यों ने यह संदेश क्यों दिया है कि फिलिस्तीन प्रश्न का समाधान पश्चिम एशिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण है?

स्टेनली जॉनी

अब तक कहानी:

पिछले सप्ताह अरब और इस्लामी देशों से फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक असाधारण संयुक्त
सऊदी अरब ने नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की
शिखर सम्मेलन में इजरायल के साथ संबंधों को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई।
गाजा और लेबनान पर सैन्य आक्रमण।

नेताओं ने क्या कहा?

नेताओं ने गाजा में इजरायली सेना के "चौंकाने वाले और भयानक अपराधों", उसके "नरसंहार के अपराध" और "जातीय सफाए" की निंदा की और इन अपराधों की जांच के लिए एक "स्वतंत्र, विश्वसनीय" अंतरराष्ट्रीय समिति की मांग की। इसने इजरायली कब्जे को समाप्त करने और "4 जून, 1967 की तर्ज पर एक स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करने के उपायों का आग्रह किया, जिसकी राजधानी अल-कुद्स [यरूशलम] हो, जो दो-राज्य समाधान पर आधारित हो और स्वीकृत संदर्भों और 2002 की अरब शांति पहल के अनुसार हो।"

शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है?

हाल के वर्षों में, अरब देशों ने फिलिस्तीन के मुद्दे को दरकिनार करते हुए इजरायल के साथ संबंधों को सुधारने या सामान्य करने की इच्छा दिखाई है, जो अरब शांति पहल की भावना का उल्लंघन है, जिसमें फिलिस्तीन राज्य के निर्माण के बदले में इजरायल को मान्यता देने का वादा किया गया था। 2020 में, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजरायल के साथ एक समझौते में संबंधों को सामान्य किया, जिसे अरब शांति पहल कहा जाता है।

7 अक्टूबर के हमले से पहले, अरब देश इजरायल के साथ संबंधों को औपचारिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन गाजा और लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के बाद, यह प्रयास पटरी से उतर गया है।

अब्राहम समझौते.
पिछले,
अरब-इज़रायल
सामान्यीकरण —
1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के साथ हुए समझौते - कुछ इजरायली समझौतों के साथ हुए।

इसराइल ने हस्ताक्षर किये
के लिए रूपरेखा
1979 में मिस्र के साथ मध्य पूर्व में शांति (कैंप डेविड समझौते के बाद), कब्जे वाले पश्चिमी तट और गाजा में एक स्वायत्त फिलिस्तीनी स्वशासी प्राधिकरण की स्थापना पर सहमति, और 1993 के ओस्लो समझौते के बाद इजरायल-जॉर्डन समझौता (वादी अरब संधि), जिसने फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की नींव रखी।

लेकिन जब अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं मिला। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले और गाजा (और पश्चिमी तट) पर इजरायल के जवाबी युद्ध के बाद, अरबों ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की, लेकिन यहूदी राज्य को भड़काने से परहेज किया। हालाँकि, इजरायल द्वारा किए जा रहे युद्ध को लेकर उनकी बेचैनी और गुस्सा जाहिर था। रियाद शिखर सम्मेलन में, उन्होंने अपना सामूहिक गुस्सा व्यक्त किया और इजरायल और अमेरिका दोनों को संदेश दिया कि फिलिस्तीन के सवाल का समाधान पश्चिम एशिया में शांति की कुंजी है।

सऊदी-इज़राइल संबंध कहाँ खड़े हैं?

सितंबर 2023 में, सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि राज्य इजरायल के साथ सामान्यीकरण समझौते को अंतिम रूप देने के एक उन्नत चरण में था। अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए, सऊदी अरब के साथ समझौता सामान्यीकरण प्रक्रिया का तार्किक अगला कदम था। अरब देश भी ईरान से लगातार चिंतित थे और वे इजरायल के साथ संबंधों को मजबूत करने और संभावित ईरानी खतरों के खिलाफ एक संयुक्त रक्षात्मक कवच बनाने के लिए तैयार थे।

फिर 7 अक्टूबर को हमला हुआ और गाजा पर इजरायल का युद्ध शुरू हो गया। सऊदी अरब और यूएई हमास ब्रांड के राजनीतिक इस्लाम को अपनी राजशाही व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन वे अरब स्ट्रीट और पश्चिम एशिया के मूड को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो मुख्य रूप से इजरायल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक है। युद्ध के कुछ महीने बाद, सउदी ने कहा कि इजरायल के साथ भविष्य का कोई भी समझौता फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने से जुड़ा होना चाहिए। 18 सितंबर को, क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने कहा, "राज्य पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने के अपने अथक प्रयासों को बंद नहीं करेगा, और हम पुष्टि करते हैं कि राज्य इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा।" रियाद शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर, प्रिंस मोहम्मद के नाम से मशहूर एमबीएस ने युद्ध की सबसे कठोर आलोचना करते हुए कहा कि इजरायल गाजा में "नरसंहार" कर रहा है। यह पिछले एक साल में सऊदी-इजरायल संबंधों में लगातार गिरावट की ओर इशारा करता है।

क्या अरब युद्ध में शामिल होंगे?

बहुत ही असंभव। पिछली बार किसी अरब देश ने इजरायल पर 1973 में हमला किया था, जब मिस्र ने सीरिया के साथ मिलकर सिनाई और गोलान में आश्चर्यजनक हमला किया था, जो क्रमशः मिस्र और सीरिया के क्षेत्र थे, जिन पर इजरायल ने 1967 में कब्जा कर लिया था।

मिस्र ने फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, बल्कि अपना क्षेत्र वापस पाने के लिए हमला किया था। तब से, इजरायल और अरब राज्यों के बीच शांति बनी हुई है, भले ही इजरायल ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर सैन्य कब्ज़ा कर रखा हो। यह यथास्थिति बदलने की संभावना नहीं है क्योंकि किसी भी अरब देश में इजरायल के खिलाफ युद्ध करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले से पहले, अरब यहूदी राज्य के साथ अपने संबंधों को औपचारिक बनाने के करीब पहुंच रहे थे - अब वह प्रयास पटरी से उतर गया है। अब, यूएई, जिसके इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध थे, का कहना है कि वह "फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना गाजा में युद्ध के बाद के दिन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है"।

अरब देशों ने ईरान के साथ भी तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे शिया राज्य के साथ उनकी दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई है।

संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

आरोपी व्यक्तियों के घरों को अवैध और प्रतिशोधात्मक तरीके से ध्वस्त करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा-निर्देश तय किए हैं? इस फैसले के लिए उसने किन संवैधानिक प्रावधानों का सहारा लिया है? अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजे के बारे में उसने क्या कहा?

आरत्रिका भौमिक

अब तक कहानी:

इस बात पर जोर दिया कि किसी भी इमारत को गिराना असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को किसी व्यक्ति की संपत्ति का बिना पालन किए कानून की उचित प्रक्रिया के तहत, केवल अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्यों द्वारा आरोपी व्यक्तियों के घरों और निजी संपत्तियों को अवैध और प्रतिशोधात्मक तरीके से गिराने से रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं को छोड़कर, बिना स्पष्ट अनुमति के देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था।

'यह फैसला अधिकारियों को ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर करेगा'

क्या ध्वस्तीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है?

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में आरोपी व्यक्तियों के घरों और निजी संपत्तियों को बुलडोजर से गिराने की घटनाएं हुई हैं।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई या अनधिकृत निर्माण के बहाने तोड़फोड़ को उचित ठहराया गया।

बुलडोजर से तोड़फोड़ की शुरुआत कैसे हुई?
दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गई।
हरियाणा के नूंह में 2023 में दो धार्मिक समूहों के बीच झड़प के कारण हुई हिंसा स्थानीय प्रशासन द्वारा पड़ोस में बड़ी संख्या में घरों को ध्वस्त करने के साथ समाप्त हो गई।

इसी तरह, मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगों के कारण मुसलमानों के घरों और व्यवसायों को ध्वस्त कर दिया गया, जिन्हें "कथित दंगाई" माना गया।

हाउसिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2024 के अनुमान के अनुसार, और भूमि अधिकार नेटवर्क के अनुसार, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों ने 2022 और 2023 में 153,820 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 738,438 से अधिक व्यक्ति विस्थापित हो गए

अधिकारों की रक्षा: न्यायालय ने माना कि विध्वंस अभियान कथित अपराधियों के परिवारों पर एक तरह की 'सामूहिक सज़ा' थोपते हैं। फ़ाइल फ़ोटो

देश का। इसके अतिरिक्त, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि चार भाजपा शासित राज्यों और एक आप शासित राज्य के अधिकारियों ने अप्रैल से जून 2022 के बीच 128 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया – जो मुख्य रूप से मुसलमानों के थे।

अदालत का फैसला जवाब में सुनाया गया
कई राज्यों द्वारा किए गए तोड़फोड़ अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को यह आदेश दिया गया है। इन याचिकाओं को जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया गया है, जिसमें 2022 में जहांगीरपुरी में किए गए तोड़फोड़ को चुनौती दी गई है।
2 सितंबर को दो न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्यकारी अखिल भारतीय दिशानिर्देश तैयार करने की मंशा व्यक्त की थी।

अदालत ने क्या फैसला दिया?

शुरुआत में, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक लोकाचार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना, चाहे वह आरोपी हो या दोषी, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। इसने आगे रेखांकित किया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह की मनमानी "कानून के शासन" के मूल में आघात करती है और जनता के विश्वास को कम करती है। अभियुक्तों को पहले से दंडित करके न्यायपालिका की भूमिका को हड़पने वाली कार्यपालिका के खिलाफ चेतावनी देते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और यह तय नहीं कर सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए, उसकी आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित कर सकती है।

कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा।"

विशेष रूप से, न्यायाधीशों ने माना कि विध्वंस अभियान न केवल अपराध के कथित अपराधियों को लक्षित करते हैं, बल्कि उनके परिवारों पर "सामूहिक दंड" का एक रूप भी लगाते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने बताया कि यह अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। "यदि उसका जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता एक ही घर में रहते हैं या एक ही संपत्ति के सह-मालिक हैं, तो क्या उन्हें किसी कथित आरोपी व्यक्ति से संबंधित होने के आधार पर किसी अपराध में शामिल हुए बिना भी संपत्ति को ध्वस्त करके दंडित किया जा सकता है? जैसा कि सर्वविदित है, एक धर्मपरायण पिता का एक अड़ियल बेटा हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है," उन्होंने कहा। न्यायमूर्ति गवई ने यह भी कहा कि यदि किसी विशेष संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है, जबकि आसपास के अन्य समान ढांचे अछूते रहते हैं, तो यह राज्य की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे का एक मजबूत अनुमान लगाता है। बिना किसी संकोच के, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे "असली मकसद" आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना उन्हें दंडित करने का एक जानबूझकर प्रयास प्रतीत होता है।

कानून की अदालत में मुकदमा।

दिशानिर्देश क्या हैं?

न्यायालय ने संस्थागत जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि ये निर्देश न्यायालय द्वारा आदेशित अनधिकृत निर्माण या विध्वंस पर लागू नहीं होंगे। न्यायाधीशों ने निर्दिष्ट किया कि अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, अवमानना के आरोप और मौद्रिक दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा, इसने निर्देश दिया कि गलत तरीके से किए गए विध्वंस के लिए मुआवजा सीधे ऐसे दोषी अधिकारियों से वसूला जाए।

प्रभावित पक्षों को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने और ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए,
अदालत ने आदेश दिया है कि कोई भी विध्वंस अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए
15 दिन की पूर्व सूचना के बिना कार्यवाही न करें। ऐसा नोटिस घर के मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाना चाहिए और इसमें अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघनों का विवरण और ऐसी बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए आधार का विवरण प्रदान करना चाहिए।

इसके अलावा, नामित प्राधिकरण को मालिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया गया है। इस तरह की बैठक के मिनट्स को अंतिम आदेश के साथ विधिवत दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पक्षों की दलीलों का विवरण दिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अनधिकृत निर्माण समझौता योग्य है, या क्या पूरे ढांचे को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित प्राधिकरण को विध्वंस अभियान के साथ आगे बढ़ने से पहले कम से कम दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

न्यायाधीशों ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूरी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जाए। ध्वस्तीकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के नाम भी शामिल होने चाहिए।
रिपोर्ट नगर आयुक्त के समक्ष रखी जानी चाहिए तथा सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

निर्देश कितने प्रभावी हैं?

बेंगलुरू स्थित विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सह-संस्थापक और प्रमुख आलोक प्रसन्ना कुमार के अनुसार, इन दिशानिर्देशों में न्यायेतर विध्वंस अभियान की प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कानूनी शक्तियां मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, "यह फैसला अधिकारियों को संदेश देने के लिए घरों को ध्वस्त करने के राजनीतिक वर्ग के आदेशों का आँख मूंदकर पालन करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर करेगा।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराना एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा। हालाँकि, इस बात पर कुछ संदेह है कि दण्ड से मुक्ति की संस्कृति बनी रह सकती है, यह देखते हुए कि घृणास्पद भाषण और भीड़ द्वारा हत्या जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के न्यायालय के पिछले प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले हैं।

"इन उपायों की प्रभावशीलता
उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिला अदालतें और उच्च न्यायालय कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से इन निर्देशों को लागू करते हैं और उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
कुमार आगे कहते हैं।

ट्रम्प कार्यकुशलता विभाग क्यों स्थापित कर रहे हैं?

सरकारी दक्षता विभाग के उद्देश्य क्या हैं? ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान क्या अनुभव रहा है? अतीत में दक्षता अभियान से क्या हासिल हुआ है? सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया क्या है? क्या अमेरिकी सिविल सेवा में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है?

जॉन ज़ेवियर

अब तक कहानी:

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 12 नवम्बर चुनिंदा तकनीक अरबपति एलन मस्क और बायोटेक
हम उद्यमी विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व करने और "सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त विनियमनों को खत्म करने, बेकार के खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन" का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नियुक्त किया।

भले ही कांग्रेस को मंजूरी दी परिवर्तन, अंतिम निर्णय का अधिकार के कार्यालय प्रबंधन एवं बजट तथा अन्य संघीय एजेंसियां

आपके सामने क्या कार्य है?

श्री मस्क और श्री रामास्वामी को सरकार को बाहर से सलाह देने और मार्गदर्शन देने का काम सौंपा गया है। वे व्हाइट हाउस और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (ओएमबी) के साथ मिलकर "बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाएंगे और उद्यमशील दृष्टिकोण तैयार करेंगे।"

ऐसी सरकार जो पहले कभी नहीं देखी गई।'' दोनों ने साझा किया सरकारी सिविल सेवाओं में नौकरशाही में कटौती के बारे में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति के विचार।
अक्टूबर में ट्रंप की एक रैली में मस्क ने कहा था कि अमेरिकी सरकार के बजट में 6.5 ट्रिलियन डॉलर से कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती की जा सकती है। उन्होंने कम सिविल सेवा कर्मियों वाली एक कमज़ोर सरकार का भी आह्वान किया है। रिपब्लिकन नामांकन के लिए अपने अभियान के दौरान श्री रामास्वामी ने संघीय एजेंसियों को खत्म करने की योजना पेश की और खुफिया इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा।

आगे क्या बदलाव होने वाले हैं: चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने वादा किया था कि अगर वे चुने गए तो हर एक नियम के बदले 10 नियम खत्म कर देंगे। एपी

क्या ऐसा अभ्यास आवश्यक है?

सरकारी जवाबदेही कार्यालय (GAO) की 2024 के प्रदर्शन और जवाबदेही रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सरकार का दीर्घकालिक राजकोषीय भविष्य अस्थिर प्रतीत होता है। फरवरी में, कांग्रेस के निगरानीकर्ता ने बताया कि वित्त वर्ष 2023 के अंत में सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 97% था। इसके 2028 तक सकल घरेलू उत्पाद के 106% के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छूने का अनुमान है। जब तक कुछ कट्टरपंथी नीति लागू नहीं की जाती है, सार्वजनिक ऋण अगले तीन दशकों में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में दोगुनी से अधिक दर से बढ़ सकता है, जो संभवतः 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद का 200% हो सकता है, GAO का अनुमान है। गैर-पक्षपाती लेखा परीक्षा कार्यालय ने पहले सिफारिश की है कि कांग्रेस सरकार के राजकोषीय दृष्टिकोण को संबोधित करने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना विकसित करे

क्या ट्रम्प अपनी विनियामक बजट नीति को वापस लाएंगे?

चुनाव अभियान के दौरान, श्री ट्रम्प ने चुनाव जीतने पर हर एक नियम के लिए 10 नियम खत्म करने का वादा किया था। यह उनके पहले कार्यकाल के दौरान लागू की गई हर नई विनियमन नीति के लिए दो नियमों से एक बड़ी छलांग है। ऐसा करने के लिए, श्री ट्रम्प को कई मोर्चों पर काम करना होगा, जिसमें बिडेन प्रशासन द्वारा निरस्त किए गए अपने कार्यकारी आदेशों को बहाल करना, वर्तमान शासन द्वारा जारी किए गए अंतिम चरण के आदेशों को वापस लेने के लिए कांग्रेस की समीक्षा अधिनियम का उपयोग करना, OMB में नियामक निरीक्षण को ओवरहाल करना या इसे कांग्रेस को हस्तांतरित करना, और सरकार के दायरे और नियामक आउटपुट को मौलिक रूप से कम करने के लिए पूरी एजेंसियों को खत्म करना शामिल है।

क्या अतीत में भी दक्षता बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाए गए हैं?

फरवरी 1982 में, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी संघीय सरकार में अक्षमता और बर्बादी की पहचान करने और उसे कम करने के लिए व्यवसायिक नेताओं का एक समूह बनाया, जिसे आम तौर पर ग्रेस कमीशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दो साल बाद 2,500 सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट पेश की।

शुरुआत में, व्हाइट हाउस के कैबिनेट मामलों के कार्यालय को सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने का काम सौंपा गया था। फिर यह जिम्मेदारी OMB को सौंप दी गई।

अधिकांश प्रस्तावों को कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें लागू नहीं किया गया।
2010 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक द्विदलीय वित्तीय आयोग, जिसे सिम्पसन-बोल्स आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका मिशन देश के संघीय घाटे को संबोधित करना है। उनकी रिपोर्ट में घरेलू और सैन्य खर्च में पर्याप्त कटौती, संघीय गैसोलीन कर में वृद्धि, कम दरों के बदले लोकप्रिय कर छूट को समाप्त या कम करना, और सामाजिक सुरक्षा लाभों में समायोजन का प्रस्ताव दिया गया था।

हालांकि, कांग्रेस में सिफारिशें सफल नहीं हो पाईं क्योंकि इसका खाका विधायी निकाय को भेजने के लिए आवश्यक 14 वोट की सीमा को पार नहीं कर पाया। यह न केवल भव्य विचारों के महत्व को दर्शाता है बल्कि उन विचारों को साकार करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रदर्शन भी करता है।

DOGE क्या अंतर ला सकता है?

DOGE पहल महत्वाकांक्षी लग सकती है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव सीमित होने की संभावना है। आयोग केवल संघीय विनियामक शक्ति को कम करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। भले ही कांग्रेस ऐसे परिवर्तनों को मंजूरी दे दे, लेकिन अंतिम कार्यान्वयन OMB और अन्य संघीय एजेंसियों पर निर्भर करता है।

इसके अलावा, 4 जुलाई, 2026 तक समाप्त होने वाले आयोग के काम के परिणामस्वरूप संघीय एजेंसियों का तत्काल बंद होना या सरकारी कर्मचारियों के बीच नौकरी का नुकसान नहीं होगा। हालांकि, यह पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प की अनुसूची एफ पहल के साथ जोड़े जाने पर एक व्यापक भूमिका निभा सकता है, जो हजारों संघीय कर्मचारियों को पुनर्वर्गीकृत करने और राष्ट्रपति के लिए उन्हें बर्खास्त करना आसान बनाने का प्रयास करता है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह अमेरिकी सिविल सेवा में एक बड़े परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे राष्ट्रपति को पदों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण मिलेगा। समर्थकों का तर्क है कि नौकरशाही प्रतिरोध की कथित "गहरी स्थिति" को संबोधित करने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह गैर-पक्षपाती नींव को नष्ट कर सकता है

सिविल सेवा।
DOGE को अप्रभावी आयोग बनने से बचने के लिए, उसे न्यू जर्सी के रेड टेप रिव्यू कमीशन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस आयोग ने प्रभावशाली रिपोर्ट तैयार करके ठोस नतीजे हासिल किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्यधिक विनियमन ने आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है।

यद्यपि बाद में राजनीतिक विरोध के कारण इसे भंग कर दिया गया, लेकिन इसके प्रयासों से यह प्रदर्शित हुआ कि नियामक सुधार आयोग कुछ हासिल कर सकते हैं।
जब उनका काम सहयोगात्मक होता है तो परिणाम मिलते हैं
व्यापक रूप से समर्थित.

निःशुल्क व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें https://whatsapp.com/channel/0029Van2VRb6RGJOKH6oBd0F
निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़ें https://t.me/+Bu7sen QdhlODg1

Machine Translated by Google

दूसरी पारी के अंश

ट्रम्प 2.0 दो

महाभियोग, चार आपराधिक अभियोग, एक धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि और 83.3 मिलियन डॉलर के यौन उत्पीड़न के मामले में फैसले के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प मतदान पैटर्न में 'लाल बदलाव' के दम पर व्हाइट हाउस में पहुंच गए हैं, जिसने लगभग हर राज्य को अपने पक्ष में प्रभावित किया है।

नारायण लक्ष्मण

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार हैं

हम हाउस में चार साल का कार्यकाल, जिसमें घरेलू और विदेश नीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और अमेरिकी सार्वजनिक संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला के कामकाज में बदलाव आएगा। तथ्य यह है कि उन्होंने 2024 के चुनाव में देश के सात स्विंग राज्यों में जीत हासिल करने, लोकप्रिय वोट और इलेक्टोरल कॉलेज दोनों जीतने और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद की दौड़ को समाप्त करने के लिए, पोलस्टर्स और अमेरिकी मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा भविष्यवाणी की गई बाधाओं को चुनौती दी, जो पिछले प्रशासन के साथ मतदाताओं के मोहभंग को दर्शाता है, जिसके कारणों पर अभी भी व्यापक रूप से बहस हो रही है।

फिर भी, यह इस बारे में भी कुछ कहता है डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ लोगों के लिए रक्षक हैं, दूसरों के लिए रहस्य हैं और कई लोगों के लिए राजनीति के घृणित ब्रांड का प्रतीक हैं, जिनमें शायद सुश्री हैरिस को वोट देने वाले 73 मिलियन लोगों में से अधिकांश शामिल हैं। यह समझने के लिए कि अगले चार साल अमेरिका और दुनिया के लिए क्या संकेत देते हैं, सभी पक्षों पर हथियारबंद प्रचार के धुंधलेपन को देखना और श्री ट्रम्प के इरादों को स्पष्ट करना शिक्षाप्रद है।

ट्रम्प वास्तव में इसके पक्ष में हैं।

श्री ट्रम्प ने कई भूमिकाएँ निभाई हैं
उनके 78 वर्षों के लम्बे कार्यकाल, तथा ओवल ऑफिस में प्रवेश करने वाले सबसे वृद्ध राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के साथ ही, जिस निपुणता के साथ उन्होंने अपने करियर के विभिन्न 'अवतारों' को पार किया है - एक रियल एस्टेट साम्राज्य के उत्तराधिकारी से लेकर एक पंथ टीवी शो व्यक्तित्व और फिर एक विशाल समूह के प्रमुख से लेकर अंततः दो-कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बनने तक - यह उनकी मूल प्रवृत्ति की गहन परिवर्तनशीलता, तथा उनके पेशेवर मिशन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण - जिसे उनके आलोचक मूल्य कहेंगे - के अभाव को दर्शाता है।

1946 में क्वींस, न्यूयॉर्क में जन्मे,
एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे के रूप में, श्री ट्रम्प ने न्यूयॉर्क मिलिट्री अकादमी में अध्ययन किया और

व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में वाणिज्य। जब उन्होंने 1971 में अपने पिता, फ्रेड ट्रम्प की कंपनी का नियंत्रण संभाला, तो उन्होंने इसका नाम ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन रखा, जो एक कॉर्पोरेट समूह था जो वाणिज्यिक और आवासीय भवनों, रिसॉर्ट्स, होटलों, गोल्फ कोर्स और कैसीनो सहित कई क्षेत्रों में काम करता था।

उनकी कई पुस्तकों में से एक थी
1987 में प्रकाशित उनकी पुस्तक आर्ट ऑफ द डील से उनके इस विश्वास के बारे में शुरुआती संकेत मिलते हैं कि सौदेबाजी ही सफलता का सही मापदंड है और इसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन है - यह एक ऐसा प्रतिमान है जो, उदाहरण के लिए, अमेरिकी विदेश विभाग में लंबे समय से चली आ रही इस मान्यता के विपरीत है कि सफल कूटनीति के लिए "धैर्यपूर्वक गठबंधन और साझेदारी का निर्माण और उसे गहरा करना...क्षेत्रीय संस्थानों में रचनात्मक भूमिका निभाना और उच्चतम स्तर पर क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों में समय लगाना" आवश्यक है।

एक बार फिर इस कदम से यह बात प्रतिबिंबित हुई श्री ट्रम्प की नौटंकी और नाटकीयता के प्रति निष्ठा को देखते हुए, जिसके तहत उनके सभी कर्मचारियों की निष्ठा का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता था, 2004 में उन्होंने हिट रियलिटी टेलीविजन शो द अप्रेन्टिस का शुभारंभ किया।

"आप बर्खास्त हैं" के उनके अब प्रसिद्ध बर्खास्तगी लाइन के वायरल होने के साथ, इस शो ने मनोरंजन टेलीविजन की दुनिया में श्री ट्रम्प की साख को मजबूत किया, भले ही इसने उनके व्यावसायिक नैतिकता के बारे में सवाल उठाए क्योंकि वे ट्रम्प संगठन में व्यापक रूप से लागू थे।

विशेषकर 2015 में उनके प्रथम राष्ट्रपति अभियान के समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि श्री ट्रम्प से अधिक किसी भी प्रमुख अमेरिकी कंपनी ने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन नहीं किया था।

पिछले 30 वर्षों में ट्रम्प के अटलांटिक सिटी कैसीनो साम्राज्य के बारे में चार अलग-अलग फाइलिंग।
इनमें से प्रत्येक मामले में, निहित कॉर्पोरेट पुनर्गठन ने श्री.

ट्रम्प की कम्पनियों को बचाए रखने के लिए, तथा बैंकों, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं पर बकाया अधारणीय ऋण से छुटकारा पाने के लिए यह कदम उठाया गया।

२०१६ में आश्चर्यजनक जीत वॉल स्ट्रीट की धोखाधड़ी में डूबे उनके रिकॉर्ड और सिस्टम के उच्चतम सोपानों पर सत्ता-दलालों के साथ निकटता के साथ, यह कई लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात थी कि २०१६ के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अभियान में श्री ट्रम्प उल्का ऊंचाइयों तक पहुंचे, जबकि इस दौरान उन्होंने खुद को जनता का आदमी, रस्ट बेल्ट में नीली कॉलर नौकरियों के उद्धारकर्ता और एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में विपणन किया।

आवारागर्द बहुत दूर से
वाशिंगटन के कुलीन नीति-निर्धारक हलकों में। यहां तक कि उनके अभियान का नारा, 'अमेरिका को फिर से महान बनाओ', भी व्यापक रूप से लोगों के लाभ के लिए प्रचारित किया गया था।

राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रमुख सरकारी पदों के लिए चुने गए व्यक्ति: (घड़ी की दिशा में) रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर (स्वास्थ्य विभाग), मैट गेट्ज़ (न्याय विभाग), मार्को रुबियो (विदेश विभाग), तुलसी गब्बार्ड (राष्ट्रीय खुफिया) और माइक वाल्ट्ज़ (राष्ट्रीय सुरक्षा)। चित्रण: आर. राजेश

ट्रम्प अभियान - रिपोर्ट बताती है कि एक साल में, 40 डॉलर प्रति पीस की दर से दस लाख से ज़्यादा टोपियाँ बेची गईं। हालाँकि, 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर, प्रमुख अख़बारों ने 90% संभावना जताई थी कि उनकी प्रतिद्वंद्वी, डेमोक्रेट और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद जीत जाएँगी - अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया द्वारा यह पहचानने में विफलता कि श्री ट्रम्प वास्तव में एक वैश्विक स्वदेशी-लोकलुभावन आंदोलन के शीर्ष पर थे, जो पश्चिम में उदार आर्थिक आम सहमति को उलटने और धीरे-धीरे नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नष्ट करके अपने व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग प्रतिमान को नष्ट करने के लिए तैयार था।

हालांकि वह लोकप्रिय वोट में सुश्री क्लिंटन से हार गए, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज ने श्री ट्रम्प को बचा लिया और उन्हें अपने पहले कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में पहुंचा दिया, चार साल ऐसे रहे जिनमें कई नीतियां लागू की गईं।

प्राप्त ज्ञान का चेहरा

आव्रजन, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और विदेशी संबंध। जबकि 45वें कमांडर इन चीफ के रूप में उनका भौंहें चढ़ाने वाला रिकॉर्ड सर्वविदित है, उनके सबसे विवादास्पद नीतिगत परिणामों में कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया का कुप्रबंधन शामिल था जिसके कारण "हजारों अनावश्यक मौतें" हुईं; अल्पसंख्यक जनसांख्यिकी के प्रति उनकी व्यापक शत्रुता जिसका उदाहरण 'मुस्लिम प्रतिबंध' और अनिर्दिष्ट प्रवासियों के खिलाफ किए गए पारिवारिक अलगाव हैं; विदेशी एल्युमीनियम, स्टील और अन्य उत्पादों पर टैरिफ सहित संरक्षणवादी नीतियों के कारण व्यापार युद्ध शुरू करना; राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मांगने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर दबाव डालने का उनका प्रयास; और, सबसे अधिक गंभीर रूप से, 2021 की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव में श्री बिडेन से उनकी प्रमाणित हार को चुनौती देते हुए यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने और तोड़फोड़ करने वाली हिंसक भीड़ को प्रोत्साहित करने में उनकी भूमिका।

कुछ महीने पहले.

फिर भी, दो महाभियोग, चार आपराधिक अभियोग, एक धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि और 83.3 मिलियन डॉलर के यौन उत्पीड़न के फैसले के बाद, श्री ट्रम्प ने न केवल अमेरिकी मतदाताओं की नजरों में मुक्ति हासिल की है, बल्कि मतदान पैटर्न में "लाल बदलाव" के दम पर व्हाइट हाउस में घर वापसी की है, जिसने लगभग हर जगह प्रभाव डाला है।

लाल और नीला राज्य उसके पक्ष में है।

इस बार, चुनाव-पश्चात विश्लेषणों से पता चलता है कि, निर्णायक राज्यों में स्वतंत्र और अनिर्णीत मतदाता आर्थिक नीति के प्रमुख प्रश्नों पर भी बहस नहीं कर रहे थे, जैसे कि बिडेन व्हाइट हाउस का वास्तविक प्रदर्शन रिकॉर्ड।

इसके बजाय, यह "मीडिया में उपस्थिति" थी, जैसे कि श्री ट्रम्प और जो रोगन, एक लोकप्रिय रूढ़िवादी टिप्पणीकार के बीच तीन घंटे की पॉडकास्ट बातचीत, जिसने श्री ट्रम्प के पक्ष में मूड को बदल दिया, जितना कि श्री ट्रम्प की दृष्टि

अब जबकि ट्रम्प को संघीय सरकार के तीनों पक्षों का समर्थन प्राप्त है, तो उनके पास अमेरिकी नीति और संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता है।

उन्होंने अपने अभियान मंच से अमेरिकियों को अनियंत्रित आव्रजन के खतरों के बारे में चेतावनी दी।

अब जबकि श्री ट्रम्प को संघीय सरकार के त्रिदेवों - व्हाइट हाउस, प्रतिनिधि सभा और रिपब्लिकन पार्टी द्वारा नियंत्रित सीनेट - का समर्थन प्राप्त है, तथा सर्वोच्च न्यायालय में 6-3 बहुमत से रूढ़िवादी न्यायाधीशों का समर्थन प्राप्त है, तो उनके पास अमेरिकी नीति और संस्थाओं को नया आकार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो मंत्रिमंडल चुना है, उसने चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत निष्ठा को प्राथमिकता दी है।

इन सबसे ऊपर - उसका पूर्व

निक्की हेली सहित सहयोगी से आलोचक बने लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, और उनकी जगह रूढ़िवादियों के एक नए समूह को चुना गया है, जबकि उन्हें व्हाइट हाउस में कोई पूर्व अनुभव नहीं है।

इनमें उल्लेखनीय हैं - व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सूजी विल्स, विदेश मंत्री के रूप में मार्को रुबियो, अटॉर्नी जनरल के रूप में मैट गेट्ज़, अटॉर्नी जनरल के रूप में रॉबर्ट एफ.
केनेडी जूनियर को स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव, तुलसी गब्बार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक, टॉम होमन को "सीमा ज़ार", पीट हेगसेथ को रक्षा सचिव, ली ज़ेल्डिन को ईपीए प्रशासक, माइक हुकाबी को इजरायल में अमेरिकी राजदूत, तथा एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।

जबकि सुश्री विल्स के पास एक के रूप में अनुभव है फ्लोरिडा में राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री.
रुबियो, जो इसी राज्य से आते हैं, चीन के प्रति कट्टर माने जाते हैं।

गेट्ज़ पर एक बार नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी के लिए जांच चल रही थी और अब वह जेल में बंद हैं।
MAGA विधायक के रूप में जाने जाते हैं

हाउस ने श्री ट्रम्प का पुरजोर बचाव किया।
ट्रम्प और उनकी नीतियों पर कई मौकों पर सदन में चर्चा हुई है। श्री कैनेडी को "कट्टर वैक्सीन विरोधी और गलत सूचना फैलाने वाले व्यक्ति" के रूप में वर्णित किया गया है

फेरीवाला [और] आखिरी बार जब उसने राज्य के चिकित्सा मामलों में हस्तक्षेप किया (समोआ), 83
बच्चे खसरे से मर गए।" सुश्री गबार्ड

उन्हें खुफिया जानकारी का कोई अनुभव नहीं है और वे रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले समर्थन के सख्त खिलाफ हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि रूस और सीरियाई नेता बशर अल-असद के साथ 2017 में हुई उनकी मुलाकात पर उनके "विचारों ने विवाद खड़ा कर दिया है।"

श्री होमन कार्यवाहक निदेशक थे
पहले ट्रम्प प्रशासन के दौरान अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के प्रमुख और श्री ट्रम्प ने कहा है कि वह "सभी के प्रभारी होंगे

अवैध विदेशियों को उनके मूल देश वापस भेजा जाना चाहिए।"
जबकि श्री.
हेगसेथ के पास एक अनुभवी सैन्यकर्मी के रूप में अनुभव है, जो इराक, अफगानिस्तान और ग्वांतानामो बे में तैनात रह चुके हैं।

तब से वह रूढ़िवादी समाचार चैनल पर प्रसारित होने वाले शो "फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड्स" के सह-होस्ट हैं। श्री ज़ेल्डिन न्यूयॉर्क के पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं, जिनके बारे में श्री ट्रम्प ने कहा

"निष्पक्ष और त्वरित सुनिश्चित करेगा

विनियमन-विरोधी निर्णय इस तरह से लिए जाएंगे कि अमेरिकी व्यवसायों की शक्ति उन्मुक्त हो जाए, साथ ही उच्चतम स्तर बनाए रखा जाए।

पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना"। श्री.

हकाबी एक टीवी व्यक्तित्व भी हैं - उन्होंने फॉक्स न्यूज पर एक शो और एक रेडियो कार्यक्रम की मेजबानी भी की है, हालांकि

उनके पास 1996 से 2007 तक अर्कांसस के गवर्नर के रूप में राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव भी है।

रामास्वामी - भले ही यह विडंबनापूर्ण लगे कि सरकारी अपव्यय और अतिरिक्तता को कम करने के लिए बनाए गए विभाग के दो प्रमुख हैं - निजी क्षेत्र से हैं, लेकिन 2024 के अभियान के दौरान श्री ट्रम्प के लिए दृढ़ता से बोलने के लिए उल्लेखनीय रहे हैं। इन सभी संभावित नामांकितों के बीच - यह मानते हुए कि उन्हें सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है, अभी भी एक लंबा

श्रीमान के कई मामलों में आदेश।

ट्रम्प के नामांकित व्यक्तियों के लिए - माना जा रहा है कि एजेंडा ट्रम्प के MAGA विजन को चार वर्षों में यथासंभव पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना होगा।

अधूरा एजेंडा श्री ट्रम्प के अभियान के नारे, "वादे किए, वादे निभाए", की सूची में सबसे ऊपर संभवतः अनिर्दिष्ट श्रमिकों का बड़े पैमाने पर निर्वासन करने का प्रयास होगा, जिनकी संख्या अंतिम गणना में 11 मिलियन है, एक आंकड़ा जो 2005 से कमोबेश स्थिर रहा है।
हालांकि, कई राज्यों में, प्रमुख शहरी केंद्र "अभयारण्य शहरों" के रूप में उभरे हैं - जिन्होंने ऐसे कानून पारित किए हैं जो आईसीई के साथ स्थानीय कानून प्रवर्तन सहयोग को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की हिरासत और निर्वासन को अंजाम देना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

ऐसे पैमाने पर गतिविधियाँ जो मायने रख सकती हैं।

फिर लॉजिस्टिक और आर्थिक चुनौतियाँ हैं - गैर-पक्षपाती अमेरिकी आव्रजन परिषद का अनुमान है कि इस तरह के प्रस्ताव से करदाताओं को संभावित रूप से $300 बिलियन से अधिक का नुकसान हो सकता है। हालाँकि, श्री ट्रम्प संभवतः कुछ ऐसे कदम उठाएँगे जिससे उन्हें अपने प्रशासन के इर्द-गिर्द रहने वाले आव्रजन समर्थकों से कुछ राजनीतिक पूंजी मिल जाएगी। आखिरकार, पिछले ट्रम्प प्रशासन के तहत, लगभग 1.5 मिलियन लोगों को निर्वासित किया गया था, और बिडेन

प्रशासन उस हद तक करीब पहुंच गया

ये दोनों ही आंकड़े उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा के दो कार्यकालों में लगभग 30 लाख लोगों को निर्वासित करने के रिकार्ड के सामने बौने थे।

दूसरा, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की संभावना है, कम से कम 2017 में श्री ट्रम्प द्वारा तथाकथित टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट के माध्यम से शुरू की गई लैप्सिंग कट्स का नवीनीकरण। समस्या यह है कि जबकि नीति ने अधिकांश लोगों के लिए करों में कमी की, लेकिन अमीरों को असंगत रूप से लाभ पहुँचाने के लिए इसकी आलोचना की गई: गैर-पक्षपाती सेंटर ऑन बजट और

पॉलिसीज़ प्रायोरिटीज़ ने कहा कि इस कानून के तहत, शीर्ष 1% आय वाले परिवारों को 2025 में $60,000 से अधिक की औसत कर कटौती मिलेगी, जबकि निचले 60% परिवारों के लिए औसत कर कटौती $500 से कम होगी। इसके अलावा, सेंटर ऑन बजट एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज़ (CBPP) ने कहा कि ट्रम्प कर कटौती "महंगी थी और इसने अमेरिकी राजस्व आधार को नष्ट कर दिया... और वादा किए गए आर्थिक लाभ देने में विफल रही।"

तीसरा, विदेश नीति के क्षेत्र में, वैश्विक आर्थिक मंच पर अनिश्चित अनुपात का प्रतिशोध-आधारित व्यापार युद्ध लगभग निश्चित है, क्योंकि श्री ट्रम्प ने सभी 3 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी माल आयात पर 10-20% क्रॉस-कटिंग टैरिफ और चीनी माल पर विशेष, दंडात्मक 60% टैरिफ का वादा किया है। उस अस्थिर करने वाली कार्रवाई से परे, और पेरिस जलवायु समझौते, ईरान परमाणु समझौते, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप, यूनेस्को, यूएनएचआरसी, नाफ्टा (उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता) और अधिक से अमेरिका के बाहर निकलने की पहली ट्रम्प प्रशासन की योजना के आधार पर, यह काफी संभावना है कि वैश्विक, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय जुड़ावों से अमेरिका की आंतरिक वापसी, तेजी से जारी रहेगी। इसका गाजा और यूक्रेन में युद्धों, पश्चिम एशिया और दक्षिण चीन सागर में व्यापक संघर्षों के अलावा असंख्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जो शायद अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों के लिए नुकसानदेह और चिढ़ का कारण बन सकती हैं।

दुनिया भर में.

ट्रम्पवाद का पर्दाफाश श्री ट्रम्प के चार और वर्षों के बाद, अमेरिका और वास्तव में दुनिया एक बहुत ही अलग जगह हो सकती है। उनका दूसरा कार्यकाल MAGA आंदोलन के चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त होता है। 2016 में ट्रम्पवाद के मूल सिद्धांतों के एक मार्मिक राजनीतिक दावे के रूप में जो शुरू हुआ था - वास्तविक आर्थिक निराशा और श्वेत अमेरिका की सामाजिक अक्षमता पर चिंताओं का एक जटिल मिश्रण जिसमें नस्लवाद, स्त्री-द्वेष और कट्टरता में निहित निम्न भावनाओं की बेबाक अभिव्यक्ति है - अब मुक्त प्रवाह प्राप्त करेगा और हर सार्वजनिक में रिस जाएगा

अमेरिका की संस्था और परिवर्तन

देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य का मूल। इस आंदोलन के शीर्ष पर श्री ट्रम्प का समय एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जिन ताकतों को मुक्त किया है, वे उस समय से बहुत आगे तक जीवित रह सकती हैं।

सार

ट्रम्प के अभियान नारे की सूची में सबसे ऊपर है, "वादे

"बनाया, वादे निभाए", संभवतः गैर-दस्तावेज श्रमिकों के बड़े पैमाने पर निर्वासन को अंजाम देने का एक प्रयास होगा, जिनकी संख्या अंतिम गणना के अनुसार 11 मिलियन है

दूसरा, कॉर्पोरेट कर में कटौती की संभावना है, कम से कम 2017 में ट्रम्प द्वारा तथाकथित कर कटौती और रोजगार अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई कटौती का नवीनीकरण

वैश्विक आर्थिक मंच पर प्रतिशोध आधारित व्यापार युद्ध लगभग निश्चित है, क्योंकि ट्रम्प ने सभी 3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी माल के आयात पर 10-20% क्रॉस-कटिंग टैरिफ और चीनी वस्तुओं पर दंडात्मक 60% टैरिफ लगाने का वादा किया है।

अमेरिका की आंतरिक वापसी

वैश्विक, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर भागीदारी जारी रहेगी, जिसका अमेरिका में युद्धों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

गाजा और यूक्रेन, पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष और
दक्षिण चीन सागर

नि:शुल्क व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें https://whatsapp.com/channel/0029Van2VRb6RGJOKH6oBd0F
नि:शुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़ें https://t.me/+Bu7sen QdhIODg1

Machine Translated by Google

The Sunday Statesman

जिसके साथ शामिल है
द इंग्लिशमैन~ की स्थापना 1821 में हुई

लीन सरकार

प्रस्तावित सरकारी दक्षता विभाग (डोगे) संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक नई सलाहकार संस्था, जो दो प्रमुख हस्तियों द्वारा संचालित है, जो अपने साहसिक लागत-कटौती दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अमेरिका की विशाल संघीय नौकरशाही से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। उद्यमी एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में, राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प का लक्ष्य संघीय खर्च को सुव्यवस्थित करना, विनियमनों को कम करना और राष्ट्र की बजटीय प्राथमिकताओं को नया आकार देना है। जबकि यह पहल परिवर्तनकारी लगती है, एक नज़दीकी नज़र दोनों आशाजनक पहलुओं और संभावित नुकसानों को प्रकट करती है। एक ओर, श्री मस्क और श्री रामास्वामी निजी क्षेत्र से अनूठी अंतर्दृष्टि लाते हैं, जहाँ लागत में कटौती, नवाचार और दक्षता सफलता के लिए मौलिक हैं। श्री मस्क ने, विशेष रूप से, अंतरिक्ष यात्रा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक ~ पूरे उद्योगों को फिर से परिभाषित किया है, जो कि जड़ जमाए हुए मानदंडों पर सवाल उठाकर और उन्हें बाधित करके हैं। परिचालन दक्षता के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके द्वारा अधिग्रहित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के विवादास्पद पुनर्गठन में भी स्पष्ट था, जहाँ उन्होंने लागत में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी की। श्री रामास्वामी, जो छोटी सरकार की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, ने भी संघीय एजेंसियों के महत्वपूर्ण हिस्सों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अनावश्यक हैं। निजी क्षेत्र के दोनों के अनुभव अक्सर बोझिल सरकारी ढांचे में नए विचार ला सकते हैं, जो दशकों से अक्षमताओं से ग्रस्त है।

हालांकि, संघीय व्यय को कम करना किसी तकनीकी कंपनी में लागत कम करने से कहीं अधिक जटिल है। संघीय एजेंसियाँ आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए मौजूद हैं ~ राष्ट्रीय रक्षा से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा तक ~ जहाँ कर्मचारियों को कम करना या विभागों को समाप्त करना गंभीर परिणाम हो सकता है। सरकारी खर्च में सुधार के पिछले प्रयासों ने बार-बार दिखाया है कि सेवा की गुणवत्ता को कम किए बिना नौकरशाही में कटौती करना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए, श्री मस्क का $2 ट्रिलियन प्रति वर्ष की कटौती का लक्ष्य, उन कार्यक्रमों में अभूतपूर्व कटौती की आवश्यकता होगी जिन पर लाखों अमेरिकी निर्भर हैं। आलोचकों का तर्क है कि अगर इस तरह की कटौती को खराब तरीके से लागू किया जाता है, तो यह सामाजिक सुरक्षा जाल को कमजोर कर सकता है और संघीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

एक और चुनौती डोगे की प्रकृति में निहित है।
चूंकि इसे आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए यह केवल सलाहकार की भूमिका में कार्य करेगा तथा इसके पास सिफारिशों को लागू करने का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि यह एक गैर-विधायी निकाय है, यह किसी भी प्रस्तावित बजटीय कटौती या संरचनात्मक परिवर्तनों पर कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकता है। यह सीमित प्रभाव इस बारे में प्रश्न उठाता है कि संघीय व्यय प्रथाओं को नया रूप देने में इसका कितना वास्तविक प्रभाव हो सकता है। जबकि डोगे वास्तव में बेकार के खर्चों की पहचान कर सकता है, इसके प्रस्तावों को कार्रवाई में बदलना एक कठिन लड़ाई हो सकती है। डोगे पहल को मैनहट्टन परियोजना से जोड़ने का श्री ट्रम्प का निर्णय ~ ऐतिहासिक रूप से उच्च-दांव वाले राष्ट्रीय परिवर्तन का प्रतीक ~ उनके द्वारा चुने गए सलाहकारों में उनके विश्वास को दर्शाता है। लेकिन नौकरशाही बाधाओं और संघीय सुधार के लिए आवश्यक जटिल सार्वजनिक-नीति परिदृश्य को देखते हुए, इस तरह के महत्वपूर्ण युद्धकालीन प्रयास के साथ समानताएं खींचना व्यावहारिक से अधिक प्रतीकात्मक हो सकता है। अंत में, जबकि डोगे अक्षमताओं को उजागर करने और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने में सफल हो सकता है, ठोस सुधार का मार्ग चुनौतियों से भरा है। एक अधिक दक्ष, अधिक कुशल सरकार की परिकल्पना महत्वाकांक्षी है और यकीनन इसमें देरी हो रही है, लेकिन आवश्यक सेवाओं को खतरे में डालने से बचने के लिए एक सूक्ष्म, सूचित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

शहरी-ग्रामीण विभाजन

झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य जटिलता को दर्शाता है

[illegible] शहरीकरण, ग्रामीण [illegible] और बढ़ते सांप्रदायिक तनावों से जूझ रहा है।

शहरी-ग्रामीण विभाजन चुनावों की एक परिभाषित विशेषता बन गया है, जो इसके लोगों की विपरीत प्राथमिकताओं और राजनीतिक आख्यानों की अलग-अलग प्रभावशीलता को दर्शाता है। शहरी क्षेत्रों में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शहरीकरण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके एक गढ़ बनाने में कामयाब रही है। ये घनी आबादी वाले क्षेत्र, अनियंत्रित रियल एस्टेट विकास, विस्तारित पेरी-अर्बन बस्तियों और खराब नागरिक नियोजन की विशेषता रखते हैं, जो भाजपा के आधुनिकीकरण के संदेश के लिए उपजाऊ जमीन बन गए हैं। बेहतर सड़कें, 24 घंटे बिजली और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के वादे शहरी मतदाताओं के साथ गूंजते हैं, जो अक्सर ग्रामीण झारखंड की व्यापक चिंताओं, जैसे सामाजिक समानता, भूमि अधिकार और जबरन पलायन से अलग होते हैं। हालांकि, झारखंड में शहरीकरण महत्वपूर्ण समझौतों के साथ आया है।

कृषि भूमि का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए तेजी से रूपांतरण आवश्यक शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से आगे निकल गया है। कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था अपर्याप्त है। फिर भी, भाजपा की पहुंच और शहरी विमर्श पर हावी होने की क्षमता अक्सर इन कमियों को ढक देती है, जिससे अन्य राजनीतिक खिलाड़ियों को गति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

इसके विपरीत, ग्रामीण झारखंड कल्याण-संचालित राजनीति का गढ़ बना हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), जिसका ग्रामीण और आदिवासी समुदायों से गहरा संबंध है, ने गरीबी और असमानता को दूर करने वाली योजनाओं पर अपना शासन केंद्रित किया है। महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद लाभ और बुजुर्गों के लिए पेंशन जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण जीवन पर ठोस प्रभाव डाला है। ये पहल ग्रामीण मतदाताओं की पारंपरिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, जो शहरी विकास के वादों की तुलना में सामाजिक न्याय और आर्थिक राहत को महत्व देते हैं।

जेएमएम और उसके सहयोगियों के लिए असली चुनौती उनके ग्रामीण गढ़ और तेजी से प्रभावशाली शहरी मतदाता आधार के बीच की खाई को पाटना है। शहरी मतदाता, भाजपा के संदेश और आर्थिक विकास पर इसके फोकस से प्रभावित होकर, अक्सर कल्याणकारी उपायों को अपनी उभरती आकांक्षाओं के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। इसके अलावा, धार्मिक आधार पर मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए भाजपा द्वारा सांप्रदायिक आख्यानों के उपयोग ने विभाजन को बढ़ा दिया है, खासकर अल्पसंख्यक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में। झारखंड के शहरी इलाके सांप्रदायिक तनाव के केंद्र के रूप में उभरे हैं, जहाँ चुनाव अक्सर शासन के बजाय पहचान पर जनमत संग्रह बन जाते हैं।

यह ध्रुवीकरण समावेशी विकास की संभावना को कमजोर करता है और धर्मनिरपेक्ष दलों को नुकसान पहुंचाता है।
इन पार्टियों की ओर से निरंतर संपर्क और सुसंगत संदेश का अभाव शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के प्रभुत्व को और मजबूत करता है। इस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, झामुमो और उसके सहयोगियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से बदलना होगा। सांप्रदायिक बयानबाजी का मुकाबला करने के लिए निरंतर प्रयासों के साथ शहरी बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए न केवल नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है, बल्कि एक ऐसी कहानी की भी आवश्यकता है जो राज्य की विविध आबादी को एकजुट करे। झारखंड में चुनाव इन रणनीतियों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा।

क्या कल्याण-संचालित राजनीति अपना आकर्षण बढ़ा पाएगी या शहर-केंद्रित आख्यान अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, यह राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है।

निभाने के वादे

सरकारें अल्पकालिक होती हैं और अल्पकालिक निर्णय लेती हैं, क्योंकि दीर्घकालिक हमेशा उलझन भरा और भ्रमित करने वाला होता है। समावेशी विकास का मतलब अब केवल उन लोगों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित करना है, जिनके बारे में राजनेताओं को लगता है कि वे उनके लिए वोट करेंगे। लेकिन जोखिम यह है कि किसी समय, यहां तक कि मतदाता जो अब समान रूप से गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, वे भी कमजोर आर्थिक विकास और खराब सेवाओं से तंग आ जाएंगे, जिससे राजनेताओं को कठिन विकल्प चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा।

चुनाव में वादे मायने रखते हैं

मतदाताओं में तर्क की कमी है। जैसा कि चुनाव इतिहास से पता चलता है, मुफ्त की चीजों से वोट मिलते हैं। अब तक, यह हताश विपक्ष के लिए चुनावी सफलता का एक समय-परीक्षणित तरीका था। ऐसा लगता है कि अब भाजपा को भी इसकी जरूरत है -

भाजपा ने रणनीति को त्याग दिया और मुफ्तखोरी के खेल में शामिल हो गई, और अंततः मतदाताओं के सामने केवल विकास के मंत्र का प्रयोग करने के अपने पुराने ढोंग को त्याग दिया।

ओडिशा में नव-स्थापित भाजपा सरकार ने घोषणा की है -
सुभद्रा नामक एक भव्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 21 से 60 वर्ष की आयु की एक करोड़ महिलाओं को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि 50,000 रुपये है, जो चालू वित्त वर्ष से शुरू होकर, अर्ध-वार्षिक किश्तों में पांच साल की अवधि में समान रूप से देय है।

यह लोकलुभावन योजना, जो पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीभंडार जैसे अन्य राज्यों में लागू इसी प्रकार की योजनाओं से मूलतः भिन्न नहीं है, करदाताओं को भारी नुकसान पहुंचाएगी।

55,825 करोड़ रुपये की भारी राशि। अनुमान है कि इससे कई गुना अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे ओडिशा को संभावित रूप से 2.5 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।

अगले पांच वर्षों में शा की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आएगा। गतिशील रूप से बदलते सामाजिक-आर्थिक माहौल में इस गणना के पीछे की धारणाएं अज्ञात और रहस्यमय हैं -

हालांकि, यह निश्चित रूप से ओडिशा के भविष्य के बजट के लिए एक बड़ा छेद होगा, क्योंकि वित्त वर्ष 23 में इसने 15,201 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्ज किया था।

संभवतः, यह गरीब राज्य को गहरे घाटे में धकेल देगा और इसकी आय को कम कर देगा।
खनिज विकास दर में गिरावट -
वित्त वर्ष 23 में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

ओडिशा लोकलुभावनवाद के झटके से पीड़ित होने वाला पहला राज्य नहीं होगा; यह कई अन्य राज्यों - पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि द्वारा स्थापित शानदार उदाहरणों का अनुसरण करेगा। लेकिन इस लेख में हम कर्नाटक की जांच करेंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चुनावी वादे करने के लिए फटकार लगाई है, जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकते।

यूपीए ने 2023 के चुनाव में पांच मुफ्त वादे करने के बाद कर्नाटक में 224 में से 135 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की थी: गृह लक्ष्मी (प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये), गृह ज्योति (प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली), शक्ति (महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा), अन्ना भार्गव (महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा), गृह लक्ष्मी (प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये मुफ्त बिजली), गृह ज्योति (प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली), शक्ति (महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा), अन्ना भार्गव (महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा), गृह लक्ष्मी (प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये मुफ्त बिजली ...

ग्या (हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल) और युवानिधि (बेरोजगार शिक्षित युवाओं को 1,500/3,000 रुपये प्रति माह) और पिछले बजट से ही इन योजनाओं के लिए 39,825 रुपये अलग से निर्धारित करके इन्हें लागू किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा हो गया

१३,९५१ करोड़ का कर्ज वापस ले लिया गया।
वित्त वर्ष 2023 में 13,496 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष।

वित्त वर्ष 2025 के बजट में इन योजनाओं के लिए 52000 करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले 39,565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे राजस्व घाटा लगभग दोगुना होकर 27,353 करोड़ रुपये हो गया है। नतीजतन, वित्त वर्ष 2023 में यानी चुनाव से पहले राजकोषीय घाटा 46,622 करोड़ रुपये या जीएसडीपी के 2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 82,980 करोड़ रुपये या जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा उधार लेने के स्तर को दर्शाता है, और उच्च राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकारी उधारी के कारण निजी उधारकर्ता बाजार से बाहर हो जाएंगे। इसका स्पष्ट अर्थ है पूंजी का पूंजी-मित्रों की ओर पलायन -

कर्नाटक में भी यही हुआ है। 2021 में इसका कुल एफडीआई 22 बिलियन डॉलर से गिरकर 2021 में 22 बिलियन डॉलर हो गया।

22 से 2023-24 में 6.57 बिलियन डॉलर तक की मामूली राशि, जो कि अधिकतर होगी -
गुजरात में कोई भी फिट नहीं है।

अधिक उधार लेने से उच्च ब्याज के रूप में अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है जो विकास राजस्व व्यय को कम करता है, साथ ही उच्च मुद्रास्फीति का कारण बनता है। ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं, और कई वर्षों में पहली बार, वित्त वर्ष 2024 में, कर्नाटक की वास्तविक विकास दर 6.6 प्रतिशत राष्ट्रीय दर 7.3 प्रतिशत से नीचे आ गई। उधार से होने वाली अतिरिक्त देनदारी के कारण कुल ऋण स्टॉक बढ़ जाता है और परिणामस्वरूप उच्च ऋण अनुपात (जीएसडीपी के लिए बकाया ऋण का अनुपात) जो वित्त वर्ष 2024 में 22.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 24 प्रतिशत हो जाएगा।

गोविंद भट्टाचार्य

लेखक एक टिप्पणीकार, लेखक और शिक्षाविद हैं। व्यक्त किए गए विचार निजी हैं

जब सरकार अपने वादों के पूरा होने का जश्न मना रही थी और पार्टी नेता सीएम को बधाई दे रहे थे, तब 1.26 करोड़ महिलाओं ने गृह लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण कराया। संभावित बजटीय प्रभाव से चिंतित वित्त विभाग ने योजना की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल कल्याण विभाग को एक नोट लिखा, जिसमें कहा गया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 31,423 करोड़ रुपये राज्य को काफी राजस्व घाटे की ओर ले जाएंगे, जो संभावित रूप से कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उल्लंघन होगा। इसमें कहा गया है कि योजना -

ईएमई के परिणामस्वरूप पर्याप्त आवर्ती देयता होगी और -

सभी विभागों और खातों में बजटीय प्रावधानों में महत्वपूर्ण कटौती की आवश्यकता है। निष्कर्ष: यह संभव नहीं है

इतनी बड़ी राशि प्रदान करें -
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निधियों की संख्या।

इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, 30 अक्टूबर को उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने संकेत दिया कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शक्ति योजना की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें फटकार लगाई और आगामी महाराष्ट्र चुनावों के दौरान गैर-टिकाऊ मुफ्त सुविधाओं का वादा करने के खिलाफ पार्टी को आगाह किया।

बजट पर विचार किए बिना वादे करने से दिवालियापन हो सकता है; सड़कों पर रेत डालने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार विफल होती है, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इससे बदनामी हो सकती है और सरकार को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है -

अगले दस वर्षों के लिए।

ये गारंटियां राज्य के विकास पर भारी पड़ रही हैं।

अगस्त 2023 में सरकार ने मांग की -
15वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के तहत बकाया राशि के रूप में केंद्र से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। कोविड के कारण एक असामान्य कदम उठाते हुए, जिसने केंद्र और राज्यों के वित्त को समान रूप से प्रभावित किया था, एफएफसी ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं, 2020-21 के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट और 2021-26 के लिए अंतिम रिपोर्ट।

पहली रिपोर्ट में, एफएफसी ने कर्नाटक और दो अन्य राज्यों - मिजोरम और तेलंगाना - के लिए 5,495 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र ने स्वीकार नहीं किया। कर्नाटक ने बेंगलुरु में दो परियोजनाओं - तालाबों के जीर्णोद्धार और पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना के लिए 3,000-3,000 करोड़ रुपये मांगे थे, जिसे भी केंद्र ने अपनी वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया। श्री सिद्धारमैया ने फिर एफएफसी द्वारा कर्नाटक की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन जब उन्हें इससे धन नहीं मिला, तो अन्य उपायों का सहारा लिया गया।

अक्टूबर 2023 में सभी संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जिससे 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जून 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 3 रुपये और 3.02 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

इन पर बिक्री कर बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।
अन्य उपायों में शराब की कीमतों में संशोधन, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ बेंगलुरू में घरों से ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव और खनन लाइसेंस के लिए शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है। जुलाई 2024 में, एससी/एसटी उप-योजनाओं में एससी/एसटी के कल्याण के लिए निर्धारित निधियों में से 37 प्रतिशत का उपयोग किया गया

इन गारंटियों के लिए 14,743 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है।

पार्टी विधायकों से कहा गया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन की मांग न करें, ताकि गारंटी के लिए धन जुटाया जा सके। राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में सिंचाई-कार्य और अन्य विकास कार्य धन की कमी के कारण रुके हुए हैं।

बजट के छठे हिस्से के लिए संसाधन जुटाना आसान नहीं है ~ हताश सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए छह महीने के लिए 9.5 करोड़ रुपये की लागत से एक निजी फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को नियुक्त किया। बीसीजी ने अन्य बातों के अलावा, बंगालू-रू के पास लगभग 25,000 एकड़ भूमि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सिफारिश की, जो गंभीर विरोध के घेरे में आ गई थी -

विधानसभा में गोलीबारी की, जिससे सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।

जब सब कुछ विफल हो जाता है, तो अंतिम पुनः -

केंद्र को दोष देना ही सही है, इसलिए सिद्धारमैया ने मेरा टैक्स, मेरा अधिकार अभियान शुरू करते हुए कहा कि कर्नाटक ने केंद्रीय कर में 4.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है -

सवाल यह है कि उसे केवल 50,000 करोड़ रुपये ही वापस मिले। अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो भारतीय संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

संक्षेप में, जबकि सरकार उन गारंटियों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिसके लिए नागरिकों पर भारी शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में नया बोझ डाला जा रहा है, विकास परियोजनाओं और पूंजी निर्माण को भारी झटका लग रहा है, जिससे राज्य का भविष्य अनिश्चित हो रहा है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना है, और राज्य की वितरण क्षमता धीरे-धीरे गायब हो जाएगी।

कर्नाटक के भी एक और राज्य बनने की पूरी संभावना है, जो अब तक अच्छी तरह से प्रबंधित था, और अपरिवर्तनीय क्षय की ओर बढ़ रहा है, तथा स्वार्थी राजनेताओं द्वारा प्रचारित अनियंत्रित और गैर-जिम्मेदार लोकलुभावनवाद का शिकार हो रहा है।

सरकारें अल्पकालिक होती हैं और अल्पकालिक निर्णय लेती हैं, क्योंकि दीर्घकालिक परिणाम सदैव उलझन भरे और उलझन भरे होते हैं।

समावेशी विकास का मतलब अब सिर्फ़ उन लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करना है, जिनके बारे में राजनेताओं को लगता है कि वे उनके लिए वोट करेंगे। लेकिन जोखिम यह है कि किसी समय, जो मतदाता अभी भी उतने ही गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, वे भी कमज़ोर आर्थिक विकास और खराब सेवाओं से तंग आ जाएँगे, जिससे राजनेताओं को मुश्किल विकल्प चुनने पर मजबूर होना पड़ेगा।

राजनेताओं के लिए इस क्षेत्र पर बातचीत करना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि उनकी लोकलुभावन नीतियों ने ऐसे हित समूहों का निर्माण कर दिया होगा जो निश्चित रूप से विद्रोह करेंगे, जिससे समाज अराजकता में फंस जाएगा।

जब वित्तीय आपदा अराजकता के साथ मिल जाती है, तो श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
फिलहाल, कर्नाटक में लोकलुभावनवाद का असर दिखने लगा है।

एक सदस्य की ANN ASIA NEWS NETWORK

एशियाई आवाज़ ASIAN VOICES

क्या बांग्लादेश आय कम करना 2030 तक असमानता समाप्त हो जाएगी?

सतत विकास के अंतर्गत दसवां लक्ष्य विकास लक्ष्य (एसडीजी) #10 इसमें लिखा है, "2030 तक, उत्तरोत्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर पर जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत हिस्से की आय वृद्धि हासिल करना और उसे बनाए रखना।" यह सभी देशों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देकर जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत हिस्से की आय को बढ़ाने का आह्वान करता है।

सभी लोगों को शामिल करना, चाहे उनका लिंग, आयु, शारीरिक स्थिति कुछ भी हो
विकलांगता, धर्म, जाति, वर्ग, जातीयता, आदि। इस वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति

इसके लिए उचित एवं समान अवसरों का सृजन, महिलाओं का सशक्तिकरण तथा गरीबी एवं असमानता में कमी लाना आवश्यक है।

अंतरिम सरकार के लोक प्रशासन और संवैधानिक सुधार आयोगों के चल रहे कार्यों में इन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भावी निर्वाचित सरकार सतत विकास लक्ष्य 10 को पूरा करने के लिए काम कर सके, क्योंकि बांग्लादेश के पास इस वैश्विक लक्ष्य पर पर्याप्त सुधार स्थापित करने के लिए केवल छह वर्ष का समय है।

भारत में आय असमानता की स्थिति को उचित रूप से समझने के संबंध में डेटा संबंधी चुनौतियां हैं।

बांग्लादेश। यूएनडीपी के आंकड़ों के अनुसार, देश की आबादी के निचले 40 प्रतिशत लोगों की आय में हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है। इसके विपरीत, शीर्ष 10 प्रतिशत के लिए, आय में हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है।
आय का हिस्सा 43 प्रतिशत है। घरेलू आय और व्यय अधिशेष के आधार पर

The Daily Star

वे (HIES), 2022 के अनुसार, निचले स्तर की 40 प्रतिशत आबादी की आय में प्रति वर्ष 7.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि कुल आबादी की आय की वार्षिक वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत होगी। HIES 2022 से पता चलता है कि शीर्ष 10 प्रतिशत परिवारों ने अपनी संपत्ति का हिस्सा 40.91 प्रतिशत तक बढ़ा लिया है, जो 2016 से लगभग 2.83 प्रतिशत की वृद्धि है। निचले स्तर के 50 प्रतिशत परिवारों के पास 2022 में कुल आय का 19.05 प्रतिशत हिस्सा था, जो 2016 में 20.23 प्रतिशत से कम हो गया।

भले ही देश ने गरीबी कम करने में प्रगति हासिल की हो, लेकिन आय गिनी गुणांक में वृद्धि जारी है। यह 2010 में 0.458 से बढ़कर 2022 में 0.499 हो गया। इसी अवधि के दौरान, उपभोग गिनी गुणांक 2010 में 0.321 से बढ़कर 2022 में 0.334 हो गया। पिछले दो दशकों के सर्वेक्षणों के डेटा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बांग्लादेश में आय और संपत्ति असमानता बढ़ रही है। चाहे हम जाने-माने उपाय, गिनी गुणांक या किसी वैकल्पिक उपाय पर विचार करें

पाल्मा अनुपात की तरह, और शीर्ष 10 प्रतिशत की आय हिस्सेदारी की तुलना निचले 40 प्रतिशत की आय हिस्सेदारी से करने पर, हमें वही परिणाम मिलता है, जो दर्शाता है कि हमारे समाज में असमानता लगातार बढ़ रही है।

देश के नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को बिना किसी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक अशांति के बनाए रखा जा सकता है। हालांकि, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आय और संपत्ति की असमानता अपने आप कम हो जाएगी।

असमानता को कम करने के लिए उपलब्ध सामान्य रणनीतिक विकल्प हैं भागीदारी योजना और समावेशी विकास, गरीब-हितैषी बजट निर्माण और कार्यान्वयन, कौशल विकास, आय पर प्रगतिशील कराधान, उपयुक्त कानून को अपनाना, भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करना, यथार्थवादी न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, बेहतर शासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी उपाय, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।

संरक्षण उपाय, लघु एवं मध्यम उद्यमों में निवेश, तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश।

बांग्लादेश में आर्थिक और सामाजिक समानता की प्राप्ति में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ हैं: शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर कम सार्वजनिक व्यय,

ग्रामीण विकास और सामाजिक संरक्षण;
खराब प्रत्यक्ष कर संग्रह और कर चोरी की संस्कृति; सामाजिक संरक्षण योजनाओं में चयन त्रुटि का उच्च स्तर; और सीमित परिसंपत्तियों वाले महिला-प्रधान परिवारों का उच्च प्रतिशत (12.6 प्रतिशत)

और उत्पादन के साधन।
देश में आर्थिक विकास का लाभ उच्च आय वर्ग के पास चला गया है, जबकि गरीब लोग हाशिए पर हैं।

संपादक के नाम चिठ्ठी LETTERS TO THE EDITOR

editor@thestatesman.com

मुद्रा स्फ़ीति

महोदय, सरकार के प्रयासों के बावजूद, देश में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति चौदह महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा मंगलवार को उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर है।

आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत थी।

ऐसी स्थिति में, इस वर्ष दिसंबर में ब्याज दरें कम होने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।

खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि सब्जियों, फलों, वसायुक्त खाद्य पदार्थों और तेलों की लागत में वृद्धि से संबंधित है। यह गहरी संरचना को दर्शाता है-

भारत की खाद्य आपूर्ति प्रणाली में मौजूद प्राकृतिक मुद्दे।

इसमें स्थिति को सुधारने के लिए त्वरित सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

निश्चित रूप से, अक्टूबर में भोजन - मुद्रास्फीति की दर 10.87 प्रतिशत है, जो इस साल की सबसे अधिक दर है, जिससे नीति निर्माताओं को चिंता होनी चाहिए। दूसरी ओर, बढ़ती मुद्रास्फीति दर्शाती है कि अस्थिर खाद्य कीमतें देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को कैसे कमजोर कर सकती हैं।

वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से टमाटर और तेल की कीमतों में वृद्धि, तथा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं और आयातित वस्तुओं पर देश की निर्भरता हमारी कमजोरी को दर्शाती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हर साल बरसात के मौसम में सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।

राज्य उत्पादन और आपूर्ति में बाधा डालते हैं।
साथ ही सब्जियों और फलों को भी नुकसान हो रहा है।

अनियमित और अत्यधिक वर्षा ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभाव चरम पर पहुंच गए हैं।

हमारे दरवाजे पर.

आपका, आदि, अभिजीत रॉय, जमशेदपुर, 14 नवंबर।

यादों का बगीचा

महोदय, यह आपकी रिपोर्ट नाटककार और अभिनेता मनोज मित्रा के निधन पर 13 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट से संबंधित है। नाटककार-निर्देशक मनोज मित्रा का निधन फिल्म उद्योग के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

कुछ यादें कभी मिटती नहीं। तपन सिन्हा निर्देशित बंगाली फिल्म बंचारामर बागान में मनोज मित्रा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बूढ़े बंचाराम की भूमिका में उनके अभिनय की हर जगह सराहना हुई थी। फिल्म का आउटडोर हिस्सा बरुईपुर के एक बगीचे में शूट किया गया था। फिल्म रिलीज होने के बाद वह बगीचा बंचाराम के बगीचे के नाम से मशहूर हो गया। यह बगीचा चक्रवर्ती परिवार का है। परिवार ने बगीचे में ज्यादा बदलाव नहीं होने दिया। आज भी उस बगीचे में फिल्मों की शूटिंग होती है। कुछ लोग सर्दियों में पिकनिक मनाने भी आते हैं। पुराने आम के पेड़ बंचाराम की यादें संजोए हुए हैं।

आपका आदि, देबप्रसाद भट्टाचार्य, सोनारपुर, 14 नवंबर।

Machine Translated by Google

माइंडफुलनेस सिटी के लिए मानसिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण

स्नेहा पोद्दार और
एंड्रयू शेंग

भूटान ने एक "माइंडफुलनेस सिटी" बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है, जो इस तरह की सफलता सुनिश्चित करेगी

जैसा

शहर?

इसका उत्तर केवल वास्तुकला, हरित स्थान, उन्नत अवसंरचना या लोगों में नहीं है, बल्कि इसके निवासियों की मानसिकता या मन की खेती में है। माइंडफुलनेस में निहित शहर का निर्माण करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के समुदाय की आवश्यकता होती है जो गहराई से जागरूक, दयालु, परस्पर जुड़े हुए और जैविक उद्भव के लिए इच्छुक हों। मन की खेती के बिना, माइंडफुलनेस सिटी की कोई भी कल्पना अधूरी रहेगी, जिससे निवासियों को जीडीपी की माइंडफुलनेस की ओर ले जाया जाएगा, जो वर्तमान में वैश्विक खुशी और कल्याण को नष्ट करने वाला कारक है।

आज की दुनिया में, ज़्यादातर लोग मुख्य रूप से बाएं-दिमाग, विश्लेषणात्मक मानसिकता से काम करते हैं। तर्कसंगत, लक्ष्य-उन्मुख सोच के पक्ष में इस प्रवृत्ति ने वास्तविकता के एक खंडित दृष्टिकोण को जन्म दिया है। जब जीडीपी में तर्कसंगतता को प्रगति के एक संकीर्ण उपाय के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें मनुष्यों और ग्रह की भलाई को अनदेखा किया जाता है, तो वह आंशिक तर्कसंगतता भ्रामक और हानिकारक दोनों होती है। बायाँ-दिमाग बाहरी दुनिया को वर्गीकृत करने, उसका विश्लेषण करने और उसे नियंत्रित करने में माहिर होता है, फिर भी यह अक्सर उन गहरे संबंधों और अंतर्निहित संपूर्णता को समझने में विफल रहता है, जिन्हें दायाँ-दिमाग समझ सकता है। यह असंतुलन सिर्फ़ एक व्यक्तिगत चिंता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है, जो पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक विघटन और अस्तित्व संबंधी खतरों के रूप में प्रकट होता है।

अधिक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने के लिए, हमें अपना ध्यान केवल मन को लगाने से हटाकर सचेत रूप से उसे विकसित करने पर केन्द्रित करना होगा।

यह समझने के लिए कि माइंडफुलनेस सिटी के लिए मन की साधना क्यों महत्वपूर्ण है, यह पहचानना आवश्यक है कि व्यक्ति और उनके कार्य समाज के ढांचे का निर्माण करते हैं। लोग जो कार्य करते हैं, वे उनके मन की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होते हैं।

यदि अधिकांश मन गलत रूप से गठित, अपरिष्कृत अवस्था से कार्य करते हैं, तो संग्रहकर्ता- वास्तविक वास्तविकता अनिवार्य रूप से इस असंतुलन को दर्शाती है। एक समाज जो केवल मन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है - इसे लक्ष्य प्राप्त करने, शक्ति प्राप्त करने और संसाधनों या सकल घरेलू उत्पाद को इकट्ठा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है - मन की खेती के महत्वपूर्ण कदम को याद करता है। यह चूक ऐसे व्यक्तियों को जन्म देती है जो संकीर्ण स्वार्थ, अल्पकालिक लाभ और सतही सुखों से प्रेरित होते हैं, जो सभी व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय संकटों में योगदान करते हैं।

जीडीपी में सफलता सापेक्ष है। चूंकि जीडीपी मौद्रिक शर्तों में सफलता का सूचकांक है, इसलिए जीडीपी जाल में फंसे लोग मौद्रिक शर्तों में एक दूसरे के खिलाफ अपनी "प्रगति" को मापते हैं।

एक निश्चित स्तर के बाद, जीडीपी बाजार में भाग लेने वाले लोग केवल पैसे और लालच के बारे में सोचते हैं, और एक-दूसरे, ग्रह और समग्र कल्याण की परवाह कम करते हैं। साधन ही अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भौतिक आय और कल्याण की आवश्यकता को संतुलित करना माइंडफुलनेस के मूल में है - यह ऐसे समग्र और स्वस्थ लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों के साथ लक्ष्यों को संतुलित करता है।

भूटान में, जहाँ वज्रयान बौद्ध धर्म में निहित सांस्कृतिक परंपराओं ने लंबे समय से मन की साधना पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया है, माइंडफुलनेस सिटी के निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक और दार्शनिक आधार है। मन के विज्ञान संस्थान और वज्रयान प्रथाओं की समृद्ध विरासत एक ऐसे मन की साधना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं के मात्र प्रयोग से आगे बढ़कर जागरूक और दयालु दोनों है।

इन प्रथाओं ने इस बात पर बल दिया है कि मन की साधना एक निष्क्रिय गतिविधि या एकाकी अभ्यास नहीं है, बल्कि इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है - जिसे अब कुछ विद्वान "अभ्यासों की पारिस्थितिकी" कहते हैं।

पारंपरिक पूर्वी शिक्षा प्रणालियों के स्थान पर आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आने से मन के विकास से दूर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।

पहले, शिक्षा का मतलब सिर्फ़ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ज्ञान, चरित्र और खुद और ब्रह्मांड की गहरी समझ विकसित करना था। भूटान और पूर्व के अन्य हिस्सों में, मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में ऐसी प्रथाएँ शामिल थीं जिनका उद्देश्य था जागरूकता, करुणा और परस्पर जुड़ाव की भावना विकसित करना।

ये अभ्यास बौद्ध धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की शिक्षाओं में अंतर्निहित थे, जो पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए मन की साधना को केंद्रीय मानते थे।

हालाँकि, आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आगमन से ध्यान बदल गया।
आलोचनात्मक सोच, वैज्ञानिक समझ और तकनीकी उन्नति रैखिक और यांत्रिक बन गई, जिसमें फीडबैक, अंतःक्रिया और जटिल मुद्दों की उलझनों की उपेक्षा की गई।

जबकि ये निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं, वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। इस संकीर्ण फोकस ने ऐसे व्यक्तियों के विकास को जन्म दिया है जो अपने बाहरी वातावरण में हेरफेर करने में अत्यधिक कुशल हैं, लेकिन अपने कौशल का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आवश्यक आंतरिक स्थिरता, नैतिक आधार और जागरूकता की कमी है। मुख्यधारा की शिक्षा में इस तरह की मानसिकता की कमी ने एक ऐसे सामाजिक मॉडल को बढ़ावा दिया है जो आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को मानव कल्याण और पारिस्थितिक संतुलन से अधिक प्राथमिकता देता है।

डोनेला मीडोज, एक प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक और सिस्टम थिंकर, ने वैश्विक स्तर पर एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे व्यवहार से उत्पन्न होने वाले गहरे आदर्शों में परिवर्तन सार्थक और टिकाऊ समाधान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस समग्र आत्म-परिवर्तन के लिए पारंपरिक सोच पैटर्न से आगे बढ़कर गहरी जागरूकता और जुड़ाव विकसित करने की आवश्यकता है। मन की खेती या माइंडफुलनेस को वैश्विक प्राथमिकता बनना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत या सांस्कृतिक प्राथमिकता।

सौभाग्य से, मानसिकता परिवर्तन के तरीकों को शुरू से ही आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। भारत और भूटान की समृद्ध परंपराएँ, ध्यान, माइंडफुलनेस और नैतिक जीवन जैसी प्रथाओं में गहराई से समाहित हैं, जो मन को विकसित करने के लिए समय-परीक्षणित ढाँचा प्रदान करती हैं। सहस्राब्दियों से परिष्कृत इन प्रथाओं को बस आधुनिक संदर्भ में अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इन पूर्वी परंपराओं को समकालीनता में एकीकृत करना-

निरंतर शिक्षा और दैनिक जीवन एक अधिक जागरूक, सजग और दयालु वैश्विक समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चिंतन और आत्म-चिंतन के लिए पैसे की नासमझ खोज से दूर, स्वयं और समुदाय के लिए एक शांत, शांत समय की आवश्यकता होती है। माइंडफुलनेस सिटी के लिए यही अवसर है।

माइंडफुलनेस में पश्चिमी देशों की रुचि तेजी से बढ़ी है, जो अक्सर इस अवधारणा को ध्यान के एक एकल अभ्यास तक सीमित कर देती है। जबकि ध्यान निस्संदेह जागरूकता विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यह अहसास अकादमिक हलकों में मान्यता प्राप्त कर रहा है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, जहाँ मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि मन को सही मायने में विकसित करने के लिए अभ्यासों का एक व्यापक सेट आवश्यक है। पूर्व की प्राचीन परंपराओं ने इसे लंबे समय से समझा है, जैसा कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक महान मार्ग और योग के आठ अंगों में देखा गया है।

ये ढांचे प्रथाओं का एक व्यापक सेट या "प्रथाओं की एक पारिस्थितिकी" प्रदान करते हैं जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान को एकीकृत करते हैं।

मन की साधना से हटकर मात्र प्रयोग की ओर जाने के कारण समाज के आध्यात्मिक भाग में गिरावट आई है। यह गिरावट अवसाद, संघर्ष, हिंसा और अपराध के बढ़ते मामलों में प्रकट होती है। बिना संस्कारित मन के, व्यक्ति अक्सर अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग केवल आनंद, मनोरंजन या व्यवसाय के लिए करते हैं, जीवन के उन गहरे पहलुओं की उपेक्षा करते हैं जो जीवन में योगदान करते हैं।

सच्चा कल्याण और संतुष्टि। इस संदर्भ में, माइंडफुलनेस सिटी को अपने नागरिकों के दिमाग को विकसित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। माइंडफुल आर्किटेक्चर, ग्रीन स्पेस, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक हार्डवेयर होना ही काफी नहीं है; व्यक्तियों का आंतरिक विकास सबसे आगे होना चाहिए।

खुशी केवल भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा में अधिक मूल रूप से निवास करती है। भूटान, अपनी गहरी आध्यात्मिक विरासत और सकल राष्ट्रीय खुशी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, सचेत जीवन जीने और अभ्यास करने में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। शिक्षा और सामाजिक मानदंडों में "अभ्यासों की पारिस्थितिकी" को शामिल करके, भूटान एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित कर सकता है कि कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहाँ व्यक्ति न केवल संज्ञानात्मक रूप से कुशल हों, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित हों। व्यक्तिगत जिम्मेदारी की एक संहिता स्थापित करना जो पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन के साथ-साथ मन की खेती पर जोर देती है, इस दृष्टि का अभिन्न अंग होगा।

(लेखक क्रमशः जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एंड एडवांस्ड स्टडीज में रिसर्च फेलो, ग्लोबल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के एसोसिएट, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख में सहायक संकाय सदस्य और हांगकांग विश्वविद्यालय के एशिया ग्लोबल इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित फेलो हैं, जो वैश्विक वित्त, जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक मुद्दों पर लिखते हैं।)

एएनएन के लिए विशेष।

कमला की हार क्या संकेत देती है?

अनीस शिवानी

मृत्यु का उद्देश्य निश्चित रूप से की गई गलतियों पर केन्द्रित होना है

चुनाव के बाद का अधिकांश भाग- कमला हैरिस द्वारा, लेकिन मैं 2024 के चुनावों में डेमोक्रेट्स की व्यापक हार की एक बड़ी तस्वीर के लिए एक कदम पीछे जाना चाहता हूं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बिडेन और उनके त्वरित-समाधान वाले उत्तराधिकारी की गलतियों ने सफाया में योगदान दिया, लेकिन बढ़ते हुए अति-राष्ट्रवादी खतरे के खिलाफ नवीनतम उदारवादी झटके का मूल कारण राजनीतिक पक्षाघात है, जिसका सामना यह गिरता हुआ साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में कर रहा है।

लिज़ चेनी जैसे बदनाम नवरूढ़िवादियों के साथ चलना, सम्मेलन के दौरान एक मुस्लिम अमेरिकी को बोलने से मना करना, तथा केवल उत्साह और आनंद के बल पर चलने की उम्मीद करना, कॉर्पोरेट सशक्तिकरण की सलाहकार-संचालित राजनीति के लिए भयानक रियायतें थीं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने आर्थिक दर्द को दूर करने और युद्धों को समाप्त करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास करने के बजाय आत्म-हाशिए पर जाना क्यों पसंद किया?

डोनाल्ड ट्रम्प के पुनरुत्थान का पैमाना इस बात की पुष्टि करता है कि 2016 में उनकी शुरुआती जीत कोई संयोग नहीं थी। बल्कि, ओबामा के युग में तीखी पहचान की राजनीति और छोटी-छोटी आर्थिक पहलों को निश्चित रूप से फटकार मिली है। 2024 का चुनाव 1980 और 2000 के चुनावों से तुलना करने लायक है, क्योंकि मजदूर वर्ग ने उन्हीं नीतियों को खारिज कर दिया है, जिनके बारे में नवउदारवादियों को लगता था कि वे उनके लिए फायदेमंद होंगी। मैं नहीं मानूंगा इसे पुनर्संरेखण के रूप में वर्णित करें, जिसे गलती से 2004 और 2008 में भी लागू किया गया था। यह पदनाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा हर कुछ वर्षों में इस्तेमाल किया जाता है, और 1968 को छोड़कर, वियतनाम पराजय और नागरिक अधिकार कानून के प्रति दक्षिण के प्रतिशोध के मद्देनजर, शायद ही कभी लागू होता है।

ट्रम्प संभवतः प्रोजेक्ट 2025 के अनुसार प्रशासनिक राज्य को खत्म करने में अतिशयोक्ति करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में विनियामक राज्य को खत्म करने के प्रयास असहनीय दर्द का कारण बनेंगे। वह कठोर सार्वभौमिक टैरिफ लगाने और प्रशासनिक साधनों और वास्तविक राउंडअप के माध्यम से बड़े पैमाने पर निर्वासन को लागू करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे-जैसे ये उपाय मुद्रास्फीति को फिर से बढ़ाते हैं, कामकाजी वर्ग के मतदाताओं का उनका नया गठबंधन बिखर जाएगा। अगले चुनावी चक्र तक, वे आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स से उनके जीवन की घटती गुणवत्ता को कम करने में कोई मदद मिलेगी।

ट्रम्प 2.0 पहले अवतार से अलग है। अपूर्ण अलगाववादी प्रवृत्तियाँ - वास्तव में, साम्राज्य को समाप्त करने की इच्छा - हाल ही में अरबपति वर्ग की पूर्व-न्यू डील युग में शून्य विनियमन की वापसी की स्पष्ट रुचि के साथ मिल गई है, जो कि श्रमिक वर्ग को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य की कठोर दंडात्मकता द्वारा समर्थित है।

ट्रम्प पिछली बार की तुलना में कहीं बेहतर तैयारी के साथ आए हैं, उनके वफादारों ने ऐसी योजनाएँ बनाई हैं, जो जीवन को जीने लायक बनाने वाली हर चीज़ पर तुरंत काम करने के लिए तैयार हैं।

इन उद्देश्यों का एक अंश, विशेष रूप से प्रवासन और टैरिफ के संबंध में, उथल-पुथल का कारण बनेगा, जिससे राजनीतिक भाग्य में एक और उतार-चढ़ाव आएगा।

अब हर चुनाव बदलाव का चुनाव लगता है। पिछली बार जब कोई ठोस बिप कारीगर विधायी प्रगति हुई थी, तब बिल क्लिंटन ने नवउदारवादी वैश्वीकरण की नींव रखी थी, उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नवउदारवादी वैश्वीकरण की नींव रखी थी।

बुश द्वारा निगरानी-लांस राज्य के कार्यान्वयन। ओबामाकेयर, निजीकृत चिकित्सा का एक रूप, टी पार्टी और आंशिक रूप से ट्रम्पवाद का परिणाम है। हर बार जब जमीनी स्तर पर प्रगतिशील उभार होता है, जैसा कि 2000 में राल्फ नादर या 2016 और 2020 में बर्नी सैंडर्स के साथ हुआ, तो परिणाम एक बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी बदलाव के रूप में दिखाई देता है।

इस बार मतदाताओं ने इसी कदम का समर्थन किया है।

हालाँकि हैरिस की हार की बहुत सी आलोचनाएँ इस बात पर केंद्रित होंगी कि वह जीवन की लागत को कम करने के लिए कोई सुसंगत आर्थिक संदेश देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन न तो बिडेन और न ही हैरिस ने उन प्रगतिशील मील के पत्थरों का बखान किया जो उन्होंने हासिल किए थे। बिडेन की प्रशंसा करना आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन निस्संदेह वे ओबामा से बहुत दूर थे, और स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण, औद्योगिक नीति और एंटी-ट्रस्ट विनियमन पर अग्रिम भुगतान किया गया था। बिडेन की लोकप्रियता में तेज गिरावट तब शुरू हुई जब उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी का सही ढंग से पालन किया।

मूल बिल्ड बैक बेटर योजना, जिसकी देखभाल अर्थव्यवस्था समग्र है- अधिकांश नेट्स हटा दिए गए थे, हैरिस के दक्षिणपंथी झुकाव के मद्देनजर यह एक असंभव सपना जैसा लगता है। बिडेन प्रेसीडेंसी को प्रगतिशील उत्साह के चरम से एक प्रबंधित गिरावट के रूप में भी व्याख्या किया जा सकता है, क्योंकि महामारी को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कम से कम श्रमिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए बयानबाजी की निष्ठा थी।

श्रमिकों की भारी कमी को पूरा करने के लिए आव्रजन को सही तरीके से ढीला किया गया था, और मुद्रास्फीति की वृद्धि दर, जिसके लिए ट्रम्प के पिछले टैरिफ और आव्रजन प्रतिबंधों ने महामारी-युग की आपूर्ति श्रृंखला की कमी के समान ही योगदान दिया था, काफी कम थी। लेकिन बिडेन और हैरिस इन पहलों के बल पर क्यों नहीं चले? ट्रम्पियन ज़ेनोफ़ोबिया और सांस्कृतिक व्यामोह, जो ट्रांसजेंडर लोगों के डर में उदाहरणित है, ने बिडेन के विधायी प्रयासों को पूरी तरह से पृष्ठभूमि में क्यों धकेल दिया? मुझे विश्वास नहीं है कि मुद्रास्फीति के कहर के बावजूद चुनाव का परिणाम अपरिहार्य था। हैरिस बिडेन की अल्पविकसित आर्थिक प्रगतिवाद पर निर्माण कर सकती थीं, और युवाओं को आर्थिक रूप से टिकाऊ भविष्य और विकल्पों के दोहरे युद्ध से बाहर निकलने की आशा दे सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यह संयोग नहीं था।

ऐसा प्रतीत होता है कि उदारवादियों की ओर से 2004 के बाद और निश्चित रूप से 2016 के बाद से अधिक आत्ममंथन हो रहा है, जब ट्रम्प को एक अलग व्यक्ति और उनके मतदाताओं को निंदनीय बताकर दोष देना बहुत आसान था।

और फिर वर्षों तक उसे और उसके आंदोलन को आपराधिक उद्यम के रूप में अयोग्य ठहराने की कोशिश करते रहे।

लेकिन आप तब क्या करेंगे जब सभी जातियों के बड़ी संख्या में मेहनतकश लोग उस पार्टी की ओर आकर्षित होंगे जिसके टैरिफ और प्रवासन दमन से भारी आर्थिक व्यवधान पैदा होगा?

क्या ऐसी कोई भाषा भी है जो ऐसे मतदाताओं को खुलेपन के लाभों के बारे में बता सके, चार दशकों से चल रहे नवउदारवादी शून्य-योग खेल के बाद, जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है? शायद ऐसी कोई भाषा है, लेकिन इसकी कोशिश नहीं की गई।

बाकी दुनिया के लिए सबसे स्वस्थ परिणाम यह होगा कि MAGA आंदोलन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अलग हो जाए। यह वह घातक झटका है जिसे साम्राज्य खुद पर थोपने के लिए दृढ़ है और यह अंततः बताता है कि क्यों प्रगतिशील पहल, चाहे बड़ी हो या छोटी, मूल में सड़े हुए खालीपन को संतुष्ट नहीं कर सकती। आखिरकार, यह रणनीति या तरकीबों की विफलता नहीं थी जिसने हैरिस को बर्बाद कर दिया, बल्कि साम्राज्य के पतन की दिशा में आगे बढ़ना था जो अब अजेय लगता है।

डॉन/एएनएन.

NOW AND AGAIN / अब और फिर से

DIFFERENT STROKES / अलग-अलग स्ट्रोक

बुद्धदेव नंदी

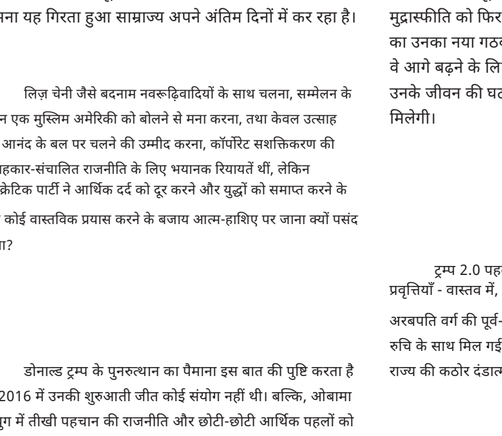

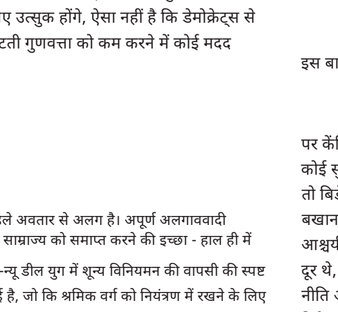

घर एक स्थायी निवास स्थान है
बंदरों का झुंड और उनका झुंड
हमारे पीछे फैला हुआ बगीचा

गिलहरी। मुख्य कारण यह है कि हमारा बगीचा मुख्य रूप से एक बाग है। आम, जामुन, कटहल, अमरूद, मिट्टी के सेब और अनार के पेड़ों सहित अधिकांश पेड़ साल भर स्वादिष्ट फल देते हैं। मजबूत शाखाओं वाले ये सदाबहार पेड़ उछलते, कूदते और उछलते-कूदते बंदरों को अच्छा सहारा देते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, बगीचे में बहुत सारा पानी उपलब्ध है क्योंकि बगीचे में घर के कुएं के पास पानी से भरी कई बाल्टियाँ और ड्रम मुख्य रूप से पेड़ों को पानी देने के लिए रखे गए हैं।

वैसे, मेरे पिता को छोड़कर हमारे परिवार के सभी सदस्यों की बंदरों की टोली से बहुत दुश्मनी थी। किचन गार्डन या फूलों की क्यारी बनाने की हमारी बार-बार की कोशिशें नाकाम हो गई थीं। इसके अलावा, जब भी किचन का दरवाज़ा खुला रहता है, तो बंदर चुपके से अंदर घुसकर आलू, बैंगन, खीरे और लौकी चुरा लेते हैं। यहाँ तक कि बिस्कुट, नमकीन और अचार वाले बर्तन भी लूट लिए जाते हैं।

हमने उन्हें अपने बगीचे से भगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने पटाखे फोड़े लेकिन बंदरों को तेज आवाज की आदत हो गई थी। गुलेल से कुछ समय के लिए काम चल गया, लेकिन फिर उन्होंने अपने कलाबाजों की बदौलत कांच के कंचों से बचने की कला में महारत हासिल कर ली।

हालाँकि, खास तौर पर युवा बंदरों की मस्ती देखने में मज़ेदार होती है, लेकिन हमारे परिवार के ज़्यादातर सदस्य इस झुंड के कट्टर दुश्मन हैं। जब भी हम बगीचे में जाते हैं, तो वे चिल्लाते हैं और गुस्से में अपने दाँत दिखाते हुए हमारी ओर चिल्लाते हैं। एक दिन, जब मैं बायोमास लगाने के लिए एक पेड़ के चारों ओर उथली खाई खोदने में व्यस्त था, तो एक बंदर ने मेरी पीठ खरोंच दी और मुझे टीका लगवाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

लेकिन मेरे दिवंगत पिता, जो सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षक थे, के साथ सेना ने काफी सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। मेरे पिता ने कभी भी हमारे बंदर विरोधी अभियान का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि बगीचे में होने वाली उपज पर पहला अधिकार बंदरों, पक्षियों, गिलहरियों आदि का है। जब वे घर पर होते थे तो हम बंदरों को भगाने से परहेज करते थे।

मेरे नब्बे वर्षीय पिता दिन का अधिकांश समय - सुबह से शाम तक - बगीचे में बिताते थे। एक पत्तेदार आम के पेड़ के नीचे सागौन की लकड़ी से बनी एक कुर्सी लगभग लगी हुई थी। एक शौकीन पाठक के रूप में, वे किताबें, अख़बार, पत्रिकाएँ आदि पढ़ने में तल्लीन रहते थे। अक्सर, बंदर उनके आस-पास ज़मीन पर मँडराते रहते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी कुर्सी के हैंडल पर उछल-कूद कर बैठते थे। वे उनकी कमीज़ की जेबों में मूंगफली और बिस्कुट ढूँढ़ते रहते थे। जब भी वे सुबह और शाम को टहलते थे, तो कुछ छोटे बच्चे उनके पीछे-पीछे चलते हुए पाए जाते थे। गिलहरियों का झुंड भी दौड़ता रहता था और कबूतरों का झुंड उनके हाथों से मूंगफली और चावल लेने के लिए उनके इर्द-गिर्द घूमता रहता था।

यद्यपि हमें डर था कि मेरे पिता पर किसी दिन दल द्वारा हमला हो सकता है या गिलहरियाँ उन्हें काट सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की।
मेरे पिता की मृत्यु के बाद से बंदरों ने गुलेल के हमले के डर से हमारे बगीचे की जमीन पर उतरना बंद कर दिया है।

100 YEARS AGO / 100 साल पहले

LACK OF MANPOWER / जनशक्ति की कमी

FRANCE REDUCING HER ARMY / फ्रांस में कटौती उसकी सेना

(टाइम्स विशेष सेवा.)

"फ्रांस किसी निरस्त्रीकरण सम्मेलन की प्रतीक्षा किए बिना अपनी सेना में बदलाव कर रहा है और उसे कम कर रहा है। उसके इरादे शांतिपूर्ण हैं, लेकिन वह आराम से नहीं रहना चाहती और हथियारबंद रहेगी।"

द टाइम्स में एक सैन्य लेखक ने "फ्रांस में सेना में परिवर्तन" पर अपने लंबे लेख का समापन इस प्रकार किया है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि हाल के फ्रांसीसी सैन्य निर्णय निस्संदेह काफी हद तक जनशक्ति की कमी के कारण लिए गए हैं।

"लेकिन," वे कहते हैं, "हालाँकि फ्रांसीसी खुद को अपनी सेना को कम करने और बदलने के लिए मजबूर पाते हैं, फिर भी वे मज़बूत और कुशल बने रहने का इरादा रखते हैं। पुनर्गठन की योजना के पीछे का विचार अपरिवर्तित है। इसका उद्देश्य फ्रांस को जर्मनी द्वारा विनाश के ख़तरे से बचाना है, जिसे अभी भी एक संभावित दुश्मन माना जाता है।"

COFFEE PROSPECTS / कॉफी की संभावनाएँ

AS BRIGHT AS THOSE OF TEA / उतना ही उज्ज्वल चाय के जैसा

(हमारे संवाददाता से)

प्लांटर्स क्रॉनिकल के लंदन संवाददाता ने चाय की आश्चर्यजनक कीमतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस वर्ष दक्षिण भारत लगभग उत्तर भारत के बराबर पहुंच गया है, लेकिन सीलोन अभी भी काफी आगे है।

पिछले महीने कॉफी को खास तौर पर सामान्य से कहीं ज़्यादा प्रचार मिला है। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने सांख्यिकीय स्थिति की ओर ध्यान खींचा है और खरीदारों ने, फसल के कम अनुमान को देखते हुए, स्पष्ट रूप से यह तय कर लिया है कि मौजूदा सीज़न में कीमतें ऊंची रहेंगी। इस प्रकार कॉफी उत्पादक कंपनियों के लिए संभावनाएँ विशेष रूप से उज्ज्वल हैं।

कॉफी को खास तवज्जो मिलने की एक वजह यह थी कि एक्वा सांता कॉफी कंपनी की रिपोर्ट अक्टूबर की शुरुआत में ही आ गई थी। पिछले दो सालों के औसत 5,000 पाउंड के मुकाबले कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 20,400 पाउंड हो गया।

CROSSWORD / क्रॉसवर्ड

NO 292963

PREVIOUS SOLUTION

ACROSS

1 ग्रीक राज्य पीछे हट गया स्ट्राइक द्वारा (6)
5 पृथ्वी के मेंटल से विस्फोट (6)
8 गायक मंडली में कसाई ने नए पादरी को चौंका दिया (6,8)
9 दृश्य पढ़ें उद्धरण (5)
10 बेस्टसेलर सूची ने कुछ स्थानीय दुकानों को प्रभावित किया (3,6)
12 शादी के अंदर ही शिक्षित महिला को फ्रांसीसी बीमारी लग जाती है? इसके विपरीत (7)
14 मिलीभगत शुरू हो जाती है गुस्से से भरे कॉल का कारण संसद (7)
15 महत्वपूर्ण हिस्सा येल में प्रवेश दिलाने वाला पाठ्यक्रम? (7)
18 पोशाक और ड्रेसिंग: क्रिया का हिस्सा और एक जेरंड (7)
20 के बाद की गई कार्रवाई क्षेत्रीय फेरबदल के दौरान निदेशक को हटाया गया (9)
21 क्यूबेकॉइस विकास का चार्ट बनाएं, विशेष रूप से कनाडा में (5)
22 क्या महिला पुरुष के पास कोई योजना है? (7-7)
23 धार्मिक समुदाय सर्वनाश की शुरुआत को लेकर खुश है (6)
24 हम बाहर रहते हैं, चिकनाई, स्वाभाविक रूप से (6)

नीचे

2 कलाकार आगे नहीं बढ़ पा रहा है (7)
3 अदरक के बाल असली रंग दिखाना (5)
4 फ़िज़ी कोला पीने के तुरंत बाद गुहा दिखाई देना (7)
5 सुधारवादी नेता इक्वाडोर का प्रभार जारी रहेगा (7)
शाम 6 बजे का निर्देश काबुल में संपर्क व्यक्ति, साथी गायब हो गया (9)
7 बूढ़ा आदमी उस स्पेनिश पड़ोसी के खिलाफ मतदान कर रहा है (7)
8 कानून के निर्माता पुलिस जो निगरानी रखती है? (9)
11 वसंत ऋतु का उपहार, जिसमें एक के लिए विशेष दरें शामिल हैं (6,3)
13 संकरे जंक्शन पर हिंसक विवाद सुलझने लगा है (6,3)
16 टेबल पर दो पॉइंटर्स ने चिकन को लार टपकाना शुरू कर दिया (7)
17 कहावत जन सब को ऊपर उठाती है निराशा से भी (7)
18 लम्बे अंगों वाला पायलट, अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में कुशल (7)
19 फ़ोन पर बहस करना (7)
२१ हिरण चारों ओर मवेशियों की नकल कर रहे हैं लंदन (5)

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक आवश्यक शब्दों में अक्षरों की संख्या दर्शाते हैं। (द इंडिपेंडेंट, लंदन के साथ व्यवस्था द्वारा)

Machine Translated by Google

the pioneer agenda

मैं गोवा के मनमोहक तटीय शहर में, जहां समुद्र सपने की फुसफुसाहट करता है और रेत कहानी को समेटे हुए है, भव्य पर्दे उठाए जाएंगे

अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) दुनिया के लिए एक मान्यता प्राप्त महोत्सव है। आईएफएफआई एकमात्र दक्षिण एशियाई महोत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघों के महासंघ (एफआईएपीएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

अब, 2004 से गोवा में आयोजित किया जा रहा IFFI न केवल फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक भव्य महोत्सव है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहां भारतीय सिनेमा विश्व सिनेमा के साथ बातचीत करता है, जहां फिल्म निर्माता दर्शकों से जुड़ते हैं, और जहां कहानी कहने का जादू वास्तव में मनाया जाता है।

इस साल, IFFI को 101 देशों से 1,676 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जो इतने वर्षों के बाद इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्में दिखाई जाएँगी

81 देशों की फिल्में, जिनमें 15 विश्व प्रीमियर, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 40 एशियाई प्रीमियर और 106 भारतीय प्रीमियर शामिल हैं।

दुनिया भर की प्रसिद्ध शीर्षकों और पुरस्कार विजेता फिल्मों को प्रदर्शित करते हुए, इस वर्ष का महोत्सव दर्शकों और सिनेमा की दुनिया पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालने का वादा करता है।

अतीत की बात करें तो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) की यात्रा 1952 से शुरू होती है, जब भारत स्वतंत्रता के बाद अपनी सिनेमाई आवाज खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था।

भारत सरकार ने पहला IFFI मुंबई में आयोजित किया था, और इसमें 23 देशों की 40 फिल्में दिखाई गईं। IFFI 1952 में पहली बार भारत ने अपनी पहली IFFI फिल्म प्रदर्शित की थी।

अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वैश्विक सिनेमा को भारतीय तटों पर लाना। IFFI के शुरुआती संस्करण दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता सहित विभिन्न भारतीय शहरों में आयोजित किए गए थे, और यह महोत्सव व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करता था।

गोवा में IFFI द्वारा पिछले 20 वर्षों में आयोजित किये गए कार्यक्रमों ने गोवा को IFFI के लिए आधिकारिक स्थान बनाने में योगदान दिया है, क्योंकि इसकी सांस्कृतिक जीवंतता और प्राकृतिक सुंदरता का लाभ ध्यान में रखा जाता है। IFFI दुनिया भर के अन्य फिल्म समारोहों से अलग एक अनूठा समारोह है। इसे "फिल्म फेस्टिवल" के रूप में जाना जाता है।

गोवा महोत्सव'', आईएफएफआई गोवा की स्थानीय संस्कृति के साथ सहज रूप से घुल-मिल जाता है, तथा भारत के पसंदीदा पर्यटन स्थल की ओर अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करता है।

गोवा का जीवंत कला दृश्य, समुद्र तट संस्कृति और विरासत वास्तुकला उत्सव की भावना को पूरक बनाते हैं, जिससे एक आकर्षक स्थान बनता है जहाँ दुनिया के सभी कोनों से सिनेमा प्रेमी एक साझा उत्सव के लिए एकत्र हो सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सहयोग से

गोवा फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा (ईएसजी) के सहयोग से, 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया जाएगा।

गोवा में लगातार IFFI के आयोजन से राज्य को फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद मिली है। स्थानीय व्यवसाय, कलाकार और कारीगर आगंतुकों की आमद से लाभान्वित होते हैं, और यह महोत्सव क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है। नई दिल्ली में IFFI के लिए कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान, डॉ. एल. मुरुगन ने वैश्विक मंच पर महोत्सव की प्रतिष्ठित भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "IFFI न केवल भारत के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक आयोजन बन गया है, जो कान्स जैसे वैश्विक महोत्सवों के बराबर है।"

2024 में IFFI के 55वें संस्करण में 'युवा फिल्म निर्माताओं' की थीम - "भविष्य अभी है" प्रदर्शित की जाएगी। थीम हमारे देश में कालातीत और युवा प्रतिभाओं को अपनाने और रचनात्मकता के भविष्य को आकार देने में उनकी क्षमता को पहचानने के लिए कहती है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ़ टुमॉरो प्लेटफ़ॉर्म की पहल को पिछले संस्करणों में 75 से बढ़ाकर 100 युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए बढ़ाया गया है। देश भर के फिल्म स्कूलों के 400 युवा फिल्म छात्रों को IFFI में भाग लेने के लिए मंत्रालय द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है।

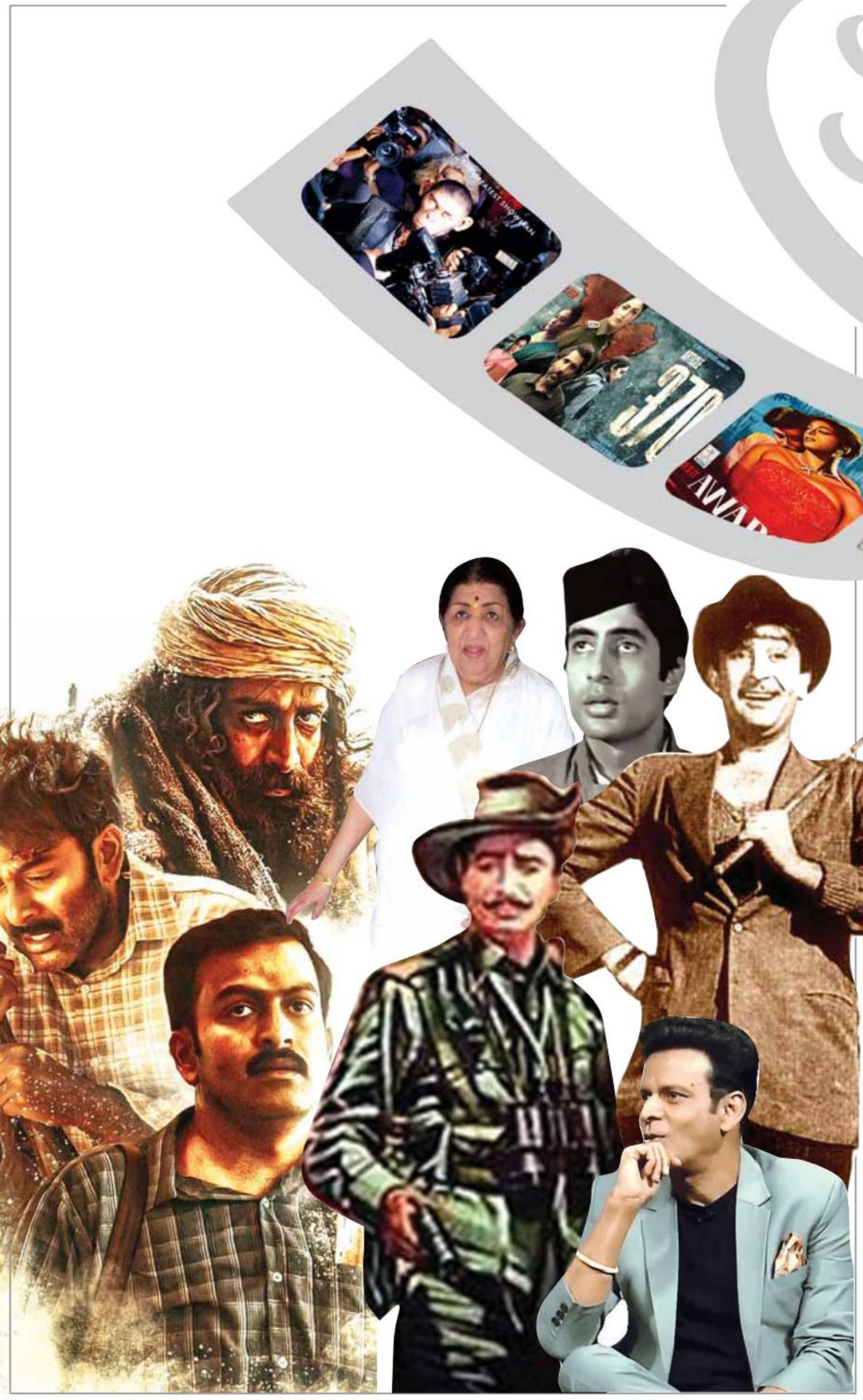

इस महोत्सव में सिनेमा जगत के दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी तथा प्रतिष्ठित करियर पर पुनर्विचार किया जाएगा। देश फोकस अनुभाग दर्शकों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जोड़ते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करेगा।

IFFI 2024 के लिए फोकस का देश ऑस्ट्रेलिया होगा। यह ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों के एक समर्पित पैकेज द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा जो महोत्सव में मजबूत उपस्थिति देगा। महोत्सव में अग्रणी ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माताओं की भागीदारी और फिल्म के लिए स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया और NFDC के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बाज़ार और ऑसफिल्म द्वारा एक शोकेस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय फिल्मांकन स्थानों और सह-निर्माणों को बढ़ावा दिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के अलावा, ब्रिटिश फिल्म संस्थान के साथ साझेदारी में, यूनाइटेड किंगडम को "संधि देश" के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश सिनेमा को सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पैकेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

अग्रणी लोगों का उत्सव मनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, उदाहरण दिए जा सकें और पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सके। हर साल की तरह, मनोरंजन उद्योग के साथ कदमताल करने वाले सिनेमा के सितारों को IFFI 2024 में पुरस्कार दिए जाएंगे।

सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाने वाला आईएफएफआई का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक रहेगा।

इसके अलावा, कार्यशालाओं, मास्टरक्लास, पैनल चर्चाओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के माध्यम से, IFFI 2024 महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के लिए एक सीखने का मंच प्रदान करेगा, जिससे एक समावेशी माहौल बनेगा सिनेमाई उत्सव और विकास के लिए स्थान।

महिला सुरक्षा और सिनेमा जैसे पैनल चर्चाओं में प्रसिद्ध पैनलिस्ट इम्तियाज अली, सुहासिनी मणिरत्नम, खुशबू सुंदर, भूमि पेडनेकर शामिल होंगे; यात्रा करने वाली कहानियां, एक पैनल जो कहानी कहने की कला का पता लगाएगा जो अपने मूल से परे यात्रा करती है, विषयों, तकनीकों और भावनात्मक कोर को संबोधित करती है जो कहानी कहने की अनुमति देती है।

दुनिया भर के विविध दर्शकों तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने वाली फिल्में

फारुख धोंडी, अन्ना सौरा के साथ, तनिष्ठा चटर्जी, वाणी त्रिपाठी टिकू और लूसी वाकर। प्रत्येक पैनल चर्चा एक नई बात होगी

उत्सव में उपस्थित सभी लोगों के लिए सीखने की एक जगह।

पैनलिस्ट डॉ. सच्चिदानंद जोशी, अमीश त्रिपाठी, भरत बाला के साथ सिनेमाई कहानी सुनाना दर्शकों के लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव होगा।

मनोज बाजपेयी, सुनील श्रीनिवासन के साथ अनदेखी को परखना; शताब्दी विशेष: एएनआर - अक्किनेनी नागेश्वर राव के जीवन और कार्यों का जश्न। यह शताब्दी विशेष महान अभिनेता और निर्माता अक्किनेनी नागेश्वर राव (एएनआर) का जश्न मनाएगा, जिनका भारतीय सिनेमा में योगदान रहा है।

अद्वितीय, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता और उनके पुत्र नागार्जुन वक्ता होंगे; मनीषा कोइराला और विक्रमादित्य मोटवानी के साथ बिग स्क्रीन से स्ट्रीमिंग तक की चर्चा; राज कपूर के जीवन और कार्यों का जश्न - 'द ग्रेटेस्ट शोमैन' रणबीर कपूर के साथ; सशक्तीकरण परिवर्तन: सिनेमा में अग्रणी महिलाएं, जिसमें महिला प्रधान हिट फिल्में देने वाली कृति सनोन और रुद्राणी चट्टोराज शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त लता मंगेशकर स्मृति वार्ता: भारत में संगीत थिएटर पर ए.आर. रहमान के साथ चर्चा होगी।

सिनेमा उद्योग के अग्रणी लोगों द्वारा मास्टरक्लास, हर साल 7 दिवसीय महोत्सव के सभी दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उतार-चढ़ाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। अनुपम खेर द्वारा आयोजित मास्टरक्लास पॉवर ऑफ फेलियर में उनकी यात्रा को साझा किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे असफलताओं ने उनके विकास और सफलता के लिए उत्प्रेरक का काम किया।

फिलिप नोयस द्वारा न्यू हॉलीवुड में सफलता कैसे पायें विषय पर एक और व्याख्यान। इन सबके अलावा, स्टीफन वूली नामक एक अंग्रेजी फिल्म निर्माता भी शामिल होंगे, जो फिल्म निर्माण और इसके चरणों पर एक मास्टरक्लास देंगे, जो मूल्यवान होगा।

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार व्यक्तिगत उत्कृष्टता को उजागर करते हैं। हाल के वर्षों में, IFFI ने उभरते सिनेमाई रुझानों को दर्शाने के लिए अपने पुरस्कारों का विस्तार किया है। भारत भर में युवा फिल्म निर्माण प्रतिभाओं को मान्यता देने के लिए इस साल सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक का एक नया पुरस्कार जोड़ा गया है।

आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक सम्मान

शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाली फिल्मों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तथा विशेष जूरी पुरस्कार उत्कृष्ट कथात्मक और तकनीकी उपलब्धियों को उजागर करता है, जो अक्सर अद्वितीय कार्यों को सुर्खियों में लाता है।

महोत्सव की नई प्रतिभाओं के प्रति प्रतिबद्धता

सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म पुरस्कार के माध्यम से चमकता है, जो बोल्ड नई आवाज़ों को प्रोत्साहित करता है, जबकि भारतीय पैनोरमा अनुभाग भारतीय सिनेमाई विविधता को बढ़ावा देता है। आधुनिक कहानी कहने के रूपों को अपनाने के लिए, IFFI ने एनीमेशन, VR और वृत्तचित्रों के लिए पुरस्कारों की शुरुआत की, साथ ही पर्दे के पीछे के लिए “फिल्म शिल्प में उत्कृष्टता” पुरस्कार भी दिया

प्रतिभा के लिए यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नॉयस को दिया जाएगा।

इस वर्ष, नई श्रेणियां - जैसे "प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग" और स्थिरता-केंद्रित पुरस्कार - सीजीआई जैसी प्रगति को सम्मानित करते हैं और वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं, जिससे आईएफएफआई को सकारात्मक बदलाव के अग्रणी महोत्सव के रूप में स्थापित किया जाता है।

स्क्रीनिंग, हमेशा की तरह, एक मुख्य आकर्षण रहेगी, जिसमें बहुप्रतीक्षित फिल्में शामिल होंगी जैसे 21 नवंबर 2024 को आईनॉक्स पंजिम में जीरो से रीस्टार्ट का विश्व प्रीमियर, 26 नवंबर 2024 को आईनॉक्स पंजिम में सौरभ शुक्ला की जब खुली किताब, 24 नवंबर 2024 को आईनॉक्स पंजिम में हजार वेला शोले पहला मानुस का एशिया प्रीमियर, 25 नवंबर 2024 को आईनॉक्स पंजिम में बोमन ईरानी द्वारा निर्देशित द मेहता बॉयज़ का एशिया प्रीमियर।

माइकल ग्रेसी की ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बेटर मैन, जो संगीत कलाकार रॉबी विलियम्स के जीवन पर एक मनोरंजक नज़र डालती है, जिसे जॉनो डेविस ने एक अभूतपूर्व मोशन-कैप्चर प्रदर्शन में एक चिम्पांजी की भूमिका निभाई है, का एशिया प्रीमियर महोत्सव के आरंभ में होगा।

55वें IFFI की ओपनिंग फीचर फिल्म का सम्मान रणदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित स्वातंत्र्य वीर सावरकर द्वारा किया जाएगा, जो एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व का सशक्त चित्रण है। इसके अलावा ओपनिंग नॉन-फीचर फिल्म हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित घर जैसा कुछ होगी।

आवारा (1951), हम दोनों (1961), देवदासु (1953), दादा साहेब फाल्के की कालिया मर्दन (1919), अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी (1969), और सीमाबद्ध (1971) सहित उनकी प्रतिष्ठित फिल्मों की पुनर्स्थापित क्लासिक्स प्रदर्शित की जाएंगी। महोत्सव में।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) 20 से 24 नवंबर तक बहुप्रतीक्षित फिल्म बाजार का आयोजन भी करेगा, जिससे गोवा दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, निर्माताओं, वितरकों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक हलचल भरा केंद्र बन जाएगा।

अपनी स्थापना के बाद से, फिल्म बाज़ार ने खुद को दक्षिण एशिया के प्रमुख फिल्म बाज़ार के रूप में स्थापित किया है, जो इस क्षेत्र से नई आवाज़ों और अद्वितीय सिनेमाई कथाओं को वैश्विक मंच पर लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

फिल्म बाज़ार अब दक्षिण एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाज़ार बन गया है।

यह दक्षिण एशियाई और विदेशी फिल्म निर्माताओं, निर्माताओं, बिक्री प्रतिनिधियों और महोत्सव कार्यक्रमकर्ताओं के बीच संभावित रचनात्मक और वित्तीय सहयोग के लिए एक बैठक स्थल के रूप में कार्य करता है। 20 से 24 नवंबर, 2024 तक IFFI 2024 में 18वां फिल्म बाज़ार गोवा के मैरियट रिज़ॉर्ट में लगेगा।

इस साल, IFFI न केवल सिनेमाई प्रदर्शन का वादा करता है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान, कलात्मक उत्सव और देश और दुनिया भर में फिल्मों के भविष्य के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से भरा एक उत्सव है। ज्ञानवर्धक बातचीत से लेकर प्रेरक मार्गदर्शन और अविस्मरणीय स्क्रीनिंग तक, IFFI 2024 उम्मीदों से बढ़कर दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है।

Machine Translated by Google

the pioneer agenda

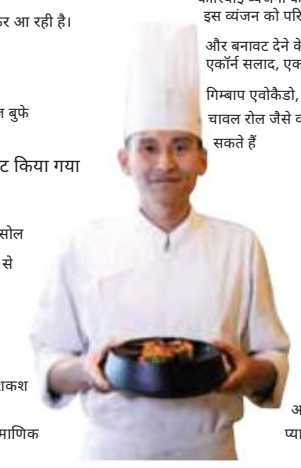

वह दक्षिण भारतीय व्यंजन

केवल इडली, डोसा और सांभर के इर्द-गिर्द घूमता है,
21

लंबे समय से चली आ रही धारणा को दूर करना

मिशेलिन स्टार शेफ सुरेश पिल्लई ने नई दिल्ली के गुड़गांव स्थित द वेस्टिन में अपने पहले पॉप-अप के साथ उत्तर भारत में पाक कला का एक अनूठा नमूना पेश किया।

यह अनुभव केरल के प्रामाणिक स्वादों का एक मिश्रण था, जिसमें शेफ पिल्लई के खास आधुनिक बदलावों और ट्विस्ट का बेहतरीन मिश्रण था। दक्षिण के मसालों की खुशबूदार महक से लेकर समुद्री खाद्य व्यंजनों की नाजुक बारीकियों तक, पॉप-अप मेन्यू दक्षिण भारत के समृद्ध गैस्ट्रोनॉमिक विरासत के स्वाद का एक उदाहरण था।

प्रसिद्ध रेस्टोरेंट शेफ पिल्लई (RCP) के सहयोग से, इस असाधारण पाक यात्रा ने खाने वालों को केरल के जीवंत स्वादों से रूबरू कराया। शेफ पिल्लई द्वारा तैयार किए गए विशेष 10-कोर्स टेस्टिंग मेन्यू के माध्यम से मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों की प्रस्तुति की गई।

इसकी शुरुआत मौसम के स्वागत पेय, आरामबम से हुई, जो थोड़ा खट्टा पेय था।

सावधानीपूर्वक तैयार किए गए शाकाहारी और मांसाहारी मेनू ने मेहमानों को सीधे केरल के हृदय में पहुंचा दिया, तथा इस क्षेत्र के पाक-कला के खजाने का सच्चा स्वाद प्रदान किया।

प्रत्येक व्यंजन को सटीकता और जुनून के साथ तैयार किया गया था, जो केरल की आत्मा को प्रदर्शित करता है

व्यंजनों की विविधता, मसालों के मिश्रण से लेकर नाजुक लेकिन मजबूत स्वाद तक।

हॉर्स डी'ओयुवर्स के लिए, मुंह में पानी लाने वाला संभरम कडुमंगा था, जिसमें केरल की गर्मियों की बटर मिल्क और अचार वाले आम को पानी पूरी में मिलाया गया था। उत्तर भारत में बैठे किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि पानी पूरी को दक्षिण भारतीय ट्विस्ट के साथ मिलाया जा सकता है, जिसने शो को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

"हमने केरल से एक मेनू बनाया

सार, उदाहरण के लिए, हमारी पानी पूरी, स्टार्टर में से एक, वास्तव में, यह एक उत्तर भारतीय पानी पूरी है, यह एक छाछ है जिसे हम केरल में आम के अचार के साथ परोसते थे।

तो हम पूरी में आम और ठंडी छाछ भरते हैं, जिसे आप आमतौर पर छाछ कहते हैं।" शेफ सुरेश पिल्लई ने बताया, जो उत्तरी क्षेत्र में अपने पहले पॉप अप को लेकर उत्साहित थे।

जब मेहमान सोच-समझकर बनाए गए हॉर्स डी'ओवर्स का लुत्फ़ उठा रहे थे, तो स्टार्टर्स ने शानदार तरीके से केंद्र में जगह बनाई, जिसका नेतृत्व पज़हम पोरी चाट ने किया। केरल से प्रेरित इस बेहतरीन व्यंजन में सुनहरे, बैटर में तले हुए केले के फ्रिटर्स थे जो बाहर से थोड़े कुरकुरे और अंदर से नरम थे, और शहद-दही के मिश्रण की बूंदों ने मिठास और मलाई को पूरी तरह से संतुलित कर दिया था।

इसके बाद, मेहमानों को फूलगोभी पोरिप्पू परोसा गया, जो केरल के समृद्ध मसालेदार स्वाद को खूबसूरती से दर्शाता है। कुरकुरी, मसालेदार फूलगोभी के फूलों को सुनहरा होने तक डीप-फ्राई किया गया और फिर थेंगा पोरिप्पू के साथ तला गया - कसा हुआ नारियल, सुगंधित करी पत्ते और मिर्च पाउडर का एक सुगंधित मिश्रण।

शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के स्टार्टर्स में बनावट और स्वाद का एक आनंददायक मिश्रण था, जिसमें फूलगोभी का कुरकुरापन मिट्टी के मसालेदार-मीठे नारियल के मिश्रण के साथ पूरी तरह से मेल खाता था।

मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल थे

शेफ सुरेश पिल्लई द्वारा स्वयं सुझाए गए व्यंजन, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो केरल की पाक कला की झलक प्रस्तुत करते हैं।

शाकाहारियों के लिए, पनीर निर्वाण था: कोमल मसालेदार

पनीर को पैन में अच्छी तरह से तला जाता है और फिर मलाईदार नारियल के दूध में धीमी आंच पर पकाया जाता है। इस डिश को अदरक, हरी मिर्च और सुगंधित करी पत्तों के मिट्टी के स्वाद के साथ और भी स्वादिष्ट बनाया गया है, जिसे पारंपरिक प्रामाणिकता के लिए केले के पत्ते में खूबसूरती से लपेटा गया है।

शाकाहारियों, मुख्य आकर्षण था
नेमीन निर्वाण, शेफ पिल्लई
प्रतिष्ठित रचना.

मुख्य पाठ्यक्रम में भी समृद्ध पेशकश की गई

केरल की पाक विरासत की झलक, जिसमें उल्ली जैसे व्यंजन शामिल हैं

थीयाल, धीमी आंच पर भुने नारियल, प्याज और इमली तथा बेबी कॉर्न वेंडाका से बनी एक गाढ़ी, स्वादिष्ट करी

मंगा मुरिंगा चारु, एक अलेप्पी शैली नारियल बेबी कॉर्न, भिंडी और कोमल ड्रमस्टिक के साथ आम की करी। कथरीकाई

थक्कली रोस्ट ने दक्षिण भारतीय व्यंजनों में तीखा और मसालेदार स्वाद लाया मसालेदार बैंगन और टमाटर के साथ भारतीय स्वाद को जीवंत करें प्याज़-टमाटर की समृद्ध रेसिपी में ग्रेवी.

इसके साथ परोसे गए व्यंजनों में नाजुक, फीतेदार किनारों वाले अप्पम शामिल थे, जो करी को सोखने के लिए एकदम उपयुक्त थे, तथा मुलायम, परतदार मालाबार नूल पोरोटा भी शामिल था, जो केरल के विविध और साहसिक स्वादों का जश्न मनाने वाले भोजन को संपूर्ण बनाता था।

मिठाई के लिए मेनू में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के मेहमानों को स्वादिष्ट व्यंजनों से प्रसन्न किया गया।

शाकाहारियों ने टेंडर का स्वाद लिया

नारियल का हलवा, एक हल्का और मुलायम व्यंजन है जो कोमल नारियल के नाजुक स्वाद और मुलायम गूदे से भरपूर है।

नारियल, कोको नटी चॉकलेट ब्राउनी के साथ, एक स्वादिष्ट अंडे रहित चॉकलेट मिठाई जो कुरकुरे नट्स और सुगंधित नारियल से समृद्ध है, जिसे मलाईदार आइसक्रीम के एक स्कूप के साथ परोसा जाता है। मांसाहारी भोजन करने वालों को पलाडा चीज़केक परोसा गया, जो एक अनूठा फ्यूजन मिठाई है जिसमें पारंपरिक केरल पलाडा (चावल के गुच्छे) स्वाद को एक कुरकुरे, कुरकुरे बेस के ऊपर रखा गया है, जो भोजन को मीठे नोट पर समाप्त करने के लिए परंपरा और परिष्कार का एक रमणीय मिश्रण पेश करता है।

शाम को हस्तनिर्मित कॉकटेल के चयन से और भी अधिक रोमांचक बना दिया गया, जिनमें से प्रत्येक मिक्सोलॉजी में कलात्मकता का प्रमाण था।

मुख्य आकर्षणों में टोकी सनटोरी व्हिस्की को सोडा वाटर और ग्रेपफ्रूट ट्विस्ट के साथ मिलाकर बनाया गया ताज़ा टोकी हाईबॉल और हरे सेब, नींबू और रेशमी अंडे के सफ़ेद झाग के साथ बनाया गया ज़ेस्टी टोकी ऑर्चर्ड सोर शामिल था। जिन के शौकीनों ने अदरक के स्वाद के साथ क्रिस्प रोकू जिन एंड टॉनिक और हिबिस्कस कॉर्डियल और फ़िज़ के साथ फ्लोरल रोकू हिबिस्कस हाईबॉल का लुत्फ़ उठाया।

व्हिस्की प्रेमियों ने सुगंधित बिटर्स के साथ बोल्ड जिम बीम ऑरेंज फैशन का आनंद लिया, जबकि लजीज हकू कारमेल एस्प्रेसो मार्टिनी, जिसमें हकू जापानी क्राफ्ट वोदका को कारमेल और एस्प्रेसो के साथ मिलाया गया था, ने कॉकटेल लाइनअप को एक शानदार समापन प्रदान किया।

शेफ सुरेश पिल्लई का द वेस्टिन गुड़गांव, नई दिल्ली में पॉप-अप एक ऐसा अनुभव था, जो दक्षिण भारतीय व्यंजनों की धारणा को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

केरल की समृद्ध पाक परंपराओं में अपने आधुनिक मोड़ के साथ, शेफ पिल्लई ने मेहमानों को एक पाक यात्रा पर ले जाया, जिसमें केरल के जीवंत स्वादों की सादगी और जटिलता दोनों का जश्न मनाया गया।

कोरियाई भोजन एक जीवंत और स्वादिष्ट व्यंजन है जो रंगों, बनावट और स्वाद के अपने अनूठे संतुलन के लिए मनाया जाता है। सदियों पुरानी परंपराओं में निहित, यह ताजा, मौसमी सामग्री पर जोर देता है, अक्सर किण्वित, गहरे, स्वादिष्ट स्वाद और पोषण संबंधी समृद्धि बनाने के लिए।

कोरियाई खाने का अनुभव अनोखा होता है, जिसमें आमतौर पर कई तरह के साइड डिश या बंचन शामिल होते हैं, जो मसालेदार किमची से लेकर नाज़ुक अचार वाली सब्ज़ियों तक होते हैं। चावल, सब्ज़ियाँ और मीट जैसे मुख्य स्टेपल को गोचुजांग (एक मसालेदार-मीठा लाल मिर्च का पेस्ट) और दोएनजांग (किण्वित सोयाबीन का पेस्ट) जैसी सामग्री के साथ कुशलता से मिलाया जाता है ताकि ऐसे व्यंजन बनाए जा सकें जो दिखने में जितने शानदार हैं, उतने ही स्वादिष्ट भी हैं। ग्रिल पर बुलगोगी की तीखी आवाज़ से लेकर बुदबुदाते जिगा स्टू की आरामदायक गर्मी तक, कोरियाई भोजन एक ऐसी संस्कृति में एक संवेदी यात्रा प्रदान करता है जो सद्भाव, संतुलन और बोल्ड, यादगार स्वादों को महत्व देती है।

नई दिल्ली में भोजन प्रेमियों के लिए एक शानदार दिन था।

कोरिया से पाककला का आनंद
नई दिल्ली को ली मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा

ने अपने बहुप्रतीक्षित कोरियन फूड फेस्टिवल के साथ कोरियाई व्यंजनों के अनूठे स्वाद का जश्न मनाया।

17 नवंबर, 2024 तक चलने वाला यह गैस्ट्रोनॉमिक इवेंट एक मनोरंजक डाइनिंग अनुभव था, जिसमें इसके 'द वन' रेस्तरां में पारंपरिक और समकालीन कोरियाई व्यंजन पेश किए गए। यह उत्सव ली मेरिडियन नई दिल्ली की एक विशेषता है।

'+1 फॉर द लीप ईयर' अभियान के अंतर्गत वार्षिक '+1 सेलिब्रेटिंग फ्लेवर्स ऑफ द ग्लोब' पहल, भारत के हृदय स्थल में विदेशी, प्रामाणिक वैश्विक स्वाद लेकर आ रही है।

कोरियाई खाद्य महोत्सव का रात्रिभोज बुफे

शेफ द्वारा सावधानीपूर्वक क्यूरेट किया गया

यंग-ह्वान जंग, शेफ डे पार्टी मैरियट एसी होटल में सोल गंगनम। दशकों से भी अधिक समय से दो पाककला विशेषज्ञता और कोरियाई व्यंजनों के प्रति गहरा जुनून,

शेफ जंग सियोल से आये हैं और पेशकश कर रहे हैं मेहमानों को अपनी मातृभूमि का प्रामाणिक स्वाद, सम्मिश्रण

पारंपरिक कोरियाई व्यंजनों को नवीन तकनीकों के साथ वैश्विक स्वाद के लिए तैयार किया गया है।

ली मेरिडियन नई दिल्ली की उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक मीना भाटिया ने कहा, "हम इस उत्सव के माध्यम से कोरिया के विविध और स्वादिष्ट व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए रोमांचित हैं।" "यह कार्यक्रम हमारे +1 सेलिब्रेटिंग फ्लेवर्स ऑफ द ग्लोब पहल के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो हमारे वार्षिक '+1 फॉर द लीप ईयर' पहल का मुख्य आकर्षण है, और हमें विश्वास है कि यह हमारे मेहमानों को वास्तव में अविस्मरणीय भोजन अनुभव प्रदान करेगा," उन्होंने कहा। मेनू में पारंपरिक कोरियाई व्यंजनों की एक श्रृंखला दिखाई गई, जो इस व्यंजन को परिभाषित करने वाले विशिष्ट स्वाद और बनावट देने के लिए तैयार की गई थी। मेहमान एकॉर्न सलाद, एक ताज़ा और पौष्टिक व्यंजन; गिम्बाप एवोकैडो, कोरिया के प्रिय समुद्री शैवाल चावल रोल जैसे व्यंजनों का स्वाद चखने की उम्मीद कर सकते हैं

आधुनिक मोड़; वसंत प्याज पैनकेक, एक स्वादिष्ट व्यंजन जो कि

शेयरिंग; मसालेदार और आरामदायक स्टिर-फ्राइड राइस केक (टेओकबोक्की); और ठंडा ठंडा समुद्री भोजन सलाद, जो दिल्ली की गर्म शामों के लिए एकदम सही है। बुफे स्प्रेड पर प्रत्येक डिश को शेफ जंग द्वारा कोरिया के प्रामाणिक स्वाद को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।

शेफ यंग-ह्वान जंग ने कहा, "मैं कोरिया के जीवंत स्वादों को ली मेरिडियन नई दिल्ली में लाने के लिए उत्साहित हूं।" "इस उत्सव के माध्यम से, हमारा लक्ष्य मेहमानों को कोरियाई व्यंजनों की विविध रेंज से परिचित कराना है, जिसमें क्लासिक आरामदायक भोजन से लेकर अभिनव पाक कृतियाँ शामिल हैं," वे मुस्कुराते हुए कहते हैं।

यह अनोखा डाइनिंग अनुभव सिर्फ़ खाने से कहीं आगे निकल गया - इसने मेहमानों को कोरिया की समृद्ध पाक विरासत की सैर पर जाने के लिए आमंत्रित किया। कोरियाई व्यंजनों के लिए मशहूर मसालेदार और नमकीन स्वाद से लेकर पारंपरिक व्यंजनों में नए-नए बदलाव तक, यह उत्सव कोरियाई संस्कृति और स्वादों में एक गहरी और स्वादिष्ट डुबकी प्रदान करता है।

मैं मेरे लिए समीक्षा लिखने से पहले कई बार एक रेस्तरां में जाना दुर्लभ है, लेकिन

पोइज़, भोजनालय की दुनिया में एक नया खूबसूरत स्थान, जिसने मुझे तीन बार लौटने पर मजबूर किया

इसके सार को पूरी तरह से पकड़ें।
पोइज़ में कलात्मक, विस्तृत इंटीरियर है, जिसमें एक विशाल आंगन के साथ सुरुचिपूर्ण इनडोर सीटिंग का मिश्रण है, जिसमें अपना बार और एक आकर्षक खुला भोजन क्षेत्र है। जबकि इस आकार के कई रेस्तरां नाइटलाइफ़ भीड़ को मुख्य रूप से सेवा प्रदान करते हैं, पोइज़ एक आदर्श संतुलन बनाता है: सामाजिक समूह के लिए आविष्कारशील कॉकटेल के साथ एक अच्छी तरह से क्यूरेट किया गया बार चयन, और एक मेनू जो परिवारों और पार्टी जाने वालों को समान रूप से प्रसन्न करता है।

कुछ व्यंजन मेरे पसंदीदा व्यंजन बन गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ खास होता है। लीची चाट, एक थाई-प्रेरित रचना है, जिसे अवश्य आज़माना चाहिए। लीची और एवोकाडो के टुकड़े कुरकुरे चावल के पफ बेस के ऊपर रखे जाते हैं, साथ में स्वादिष्ट नाम जिम सॉस - एक बार चबाने के बाद आप रुकना नहीं चाहेंगे। चिकन चिली डिम सम में एक नाज़ुक आवरण होता है और यह साथ में दिए गए सॉस के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। एक और ए बेहतरीन व्यंजन है ताइवानी मशरूम, जो कुरकुरे-लेपित होते हैं और अचार वाली मिर्च के साथ परोसे जाते हैं

और एक मीठी-खट्टी चटनी, जिसमें अतिरिक्त स्वाद के लिए कुरकुरी मूंगफली डाली गई है।

हर व्यंजन में खामियाँ नहीं थीं। नाचोस मेरे स्वाद के हिसाब से थोड़े ज़्यादा नमकीन थे। हालाँकि, उनके वैश्विक मेनू में मौजूद रेमन ने अपने समृद्ध, परतदार स्वादों से इसकी भरपाई कर दी। यह एक भरपूर हिस्सा है, जो दिल खोलकर खाने या दोस्तों के साथ साझा करने के लिए एकदम सही है।

मेरे साथियों ने सुशी के साथ-साथ लैम्ब अडाना कबाब का भी भरपूर आनंद लिया।

जबकि पोइज़ में भारतीय व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, मैंने स्वयं को वैश्विक पेशकश की ओर आकर्षित पाया, जिसमें उनके विशेषज्ञतापूर्वक तैयार किया गया नेपल्स पिज्जा भी शामिल था।

बेल्जियन नुटेला चॉकलेट के बिना यहाँ का भोजन अधूरा रहेगा। यह मिठाई न केवल स्वाद में बेहतरीन है बल्कि प्रस्तुति में भी प्रभावशाली है। चिकनी बेल्जियन चॉकलेट और नुटेला की मिठास को ब्लूबेरी के साथ चतुराई से संतुलित किया गया है

और हेज़लनट्स, एक आदर्श समापन बनाते हैं।

इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए पोइज़ एक यात्रा योग्य स्थान है।

रेटिंग: (5 में से)
भोजन: 4.25
माहौल: 4.25 सेवा: 4.0 पेय: 4.0 कुल मिलाकर: 4.25

पता: पोइज़, द्वितीय तल, एआईपीएल जॉय स्ट्रीट, सेक्टर 66, गुरुग्राम

Machine Translated by Google

जब तूफ़ान आता है, तो क्या बुरा होता है: ख़तरा या ख़तरे का डर? मुझे हक़ीकत बताइए, ख़तरा ही।

विंसेंट वैन गाग

लाइव एक्सचेंज वायदा और विकल्प महाराष्ट्र चुनाव में

टी इस सप्ताह महाराष्ट्र के मतदाताओं के पास लोकतंत्र के साथ एक तारीख है। यह फैसला राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा क्योंकि इसमें राजनेताओं और पार्टियों पर समाधि-लेखों और श्रद्धांजलियों की एक श्रृंखला सामने आएगी।

महाराष्ट्र लोकसभा में सीटों के मापदंडों और इसके सकल घरेलू उत्पाद के आकार से परे भी मायने रखता है। यह सॉफ्ट पावर और हार्ड कैश का केंद्र है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र ने राजनीतिक उद्यम पूंजीवाद की प्रक्रिया को उजागर किया है। सिनेमाई दुनिया की नकल करते हुए, राज्य में राजनीतिक शासन एकल स्टारर से मल्टी-स्टारर की ओर बढ़ गया है। राज्य की पार्टियाँ इस कहावत को मान्य करती हैं कि 'राजनीति संभव की कला है'।

महाराष्ट्र ने राजनीतिक मुहावरे को डिजाइन और पुनः डिजाइन किया है - यह एक तरह से ट्रेंड-सेटर रहा है। 1970 के दशक में, शरद पवार ने राजनीतिक चपलता को परिभाषित करते हुए एक दर्जन से अधिक पार्टियाँ एक साथ आईं।

1995 में बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन ने युद्ध में लूट का माल साझा करने का खाका तैयार किया था। 1999 में, तलाकशुदा एनसीपी और कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए फिर से हाथ मिला लिया और 2019 से दोनों पार्टियों ने राजनीतिक निष्ठा की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया है।

तीसरी आँख
शंकर अय्यर
के लेखक सुरक्षा पूर्ण गणतंत्र, आधार: का ए बॉयोमीट्रिक इतिहास भारत का 12 अंक क्रांति, और आकस्मिक भारत
(shankkar.aiyar@gmail.com)

एक तरह से, इस सप्ताह राज्य के मतदाताओं के पास लोकतंत्र के साथ एक अंधी तारीख है। आखिरकार, पिछले पांच सालों में, सत्ता का मार्ग ईवीएम में नहीं, बल्कि राजनीतिक स्टॉक एक्सचेंज में तैयार किया गया था। शब्दकोश में वायदा को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है जो खरीदार को एक निर्दिष्ट तिथि पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करता है, जबकि विकल्प खरीदार को अधिकार देता है लेकिन संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए कोई बाध्यता नहीं डालता है। सभी दांव टेबल पर हैं। महाराष्ट्र वास्तव में एक जीवंत प्रयोगशाला है, संभावित विलय और सुविधाजनक अधिग्रहण के लिए वायदा और विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक खुला राजनीतिक एक्सचेंज है।

निवेश का सूचकांक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के गणित पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से, दोनों गठबंधन-महायुति और महाविकास अघाड़ी-दावा करते हैं कि वे स्पष्ट बहुमत हासिल करेंगे। हालांकि, शांत आम सहमति से त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है, जिस स्थिति में 'प्रभाव प्रतिस्थापन' - आईपीएल से एक मुहावरा उधार लेते हुए-खेल में आएंगे। 2,000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों का बड़ा क्षेत्र चुनने के लिए विकल्प प्रदान करता है। 1995 की तरह, क्षेत्रीय क्षत्रपों ने प्रतिस्पर्धा की संभावनाओं को कम करने के लिए गठबंधनों के भीतर प्रॉक्सी को बढ़ावा दिया है। पार्टी बदलने वालों की भीड़ के कारण होने वाली अराजकता प्रतीकों की उलझन या जिसे ट्रम्प-पेट्स की लड़ाई कहा जाता है, के कारण और बढ़ जाती है, जिसमें 163 निर्दलीय उम्मीदवार ट्रम्पेट के प्रतीक के साथ और एनसीपी उम्मीदवार ट्रम्पेटर के प्रतीक पर लड़ रहे हैं।

हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्पष्ट बहुमत गठबंधनों को नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री पद की लड़ाई और प्रासंगिकता की तलाश के लिए गठबंधन के भीतर पार्टियों को पर्याप्त सीटें जीतनी होंगी और उम्मीद करनी होगी या सुनिश्चित करना होगा कि अन्य घटक बहुत अच्छा प्रदर्शन न करें। दूरसंचार की तरह, मतदाता संपर्क रोमिंग व्यवस्था की प्रभावशीलता, गठबंधनों में वोटों के हस्तांतरण पर निर्भर करता है - और अजीत पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना को कमजोर माना जाता है। भाजपा के लिए लगभग 100 सीटों का आंकड़ा एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकता है, 50 से कम सीटें उद्धव शिवसेना के लिए तस्वीर बदल सकती हैं, और भाजपा और शिंदे सेना के बीच 130 का आंकड़ा अजीत पवार को परेशान करेगा।

पार्टियों की स्ट्राइक रेट राजनीति के भूगोल पर निर्भर करती है - मुख्य रूप से, कोटा कॉरिडोर। सामाजिक इंजीनियरिंग के सभी प्रयास सीमाओं के क़ानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रभावी रूप से, किसी एक वर्ग को लुभाने के प्रयास - उदाहरण के लिए, माली, धनगर और वंजारा समुदायों में ओबीसी एकीकरण के लिए खेल - ने मराठवाड़ा में मराठों और उत्तरी महाराष्ट्र में आदिवासियों के बीच गुस्सा और प्रति-एकीकरण को जन्म दिया है।

दोनों गठबंधनों के लिए जीत एक ऐसा खेल है जिसमें हर पहलू पर ध्यान देना होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार, उत्तर महाराष्ट्र और शहरी इलाकों में भाजपा और ठाणे और यहां तक कि कोंकण में शिंदे सेना का वर्चस्व है। मुख्य बात यह होगी कि कांग्रेस 35 से अधिक सीटों पर कैसा प्रदर्शन करती है, जहां उसका मुकाबला भाजपा से है, खासकर विदर्भ में, और उद्धव शिवसेना राज्य भर में 53 सीटों पर शिंदे शिवसेना का आमना-सामना करती है, खासकर मुंबई और कोंकण में।

वास्तव में, इसका परिणाम मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में लड़ी जा रही बड़ी लड़ाइयों से तय होगा - ये तीन क्षेत्र 'असंतोष के क्षेत्र' का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मराठवाड़ा और विदर्भ को ही लें। जातिगत आरक्षण के मुद्दे से इतर उपेक्षा का इतिहास भी है - 1983 में वीएम दांडेकर के नेतृत्व वाली तथ्यान्वेषी समिति द्वारा पहली बार पहचाने गए विकास के पिछड़ेपन का मुद्दा आज भी बना हुआ है और यह प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय असमानता के रूप में प्रकट होता है।

अब जाति के नक्शे पर उपेक्षा, कृषि संकट और किसानों के बीच गुस्से के मुद्दे हावी हो गए हैं। मराठवाड़ा और विदुरभ में, ऋण और इनपुट तक पहुंच की समस्याओं का सामना कर रहे किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र में, निर्यात के लिए निर्धारित उत्पादों पर नीतियों में लगातार बदलाव के कारण, फसल का मुद्रीकरण करना चुनौती है।

खेल की स्थिति युद्ध के कोहरे में ढकी हुई है और 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से इसकी रूपरेखा तैयार होती है। पहली नज़र में, महायुति को महा विकास अघाड़ी ने मात दी, जिसने 48 संसदीय सीटों में से 30 पर जीत हासिल की। बारीक विवरण बताते हैं कि मुकाबला ज़्यादा कड़ा था- एमवीए ने 153 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की, जबकि महायुति ने 127 पर बढ़त हासिल की। सवाल यह है कि क्या शिंदे शासन द्वारा शुरू की गई लड़की बहिन योजना के नेतृत्व में लोकलुभावनवाद का पुल और महायुति की चुनाव प्रबंधन क्षमताएँ आर्थिक-चिंता और राजनीतिक गुस्से को मात दे सकती हैं।

गांधी त्रिमूर्ति बनाम सोलो मोदी

सत्ता और राजनीति
प्रभु चावला
prabhchawla@new Indianexpress.com
उन्हें X पर फॉलो करें @PrabhuChawla

पी संसद, जहां संख्या बल का खेल जीतता है, दोहरी मार झेलने वाली पार्टी है। इस बार कांग्रेस को तिहरी मार झेलनी पड़ेगी, जब प्रियंका गांधी दक्षिण भारत से सांसद के रूप में लोकसभा में प्रवेश करेंगी। संसदीय इतिहास में पहली बार पार्टी की पवित्र त्रिमूर्ति अपने वफादारों पर राज करेगी: मातृ परिवार सोनिया गांधी और उनके उद्दाम पुत्र राहुल और प्रियंका। एक पूरा परिवार सत्ता में अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है, जो आमतौर पर राजशाही या तानाशाही में पाया जाता है।

इस बार, लोकतंत्र में इस अनोखी तिकड़ी की केवल एक ही भूमिका है: संसद में नरेंद्र मोदी की भाजपा से मुकाबला करना।

वैसे तो सांसदों के परिवार बहुत हैं, लेकिन गांधी परिवार विरासत की संस्था है, जो उनकी पार्टी का राजनीतिक चेहरा और वैचारिक आत्मा है। इसका संगठनात्मक पदानुक्रम प्रतीकात्मक है, तीनों गांधी परिवार के शब्द अलिखित कानून हैं। पार्टी के डरपोक नेताओं के बीच मौजूदा चर्चा में तीन दिग्गजों की विधायी भूमिका पर चर्चा हो रही है।

उदाहरण के तौर पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक गांधी की एक स्पष्ट भूमिका होगी जो उनकी भूमिका और शासन को परिभाषित करेगी।

● संत सोनिया: निजी त्रासदी और पेशेवर दीर्घायु के कारण संत घोषित की गई सोनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार मौन रहना है। वह रोज़मर्रा की राजनीति से दूर रहेंगी।

77 वर्षीय अभिनेत्री पिछले 26 वर्षों से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और खुद को भाजपा और मोदी के खिलाफ जोन ऑफ आर्क के रूप में पेश कर रही हैं। वह गैर-भाजपा दलों को एक साथ रखती हैं, बिना आपसी व्यक्तिगत हमले किए, जैसा कि कुछ कांग्रेस नेता करते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल, दिल्ली और केरल के स्थानीय नेता ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पिनाराई विजयन के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बदनामी करना उनकी आदत नहीं है।

उनकी कथित तटस्थता और संयमशीलता के कारण, यूपीए और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष के रूप में उनकी स्वीकार्यता सर्वोच्च है। उनका स्तुति-चित्रण प्रभामंडल 2004 में विपक्ष को एकजुट रखने के लिए प्रधानमंत्री पद से इनकार करने और 16-पार्टी यूपीए गठबंधन स्थापित करने से उत्पन्न हुआ है जिसने एक दशक तक देश पर शासन किया।

मोदी सरकार के बाद उन्होंने खुद को एक सुविधाकर्ता और समस्या का रामबाण समाधान तक सीमित कर लिया है। लोकसभा सत्र में उनका मानवीय पक्ष स्पष्ट रूप से दिखा, जब उनके नाराज सहयोगी सदन के वेल में आ गए, हालांकि कांग्रेस के प्रमुख सांसद शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम अपनी सीटों पर बैठे रहे। डीएमके सांसदों ने शिकायत की।

सौरव रॉय

उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, "मैं सदन के वेल में आऊंगी।" थरूर और कार्ति के साथ यह उनकी प्रसिद्धि की पहली यात्रा थी।

संत शांत शांति रक्षक होते हैं, लेकिन वे योद्धा भी होते हैं। संसद के पिछले सत्र के दौरान पार्टी की बैठक में उन्होंने घोषणा की, "अब संसद को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता और न ही दबाया जाना चाहिए, जैसा कि पिछले एक दशक से किया जा रहा है। अब सत्ताधारी प्रतिष्ठान के हुक्म को संसद को बाधित करने, मनमाने ढंग से सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने या उचित और उचित विचार-विमर्श और बहस के बिना कानून पारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब संसदीय समितियों को अनदेखा या दरकिनार नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए, जैसा कि 2014 से किया जा रहा है। अब संसद को दबाया और दबाया नहीं जाएगा, जैसा कि पिछले 10 सालों में किया गया है।"

1998 में जब वे सक्रिय राजनीति में शामिल हुईं, तो उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की - तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को पद से हटाकर स्वयं कुर्सी संभाल ली।

उनकी सक्रिय भागीदारी तो नजर नहीं आएगी, लेकिन पार्टी की मार्गदर्शक और अपने बच्चों की मां के रूप में उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति नजर आएगी।

● कट्टरपंथी राहुल: 54 वर्षीय पांच-सांसद बनने के बाद से ही वे खादी की कई टोपियाँ पहनते हैं। प्रमाणित स्कूबा डाइवर, पार्टी के पूर्व महासचिव, कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तथा अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल भारत के लिए एक क्रांतिकारी आर्थिक और सामाजिक मॉडल की वकालत करने वाले एक दंगा-फसाद करने वाले व्यक्ति हैं। वे लगातार जाति-आधारित नीति निर्माण और व्यापार तथा वाणिज्य के एकाधिकार को प्रतिबंधित करने पर अड़े रहे हैं।

वे कांग्रेस के पहले नेता हैं जिन्होंने पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक भारत की दो मैराथन पदयात्राएँ की हैं। इतिहास से एक पन्ना उठाते हुए जब नेहरू और इंदिरा पर टाटा-बिड़ला राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था, राहुल ने मोदी सरकार पर अंबानी-अडानी धुरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए नारे को फिर से दोहराया। हाल ही में अमेरिका में नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया, "भारत के शीर्ष 200 व्यवसायों में से लगभग 90 प्रतिशत भारत की आबादी के स्वामित्व में नहीं हैं। देश की सर्वोच्च अदालतों में भारत के 90 प्रतिशत लोगों की लगभग कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया में, निचली जातियों, ओबीसी, दलितों की भागीदारी शून्य है।"

कांग्रेस की वेबसाइट पर उनके विज़न का विज्ञापन इस प्रकार किया गया है: "राहुल गांधी का दृढ़ विश्वास है कि सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए और उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। उनका मानना है कि नीति निर्माण में संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, इससे बढ़ती आर्थिक खाई को पाटने में मदद मिलनी चाहिए, इसे भारत के किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें सुविधाएँ देनी चाहिए।"

जब तक उनकी मां यूपीए अध्यक्ष हैं, राहुल गठबंधन बनाने से दूर रहेंगे। हालांकि, राहुल कांग्रेस में उनकी पसंद और दर्शन के अनुयायी भरे हुए हैं। विपक्ष के नेता के रूप में, वह अपने भड़काऊ राजनीतिक दर्शन के साथ और भी आक्रामक होने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनके सलाहकारों ने विपक्ष के नेता के रूप में उनके चार साल के कार्यकाल के लिए पहले ही रोडमैप तैयार कर लिया है।

● जुझारू प्रियंका: 52 वर्षीय मां और विपश्यना साधिका वायनाड से निर्वाचित होने के बाद पहली बार लोकसभा में प्रवेश करेंगी, यह सीट राहुल ने खाली की है और केरल से उनके लिए सुरक्षित लॉन्चपैड है। अपनी मां की राजनीतिक चेतना के रक्षक के रूप में पेश की जाने वाली, गांधी पार्टी का नरम चेहरा होंगी। कांग्रेस उन्हें उनकी मां के नाम पर महिला छवि के रूप में प्रचारित करेगी।

अभी तक प्रियंका किसी भी गुट से जुड़ने से बचती रही हैं। उनका मुख्य काम मोदी पर राहुल के हमलों को बढ़ाना है क्योंकि वह अपने भाई का बचाव करने या मोदी पर हमला करने में बहुत आक्रामक हैं। जब मोदी ने राहुल को 'शाह-जादा' कहा तो उन्होंने गुजरात में एक चुनावी रैली में पलटवार करते हुए कहा, "वे मेरे भाई को शाहजादा कहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कैसे यह शाहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर पैदल चलकर आपकी समस्याएं सुनने आया... वह मेरे बहनों, भाइयों, किसानों और मजदूरों से मिला और उनसे पूछा कि उन्हें क्या समस्याएं हैं... दूसरी तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी हैं, जो महल में रहते हैं। क्या आपने उन्हें टेलीविजन पर देखा है... उनके चेहरे पर धूल का एक कण भी नहीं दिखता... वे आपकी समस्याओं को कैसे समझ सकते हैं?"

उन्हें भले ही विपक्ष की अगली पंक्ति में स्थान न मिले, लेकिन उनका उद्देश्य सदन में अपने भाई द्वारा दिए गए संदेशों और उपदेशों को प्रचारित करना होगा।

इस परिवार ने लुटियन के दिग्गजों के रूप में अपनी स्थिति बना ली है, तथा चुनावी और कानूनी युद्ध के मैदानों पर राजनीतिक रूप से बदनाम हो चुका है।

राजधानी के पूर्व औपनिवेशिक हृदय के स्वास्थ्यप्रद स्थान उनके वंश, पार्टियों, वार्ताओं, राजनीतिक झगड़ों और विद्रोहों का खेल-मैदान हैं। मोदी की तरह उनके पास शहर में अपना घर नहीं है, लेकिन वे सरकार द्वारा आवंटित आलीशान घरों में रहते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके घातक द्वेष के कारण उन्हें दशकों तक चले गांधी-मोदी गतिरोध के दौरान अपने सरकारी आवास से हाथ धोना पड़ा।

मोदी ने शब्दों की जंग छेड़ी है और तीनों ताकतवरों के खिलाफ कदम उठाए हैं। साथ ही, संसद में एकमात्र मोदी के खिलाफ तिहरा प्रहार होगा।

विचारधारा बनाम वैकल्पिक विचारधारा का मुद्दा अब पुराना हो चुका है; अब यह एक के विरुद्ध तीन का मुद्दा है।

सुविधा की पर्यावरणीय लागत

राय
अनुराधा गोयल
इंडीटेल्स के लेखक और संस्थापक
उन्हें X @anuradhagoyal पर फॉलो करें

हे विश्वविद्यालय परिसर में सुबह की सैर के दौरान, जहां मैं एक स्कॉलर-इन-रेजिडेंस हूं, मैंने शुरू में हर जगह कचरे के ढेर देखे।

यह हमारे समय के सबसे बड़े नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला सबसे पुराना जीवित शहर है; इसलिए ढेर निराशाजनक थे।

मीडिया ने हमें यह विश्वास दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है कि शहर साफ हो गया है, जिससे मेरी निराशा और बढ़ गई है।

अगले कुछ दिनों में मैंने सफाई कर्मचारियों को सड़क किनारे जमा हुए कचरे को अपने ट्रकों में भरते देखा।

ट्रक कुछ ही समय में भर जाते थे और सड़कों पर बचा हुआ कचरा छोड़ जाते थे। लगातार निरीक्षण करने से मुझे एहसास हुआ कि कचरे की मात्रा की एक सीमा होती है जिसे उठाया और संसाधित किया जा सकता है।

एक सुबह, मैं इकट्ठा किए जा रहे कचरे के पास खड़ा था, यह देखने के लिए कि इसमें किसका योगदान है। भारत भर में मेरी यात्राओं ने मुझे बताया कि पानी की बोतलें और चिप्स के पैकेट सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। इसलिए, मैंने उनकी तलाश की, लेकिन वे बहुत कम प्रतिशत में ही मिले। सबसे बड़े दोषी डिस्पोजेबल कटलरी, खास तौर पर डिलीवरी पैकेजिंग के साथ खाना डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक ट्रे। हर दिन इनकी ढेरियाँ बढ़ती जा रही हैं - शायद हॉस्टल और होस्ट-एड इवेंट से।

सबसे निराशाजनक बात यह थी कि ये प्लास्टिक की ट्रे 60-70 प्रतिशत भरी हुई थीं। हां, ऑर्डर किया गया भोजन मानक मात्रा में, मानक प्लेट में, बिना सोचे-समझे पकाया और पैक किया गया है। मानक मूल्य निर्धारण के युग में उपभोक्ता की भूख की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे देश में जहां हमारे शास्त्र हमें अन्न या भोजन को ब्रह्म या परम देवता बताते हैं, वहां कूड़े के ढेर में इतना पका हुआ भोजन देखना दुखद है।

बचपन में हमें भोजन और भोजन को हमारी थाली में परोसने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाया गया था; लेकिन ऐसा लगता है कि हमने भोजन और डिलीवरी एप्स के युद्धक्षेत्र में यह बात खो दी है।

फिर हर सड़क किनारे चाय की दुकान, खाने की दुकान और यहां तक कि घर पर होने वाली पार्टियों में भी डिस्पोजेबल गिलास होते हैं। इन पतले प्लास्टिक के गिलासों की सुविधा और कम कीमत के कारण ये सर्वत्र उपलब्ध हैं।

जब भी मैं रिफिल मांगता हूं, तो वे नया दे देते हैं। दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहने पर वे हंसते हैं और कहते हैं, "नया इस्तेमाल करो-इसकी कीमत मेरी होगी, तुम्हारी नहीं।" मैंने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की है। जवाब: "मैं समझता हूं, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है।"

यह गलत धारणा कि प्लास्टिक के कप और तथाकथित रिसाइकिलेबल प्लेट में प्लास्टिक नहीं होता, अपनी भूमिका निभाता है। मैं कुछ ग्रीन इन्फ्लुएंसरों को जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हुए देखता हूं, लेकिन इनका निर्माण करने वाला लघु उद्योग इन सभी अभियानों से बहुत आगे है। उनकी पहुंच बहुत बड़ी है और, ज़ाहिर है, भारी मांग।

ग्रामीण इलाकों में यह हथियार गुटखा और खैनी की थैलियों के रूप में मिलता है।

हमारी सुविधाओं की वजह से पर्यावरण और स्वच्छता पर होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है। मेरी राय में, कचरा प्रबंधन या रीसाइकिलिंग ही एकमात्र समाधान नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है।

हमें अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। हाँ, कचरे को अलग-अलग करने से कुछ हद तक मदद मिल सकती है; लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो, इस पर शायद ही अमल हो रहा है क्योंकि एक भी व्यक्ति कचरे को कचरे में मिला देता है।

उपभोक्ता सुविधा हमारे शहरी कचरे में भारी वृद्धि कर रही है। आज कूड़े के ढेर डिस्पोजेबल खाद्य कंटेनरों से भरे हुए हैं। पुनर्चक्रण ही एकमात्र समाधान नहीं है। हमें अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को भी कम करने की आवश्यकता है

एक समूह इन प्रयासों को पटरी से उतार सकता है।

हमें, नागरिकों के रूप में, अपनी खपत को इस तरह कम करने की आवश्यकता है कि प्रति व्यक्ति उत्पन्न होने वाला कुल अपशिष्ट कम हो जाए।

क्या हमें हर छोटी-बड़ी चीज आखिरी मिनट में ऑर्डर करनी चाहिए, क्योंकि कोई 10 मिनट में डिलीवरी करने को तैयार है? क्या हमें बड़ी मात्रा में खाना ऑर्डर करना चाहिए, जबकि औसत खपत अक्सर एक मानक ट्रे से 50 प्रतिशत होती है? क्या रेस्तरां छोटे हिस्से डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें कम मात्रा में खाना परोसा जा सके? क्या हम उन लोगों के लिए ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकते हैं जो ज़्यादा भूख रखते हैं? क्या हम उस पूरी खाद्य श्रृंखला के बारे में सोच सकते हैं जो भोजन को हमारे पास लाती है और भोजन का सम्मान करती है?

मैं जानता हूँ कि कई गैर सरकारी संगठन हैं जो रेस्तरां से बचा हुआ खाना बाँटते हैं। वे भी खाने की थालियों में रखे आधे खाए हुए बचे हुए खाने के साथ कुछ नहीं कर सकते।

आवारा पशु तो इन्हें खाते ही हैं, साथ ही वे भी प्लास्टिक खा लेते हैं और कचरा सड़क पर फैला देते हैं।

मैं अक्सर टैक्सी ड्राइवरों को अपनी खिड़की से बाहर थूकते हुए देखता हूँ। वे रैपर फेंकने से पहले दो बार नहीं सोचते। आने वाले पर्यटकों को यह संदेश दिया जाता है कि इस जगह पर कहीं भी कूड़ा फेंकना ठीक है। अगर वे जिम्मेदारी से निपटारा करें, तो कई पर्यटक भी ऐसा ही करेंगे। यही कारण है कि हम भारतीय सिंगापुर और दुबई जैसी जगहों पर अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा या बुरा व्यवहार आसानी से लोगों पर हावी हो जाता है। इसका बीज स्थानीय लोगों से आता है।

भोजन की बर्बादी को कम करना एक पर्यावरणीय मुद्दे के साथ-साथ एक सांस्कृतिक मुद्दा भी है।

हमें भोजन के प्रति अपने उस सम्मान को वापस लाना होगा, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि एक भी दाना बर्बाद न हो। बाहर खाना, घर पर ऑर्डर करना और मानक मूल्य पर मानक मात्रा में खाना बर्बादी को बढ़ाता है। घर का खाना ज़्यादातर ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है; बर्बाद होने पर भी, मात्रा बहुत कम होती है।

क्या खाद्य एवं वितरण उद्योग को अपशिष्ट निपटान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए?

बिल्कुल। उन्हें भोजन के हिस्सों को लेकर कुछ नया करने की जरूरत है और बर्बादी को कम से कम करना होगा। अगर हम स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर भोजन की बर्बादी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो हम जल्द ही बदबूदार कचरे के ढेर से घिर जाएंगे।

QUOTE CORNER

फ्रांस के तथाकथित विदेशी क्षेत्रों में अपराध हाल ही में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों का उल्लेख किए बिना पूरे नहीं होंगे। राष्ट्रपति [इमैनुएल] मैक्रोन के शासन ने न्यू कैलेडोनिया में कनक लोगों के वैध विरोध प्रदर्शनों के दौरान 13 लोगों की हत्या कर दी और 169 को घायल कर दिया।

अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, प्रशांत द्वीप देशों के प्रतिनिधियों की जय-जयकार के बीच अज़रबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे COP29 सम्मेलन में

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात सड़कों पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। अगर अधिकारी कुछ समय तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाया कि किसी इमारत को सिर्फ इसलिए गिराना गैरकानूनी है क्योंकि उसका मालिकाना हक या कब्जा किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिस पर अपराध का आरोप है।

उन्होंने अमेरिका में इतना समय बिताया है कि मुझे उम्मीद थी कि आव्रजन संबंधी आंकड़ों में उनका नाम शामिल होगा।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संसद में डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशंसक निगेल फरेज से बात की

MAILBAG WRITE TO letters@newindianexpress.com

आरएनजी का योगदान

संदर्भ: पत्रकारों को साहसी होना चाहिए, प्रमुख चिन्मय मिशन कहते हैं (16 नवंबर) ऐसे समय में जब तथ्य उलझे हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका जैसे दिग्गजों द्वारा दिखाया गया मार्ग अनुकरणीय है। लेकिन आज के पोस्ट-ट्रुथ युग में, कोई भी राक्षसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी झूठ फैला सकता है। सरकारें जो कभी सवाल पूछना पसंद नहीं करती हैं, वे अपने एकतरफा बयानों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल को अपनाती हैं और प्रिंट मीडिया को अनदेखा करती हैं। इस 'पत्रकारिता जलवायु परिवर्तन' के कारण प्रिंट तेजी से खत्म हो रहा है। सत्य-कथन में आरएनजी का योगदान अभूतपूर्व था।

वरुघीस चेरुकट्टू थॉमस, कुट्टपुझा

मूक अनुयायी

रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान पर रोचक और विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद, जिससे हमें प्रत्यक्षदर्शी होने का एहसास हुआ। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। नीरजा चौधरी और सांत्वना भट्ट को व्यक्तिगत रूप से हार्दिक बधाई-भारतीय महिला प्रेस कोर की यादें संग्रहित करने के लिए धन्यवाद। कृपया याद रखें कि आपके कई मूक अनुयायी हैं।

जे भाग्यलक्ष्मी, ईमेल

मानवीय कमज़ोरियाँ

संदर्भ: कमजोरियाँ और क्या है: कॉम-ऑल अंधविश्वास मोदी के बीच सोमवार को हुई बैठक प्रधानमंत्री (16 नवंबर) नीरजा चौधरी को बधाई, जिन्होंने ऐसी अंदरूनी जानकारी हम तक पहुंचाई। संपादक सांत्वना भट्टाचार्य ने बहुत सही कहा: "पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है।" कुछ फैसलों और उन्हें लेने के तरीके को पढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आखिरकार वे भी इंसान ही हैं।

अमरथिया के, धर्मपुरी

चमकता सितारा

संदर्भ: की खुशबू गिरा हुआ सितारे: के मुश्किल समय और प्यार (16 नवंबर)। सच में, साहित्य राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है। लेखक भी ऐसे ही हैं। लेखक की कड़ी मेहनत की खुशबू गिरना-en सितारे को उजागर करता है जिसने कहानी को रोशन किया। यह देश के प्रति प्रेम, उसकी विविधता और सुंदरता को प्रदर्शित करने वाला एक ईमानदार काम है। एक शक्तिशाली पीढ़ी को लाने के लिए माँ की सच्ची प्रेरणा भी सराहनीय है।

श्वेता वी, पझायंगडी

विपक्ष की जिम्मेदारी

संदर्भ: तेलंगाना की जीत जरूरी लोग भूमि अधिग्रहण करते हैं (16 नवंबर)। संपादकीय में सरकार को संयम बरतने और स्थानीय लोगों के डर को दूर करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जन सुनवाई करने की सलाह दी गई है। सरकार ने राजस्व अधिकारियों को जनता की राय जानने के लिए भेजकर सही किया। लेकिन दुर्भाग्य से, अधिकारियों से एक शब्द भी बात किए बिना, स्थानीय लोगों ने उन कारणों से पूर्व नियोजित हिंसा शुरू कर दी, जो उन्हें ही पता थे। दुखद रूप से, किसान इसके शिकार बन गए।

विपक्षी दलों पर इन क्लस्टरों पर सहयोग करने की बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे प्रदूषण कम होगा और किसानों को उचित मुआवजे और नौकरियों के लिए राजी किया जा सकेगा।

जयप्रकाश रेड्डी, नलगोंडा

पशु संघर्ष

केरल में मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है, जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों, जंगली सूअरों, बाघों और अन्य जानवरों से खतरा। ये लगातार घटनाएं जान-माल और आजीविका को नुकसान पहुंचा रही हैं। सरकार को मजबूत सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने, संघर्षों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और आवश्यक होने पर खतरनाक जानवरों को स्थानांतरित करने के लिए तेजी से कार्य करना चाहिए। प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा भी ऐसी कार्रवाई का एक अनिवार्य हिस्सा है।

मोहम्मद शफी, कोझिकोड

मणिपुर में उत्पात

मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम कोई नई बात नहीं है। राज्य में जो कुछ हो रहा है, उसे कोई फिल्म भी नहीं दिखा पाएगी। 50,000 से ज़्यादा लोगों को जंगलों में खदेड़ दिया गया, संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, बलात्कार और हत्या की गई, महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नंगा करके घुमाया गया - ऐसी घटनाएँ एक साल से भी ज़्यादा समय से हो रही हैं। सरकारी हथियार लूटे गए हैं। फिर भी सरकार को, बिना किसी जानकारी के, सिर्फ़ इसलिए बने रहने दिया जा रहा है क्योंकि पार्टी सत्ता में रहना चाहती है। अब समय आ गया है कि राज्य को एक ऐसी शासन संस्था दी जाए जो लोगों की परवाह करे।

एजी राजमोहन, अनंतपुर

न्यू संडे एक्सप्रेस
बोर्ड के अध्यक्ष: मनोज कुमार सोंथालिया संपादक: सांत्वना भट्टाचार्य
रेजिडेंट एडिटर (तमिलनाडु): एंटो टी जोसेफ * एक्सप्रेस पब्लिकेशन (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आरके झुनझुनवाला द्वारा एक्सप्रेस प्रेस, 'एक्सप्रेस गार्डन', 29, सेकंड मेन रोड, अंबत्तूर इंडस्ट्रियल एस्टेट, चेन्नई - 600 058 पर मुद्रित और प्रकाशित। चेन्नई: खंड 25, संख्या 46। आरएनआई रजिस्टर संख्या TNENG/2000/3090, फोन: 044-23457601, फैक्स: 044-23457619। * पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार।
कॉपीराइट: एक्सप्रेस पब्लिकेशन (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड। सभी अधिकार सुरक्षित। पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा, पूरे या आंशिक रूप से पुनरुत्पादन निषिद्ध है।

Machine Translated by Google

Manage C&D waste better to fight air pollution: CSE

Construction and demolition (C&D) waste is a key source of air pollution. About 80-90% of C&D waste can be repurposed for applications such as landscaping, earthworks and civil engineering projects. Municipalities are unable to recover the costs from informal and anonymous waste generators. This has often resulted in municipalities under-capitalising the C&D recycling plants to avoid paying for the tipping fees. Plant operators lose out on the potential revenue that can be generated from the sale of recycled products

NEW DELHI: With India's construction industry booming, the country's cities are all set to see a marked increase in the generation of construction and demolition (C&D) waste. This expected growth in the C&D waste stream is all the more alarming as it will add to the problem of air pollution that Indian cities have been struggling with.

"The existing operational C&D waste sector is projected to more than double in the coming years. If not fully recovered and recycled, construction waste can turn into a major polluter choking our cities. Though progressive steps are underway to set up C&D processing plants in cities, these have been marred by complaints of underutilisation and unviability due to inefficient waste management and market linkages," says a new study by Centre for Science and Environment (CSE) that was released here today. Debris Dilemma: Promoting self-sufficiency – as the study is titled – presents a detailed review of 16 C&D waste recycling plants spread across India.

Releasing the report in a national stakeholder conference held in New Delhi, Anumita Roychowdhury, executive director, CSE, said: "C&D waste management and construction dust mitigation are integral to all clean air action plans of the 131 non-attainment cities (NACs) under the National Clean Air Programme of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Cities are mandated to set up recycling plants to process waste to produce value-added products such as recycled aggregates, paver blocks etc, that can be brought back as a resource to the construction industry itself."

Roychowdhury added: "Recycling of C&D waste enables full recovery of resources and adds economic value to the waste, creates livelihood and jobs. But their utilisation and economic viability are compromised due to weak waste management system in cities and poor market uptake of the recycled products by the construction agencies."

The CSE study

Of the more than 35 new C&D waste recycling plants that are being set up in India, CSE has investigated and assessed the performance of 16 plants to understand the current gaps and the requisite policy pathways to make them scalable and effective.

The field investigation has evaluated the multifaceted processes and technologies that are applied in a C&D recycling plant, the product range produced from waste, effectiveness of waste management in sustaining waste feed to the plants, market uptake of the recycled products, and the overall economic viability of these plants. Says Rajneesh Sareen, director of CSE's sustainable buildings and habitat programme: "What we have found is that despite making huge investments, most recycling plants are struggling economically. These plants continue to rely heavily on support from municipalities. Without a viable financial model and market integration, expanding such facilities will face difficulties and this can further weaken the overall waste management ecosystem.C&D waste is not just an environmental hazard; it's an efficiency hurdle for cities."

UjjwalMitra, ADG (training and research), National CPWD Academy, said: "Reconstruction is a new reality. C&D waste generation from reconstruction is expected to rise from 7 percent to 15-16 percent of the construction portfolio. This will have huge land and energy implications if not handled well." India's building space is projected to more than double in the next 20 years. There is enormous demand for sand and gravel,which increasesthe environmental footprints of mining. This rising demand has led to a six-fold increase in sand trade over the past 20 years, and to environmental issues like erosion, biodiversity loss and water salination. As a result, imports of sand have gone up.

Says Sareen: "Recycling of C&D waste can help substitute and reduce the demand for virgin material as approximately 80-90 per cent of C&D waste can be repurposed for various applications such as landscaping, earthworks and civil engineering projects. Using recycled aggregates causes 40 per cent lesser CO_2 emissions compared to using virgin materials – this is because it helps reduce embodied energy and lowers carbon footprints."

Areas of concern

Municipalities do not have an adequate revenue stream to pay for illegally dumped waste in a city – they are unable to recover the costs from informal and anonymous waste generators. This has often resulted in municipalities under-capitalising the C&D recycling plants to avoid paying for the tipping fees. Plant operators often do not get sufficient C&D waste as feed for the recycling plants owing to inefficient waste collection and leakages in the system – they lose out on the potential revenue that can be generated from the sale of recycled products.

This increases their dependency on the tipping fee paid by the municipality for sustenance. This model is unsustainable, and discourages more C&D recycling plants from being set up.

The way forward

The CSE assessment study lists a few do's:

A more aligned effort by construction companies, municipalities and recycling plants to create a robust ecosystem for efficient waste collection, segregation and transportation to the recycling plants to sustain the feedstock.

Municipality needs to support and create a well-structured ecosystem and a smart concessionaire agreement. This will allow the municipality to reduce its own involvement and associated expenses in C&D waste recycling.

Policy mandates for uptake of recycled products by construction agencies and plant operators' own innovative marketing strategy for recycled products needed for ensuring economic viability of the plants.

Municipalities often face staffing limitations that make it challenging to fully address illegal dumping. Smarter concessionaire agreements that incorporate third-party enforcement can help to bridge this gap.

High disposal fees burdens the small waste generators, leading to illegal dumping. Rationalised fees for small waste generators, with cross-subsidies from bulk waste generators (like the Delhi model), can help them improve the formal disposal methods. A user-friendly system for waste pick-up, accessible collection points and awareness can drive the improvement.

Integration of the informal sector for primary waste collection can leverage the widespread network and capabilities of informal waste collection systems and enhance the efficiency of waste collection and transportation.

C&D recycling plants can have a successful business model if sales and market uptake of recycled products is efficient. This can also foster competition and encourage more recycling plants in cities.

With advancements in recycling technologies recycled aggregates can effectively replace natural material. This, however, requires more updated codes and standards for quality control.

Quality concerns limit the market uptake of C&D recycled products in the construction sector. Incorporating material testing labs in new recycling plants can ensure high standards and increase the use of recycled materials.

Grassroots democracy, an idea whose time has come

C B Rau

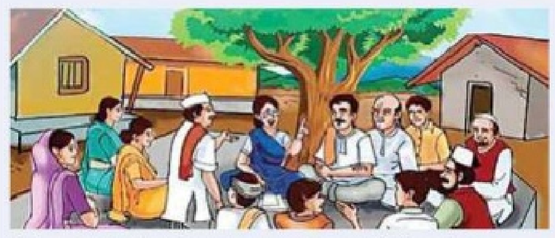

A democracy that is not grassroots–centric is a sham democracy. That was how it was before and has to be in the future. The world over, there is now a renewed interest in this kind of governance and a realization 'that systemic problems are best addressed and carried out at the root level through cooperative communities'. A study sponsored by McKinsey Global Institute starts off with the statement, "Our world is big and complex, but human progress is still about life on the ground, up close and in detail.' This is what is called subsidiarity in political science – the idea that you should devolve decision-making to the lowest level that you can to get the best outcomes

It has become customary for Indian leaders to proclaim that India is not only the biggest democracy in the world but also the 'Mother of Democracy'. Indeed, it was, but not for the reasons they cite such as the existence of non-hereditary rulers in India before anywhere else. It was just the opposite. It was a 'democracy' in true spirit despite being ruled by kings and emperors, almost right up to the advent of the British. That was primarily because authentic governance at the ground level – through bodies called sabha and mahasabha in south, and Srem, Nigama, and Nigama-Sabk in north – was almost entirely under the command and control of the people.

Then again, a state can be a democracy despite having a king or emperor at the top. We have quite a few in today's world. And also many countries which have non-hereditary or 'elected' leaders are not democracies by any stretch. The real test of democracy is what it means in Greek – rule by the people where it matters most: daily life. And the ancient Indian model ensured that. In India, the king was the head of the state, but not of the society He had a place in the social hierarchy, but was not the highest place.

As far as daily life was concerned, the points of contact between the state and the ordinary interests of the daily life of the people were indeed very few. In other words, monarchy and democracy were mutually reinforcing, not colliding. Ground-level or local bodies were practically in character sue generis or stand-alone; like, in the words of a former British Governor-General 'a separate little State in itself'. They were fully in charge of administering their designated territories and were fully empowered to raise revenues necessary to discharge their responsibilities.

At the same time, the king was empowered and expected to intervene and adjudicate when necessary to enforce discipline and accountability in the local bodies. There is a record of several interesting cases of the royal power being invoked and exercised in the interest either of the assemblies or of aggrieved parties. The kings too found it advantageous as a kind of safety valve. They were very useful to mobilise public spirit and popular participation to cope with emergencies and natural calamities. At times like that, everyone chipped in and even temples were willing to part with their jewelry.

This is the kind of spirit we lack in modern India. This kind of grassroots governance and its 'richness of structure, was what, as Rabindranath Tagore pointed out, enabled both our rural society to function without dependence on external help and to remain unimpaired by aggression from outside. It provided what one commentator called 'a kind of Noah's Ark' and another to note that it enabled it to remain largely unaffected by 'more religious and political revolutions than any other country', like a 'rock by the rising and falling of the tide'.

In post-independence, our leaders chose to turn their back on this kind of democracy and opted for the Westphalian style of sovereignty and the Westminster system of governance. That meant that the state became all-powerful and society lost its co-equal status. The praxis governance mandated by our Constitution – which is actually a cross-bred of unitary and federal systems – made the state the supreme power and concentrated all political power between the Centre and States. Local self-governance got identified with a village, which was ridiculed as a 'stink of superstition' and 'symbol of backwardness'. That doomed genuine grassroots governance, the existence of which was what entitled India to be hailed as a 'mother of democracy.' Modern India's lack of seriousness about local governance was strikingly shown by the fact that its Constitution relegated such empowerment to a Directive Principles, something like an ideal not real..

Conclusion

The bottom line is this: It is only through constitutionally empowered bottom-up governance that India can be effectively governed; indeed, it is the only way the sum of its parts can be more than its whole. The roles played in the past by monarchs – substantive but supportive; non-interfering but a vigilant watch dog – can now be the roles of the federal and state governments. Shift to bottom-up governance could be the solution to the now famous Rajeev Gandhi statement (1985), namely, that out of every rupee targeted towards welfare and poverty alleviation only a fraction, 15 paise, reached the intended beneficiary. The figure might vary and technology has made a difference but the syndrome persists. That is because the issue is not only leakages and corruption; more fundamentally it is the very process of policy-making and project formulation. That has to be fully in the hands of institutions proximate to people, which also will insure transparency and accountability. Such governance will also go a long way towards social justice and targeting the needs of the local most-needy. Last and the most important, this is the only practical way to cushion the agency of administration from party politics and emasculate the money and muscle power in our democracy.

With so many tangible benefits much in its favor and despite the 73rd and the 74th amendments to the constitution, why hasn't it happened? First, the political class saw this idea as tantamount to cutting off the supply of oxygen of power. For, as a famous American adage goes, all politics is local. Second, even these amendments were ineffective because it made the states 'responsible to establish a strong local self-government system' and for 'devolving power, responsibilities, and finances'. To expect the states to voluntarily to fall in line was at best extreme naiveté. It is like expecting a villain of the piece to be a Good Samaritan. The local bodies must be directly empowered by the constitution as part of a new 'division of power' between the Centre, States and local bodies.

The message is clear. A democracy that is not grassroots–centric is a sham democracy. That was how it was before and has to be in the future. The world over, there is now a renewed interest in this kind of governance and a realization 'that systemic problems are best addressed and carried out at the root level through cooperative communities'. A study sponsored by McKinsey Global Institute starts off with the statement, "Our world is big and complex, but human progress is still about life on the ground, up close and in detail.' This is what is called subsidiarity in political science – the idea that you should devolve decision-making to the lowest level that you can to get the best outcomes. The anomaly is that while India, in which real and robust grassroots democracy flourished for so long, abandoned it soon after it became a free nation and chose the western style representative democracy, that very west is now inching towards that which India abandoned, partly disillusioned with its own version. The silver lining is that should help us to quell some of the opposition and to bring it on to the front burner of public discourse. Only through that can we create the momentum necessary to make it a reality. That may take time but there is no time to dither any longer.

GREAT SERVICE IN WAKE OF DEVASTATING CYCLONE IN DIVI SEEMA

THE 'DIVI SEEMA GANDHI'

Vanam Jwala Narasimha Rao

Mandali Venkata Krishna Rao's involvement during the Divi Seema cyclone enhanced his stature as a reliable and trusted leader in Andhra Pradesh, leading to his sustained influence in state politics. His reputation as a compassionate and socially committed leader who preferred prioritisation of the well-being of the people over political power, during that period, are to be often remembered as an example of genuine leadership in times of crisis

47 years ago, a devastating cyclone struck Divi Seema of Krishna district on 19th November 1977. When the cyclone made landfall, the wind speed was estimated as 200 kmph, accompanied by torrential rain and storm surges. It inundated vast areas, damaged properties, and washed out several villages and whole families. Many people lost their lives, animals drowned or dead, roads were ruined, bridges collapsed, electricity and water supply discontinued, and the entire communications were disrupted. Massive relief operations were instantly initiated by the government and NGOs, regional associations, religious groups, political parties, local communities, Army, volunteers, social workers etc.

Relief camps provided the immediately requirement of ground-level support like safe drinking water, food, clothing, and shelter. The disaster management teams of state government were activated. Rescue, relief, and rehabilitation operations, followed by cyclone reconstruction activities, and establishment of central kitchens to supply hygienic food were speeded up. Medical teams were pressed into service. The disaster emphasised the need for better management of infrastructure, early warning systems, and evacuation procedures in future. The cyclone exposed the vulnerability of Coastal Andhra.

This ghastly occurrence was the deadliest cyclones in India's History, leading to widespread destruction and a significant humanitarian crisis. Despite significant weather warnings, prior to cyclone, in the absence of advanced communication systems, many coastal residents were in dark, and unaware of the impending danger. Efforts to evacuate people were inadequate, resulting in high casualties of human beings (a moderate estimate was 10,000 lives) and animals. With limited infrastructure, handling large-scale evacuations became difficult. Jalagam Vengal Rao who was the Chief Minister, handled the situation effectively and efficiently.

Most important was the unparalleled involvement with enormous sympathy and empathy by Mandali Venkata Krishna Rao, a cabinet minister in Vengal Rao team. He played a crucial role during relief operations, promptly jumping into relief activity. Often in waist deep water, and braving the intemperate weather, he toured the adjoining villages. He requested Chief Minister Vengal Rao to relieve him of his responsibilities as a minister, to enable him to serve people better, and bring succour to the suffering people.

51 years old Krishna Rao also took the lead in mobilising resources and organising immediate relief measures, including food, medical aid, and temporary shelters for displaced families. Beyond immediate relief, Mandali Krishna Rao advocated for long-term rehabilitation, including rebuilding infrastructure and providing support to revive the livelihoods of the affected population, especially in agricultural and fishing sectors. His act of walking barefoot was symbolic, showing humility and his sense of duty towards the suffering communities.

In an article (made available to me by his son Mandali Buddha Prasad) titled 'The Dark Night, The Sea Struck; The Tidal Wave That Ran Amuck' written by Mandali Venkata Krishna Rao, he recalled the happenings of those dark days, and about his 'Intuition coupled with the warnings of a severe cyclone by All India Radio News Bulletins' that led him to take the decision of cancelling his proposed journey to Hyderabad, and instead preferring to stay in the 'Sevashram Orphanage' at Avani Gadda, housing 60 orphans, so that they were not scared of the situation. That way he started doing his best in that crisis. When the velocity of the wind increased, 80 girl students from a nearby hostel and also some hut dwellers around, were evacuated and shifted to the Ashram with his initiative. Mandali Krishna Rao remained in the 'Nirmala Sadan' of Sevashram, a hut with grass roof, specially made for Gandhiji's daughter-in-law and grand-son, Nirmala Gandhi, and Kanu Gandhi respectively. They inaugurated the Sevashram on October 2, 1977, a month and half ago of the cyclone. At that place, Mandali Krishna Rao 'was standing at the window watching the place where the children were kept and assessing the cyclonic weather.' What a great, and rare characteristic compassion.

It was 4 o'clock in the evening. The wind velocity was increasing, and the roof of 'Nirmala Sadan' where he with others were staying was blown off. Some of the orphans and hostel girls who were shifted to 'Sevashram Orphanage' got scared and came running out, and started screaming. A boy was seen being carried away by the wind, and with a lot of effort, Mandali Krishna Rao and others managed to bring orphan children to 'Nirmala Sadan.'

Mandali Krishna Rao narrating the then situation in his article of interest, mentioned that, at 5 pm the 'Sky appeared Blood Red' as though a 'Burning Fire' was spread, giving a feeling of an 'Ocean Fire.' A short while later, the whole sky was most 'Brilliantly Illuminated' like day light. Afterwards it was cloudy again. The differing illumination of the sky caused different fears in the mind. All these strange phenomena could not be apprehended. When at 2 o'clock in the night, the wind velocity reduced, he went out with the help of a torch light. He noticed that the whole road was covered by tree branches, leaves, and tiles; frightful snakes crawling; thorns running into the feet. Unmindful of all this, he talked to everyone and asked them not to stir out till the morning.

Next day morning, he wrote that, when the sun was rising and sky was cloudy, electric poles were found twisted, lakhs of people were caught amidst ferocity of nature etc. CM Vengal Rao and Revenue Minister Narasa Reddy came on the 21st morning. With them, Mandali went round the cyclone-affected areas in the helicopter, and saw all the devastation. Later, the CM at a conference ordered to intensify and speed up relief and rehabilitation measures. President of India Nilam Sanjeeva Reddy (On 23rd), Governor Sharada Mukherjee, Union Agriculture Minister Surjit Singh Barnala, Defense Minister Babu Jag Jivan Ram (On 25th), Indira Gandhi (On 27th), and 'Central Team' (On 28th) headed by Secretary Agriculture SA Mukherjee toured the affected areas. On the 30th, the Prime Minister Morarji Desai also came.

Mother Theresa, Billy Graham, AICC (R) president Kasu Brahmananda Reddy, Janata Party president Chandrasekhar, CPI Secretary Chandra Rajeswar Rao, CPM Leader EMS Namboodiripad, West Bengal Chief Minister Jyothi Basu, RSS leader Deoras etc., visited the affected areas. Representatives and volunteers from international voluntary organizations like Red Cross, CAFE, EFICOR, Rotary, Lions, Ramakrishna Mission, RSS, Anand Marg, Vishva Hindu Parishad, Bharat Sevashram, and a host of others also toured the devastated places and rendered aid.

Most interesting in his article was the thought process of Mandali Krishna Rao behind his decision to resign. He mentioned that, 'I felt hurt that 20 years of my hard work in developing the area was completely destroyed. I could not see the helpless condition of the people. I felt that service to people was more important than ministerial responsibilities. I wrote to the Chief Minister requesting him to relieve me of my ministerial responsibilities to enable me to involve myself in relief operations, to which he disagreed. However, in accordance with the wishes of the Chief Minister and wishes of the people I continued in my office serving the people.'

Mandali Krishna Rao's involvement during the cyclone enhanced his stature as a reliable and trusted leader in Andhra Pradesh, leading to his sustained influence in state politics. His reputation as a compassionate and socially committed leader who preferred prioritisation of the well-being of the people over political power, during that period, are to be often remembered as an example of genuine leadership in times of crisis. Rao was an MP for one term, MLA from Avani Gadda for nearly 13 years, and Minister holding several ministerial portfolios in erstwhile Andhra Pradesh Cabinet. 'Mandali Venkata Krishna Rao' rightly came to be known as 'Divi Seema Gandhi.'

I knew him personally and met him.
(Learning Lessons from Life)

DECCAN Chronicle
17 नवंबर 2024

श्रेया सेन-हैंडले
अनजान रास्ते

ट्रम्प ने हराया? रीसेट करने, फिर से जीवंत होने और फिर से संगठित होने का समय आ गया है ।

ट्रम्प फिर से, है न? यह इतना है कि आप इस लालची, जानबूझकर अज्ञानी दुनिया को बाहर कर देना चाहते हैं, जिसने उनके जैसे स्त्री-द्वेषी, नस्लवादी, फासीवादी तानाशाह को धरती के सबसे शक्तिशाली डेस्क के पीछे बैठा दिया।

लेकिन दुनिया से मुंह मोड़ने से आप केवल मानवीयता की घटती हुई श्रेणी को ही कम कर रहे हैं। विरोध में उठाई गई आपकी आवाज़, अभी भी मायने रखती है, अगर सिर्फ़ समान विचारधारा वाले लोगों के बीच गूंज कक्षों में। यह दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। खुद को अलग कर लेना तब जवाब नहीं है, लेकिन पीछे हटना महत्वपूर्ण हो सकता है - आपके और इस ग्रह के अस्तित्व के लिए।

दुनिया की स्थिति से निराश सभी नेकनीयत लोगों की तरह, सोशल मीडिया के युद्धक्षेत्र से अस्थायी रूप से हट जाना, समाचार आउटलेट के रूप में प्रच्छन्न कई नकली प्लेटफार्मों से दूर रहना, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

लेकिन चूँकि लोभी के गंदे पंजे के निशान हर जगह हैं, सिर्फ़ आभासी दुनिया में ही नहीं, इसलिए हमारा संन्यास वास्तविक दुनिया तक भी फैलना चाहिए। फिर भी, प्राकृतिक दुनिया की महिमा में खुद को डुबोने से बेहतर कुछ भी नहीं है, खासकर उन लोगों की संगति में जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे अंधेरे समय में, हमें खुद को इस सांत्वना से क्यों वंचित रखना चाहिए?

आप देखिए, हमारे वंशजों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बलिदान तो करना ही होगा। जैसे कि कुछ लोगों के लिए अल्पकालिक लाभ की तुलना में सभी के लिए दीर्घकालिक स्थिरता, जिसे हमने अपनी सरकारें चुनते समय बार-बार अस्वीकार किया है। लेकिन क्या ट्रम्प का फिर से चुना जाना हमारे ताबूत में अंतिम कील है, या क्या हम अपने भाग्य को बचाने के लिए अन्य मोर्चों पर लड़ना जारी रख सकते हैं?

सोशल मीडिया के युद्धक्षेत्र से अस्थायी रूप से दूर रहना, समाचार आउटलेट के रूप में प्रच्छन्न कई नकली प्लेटफार्मों से दूर रहना, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन चूँकि लालच के गंदे पंजे के निशान हर जगह हैं, इसलिए हमारा संन्यास वास्तविक दुनिया तक फैलना चाहिए।

मैं विशेष रूप से इस बात से प्रभावित हूं कि हमें कितनी जल्दी यात्रा के लिए अपने दायरे को छोटा करना चाहिए (हालांकि एक अनुभवी यात्रा लेखक के लिए इसकी वकालत करना कठिन है), तथा इसके बजाय अपने दरवाजे पर मौजूद सौंदर्य को पोषित करना चाहिए, जबकि हम अपने दिलो-दिमाग को उन लोगों के लिए खोल देते हैं जिन्हें हमने कभी प्रवेश की अनुमति नहीं दी।

अगर हमने छोटे से किरिबाती या उससे भी बड़े लेकिन गरीब बांग्लादेश की तकलीफों पर ज़्यादा ध्यान दिया होता, तो क्या हम स्पेन में इस शरद ऋतु में आई जानलेवा बाढ़ को टाल सकते थे? स्टाइलिश बार्सिलोना खुद पानी में डूब गया, जबकि उसके नागरिक उससे कुछ महीने पहले ही उग्र पर्यटन विरोधी प्रदर्शनों में सड़कों पर उतर आए थे, और उन्होंने ठीक वैसी ही आपदाओं की चेतावनी दी थी जैसी उन्होंने झेली थीं। साल-दर-साल 7% की वृद्धि के साथ, 2024 में बार्सिलोना के पर्यटकों की संख्या 10.9 मिलियन तक पहुँच गई, जिससे उनके शहर के बुनियादी ढांचे पर असहनीय दबाव पड़ा, जिससे तबाही मच गई।

और जबकि दार्जिलिंग में, जहां मैंने दिवाली से पहले कुछ शांत दिन बिताए थे, वहां कोई प्रदर्शनकारी नजर नहीं आया, केवल बंदर टोपी पहने बंगाली लोगों का झुंड (महिलाएं भी, जिनकी पहचान के लिए गुलाबी पोमपोम थे) मैदानी इलाकों से आये थे, निस्संदेह वहां होना चाहिए था।

मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विस्मयकारी, राहत देने वाले पहाड़ पसंद नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करता था। और मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मानवता, विशेष रूप से इन आश्चर्यजनक भूभागों के आगंतुक, उनके साथ क्या कर रहे हैं (हाँ, मैं भी शामिल हूँ, हालाँकि हम अपनी यात्राओं पर सबसे हल्के पदचिह्न छोड़ने की कोशिश करते हैं)। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले गंभीर नुकसान को पहचानना मुश्किल नहीं है, चाहे हमारी सरकार इस पर कितनी भी आँखें मूंद ले, जबकि दूसरी पूरी तरह से काम करने वाली आँख पर्यटन से मिलने वाले पैसे पर पूरी तरह से टिकी हुई है।

इन पहाड़ों की मेरी पिछली यात्रा के दशकों बाद, बहुत कुछ बदल गया है। उनकी स्थायी सुंदरता अभी भी रोमांचकारी है, यहां तक कि ऑरेंज मेनस (उस सप्ताह) की आसन्न वापसी भी मेरे उत्साह को कम नहीं कर पाई। लेकिन अन्य कारकों ने लगभग इसे प्रबंधित कर लिया।

भारत के इस हिस्से में फैली गंदगी, बीमारी और लापरवाही, कम से कम कहने के लिए निराशाजनक थी। गरीबी निस्संदेह जिम्मेदार है, लेकिन पर्यटन का अस्थिर स्तर और भ्रष्टाचार का अभिशाप भी प्रमुख अपराधी हैं।

लामाहट्टा इको पार्क, देवदार के जंगल का एक टुकड़ा है, जो अपनी घनी धुंध और ऊंचे सदाबहार पेड़ों के साथ एक रमणीक स्थल होता, लेकिन वहां फैले कूड़े के कारण यह पार्क अब और भी सुंदर नहीं है - यह लापरवाह पर्यटकों की भीड़ का काम है, जो अपने कचरे को स्पष्ट रूप से उपलब्ध करायी गयी टोकरियों में डालने के बजाय मेरे ब्रिटिश पति (गोरे रंग के कारण ही हमारे कुछ रंग-प्रेमी देशवासी शर्मिंदा हो जाते हैं) के साथ सेल्फी लेने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं।

जहाँ तक दार्जिलिंग की बात है, तो यहाँ की गंदगी ने मेरा दिल तोड़ दिया। हालाँकि इसके ऐतिहासिक कैफ़े, चाय-चखने के ठिकाने और प्रामाणिक तिब्बती टेकअवे, सभी चखने लायक थे, लेकिन चारों तरफ़ से पर्यटकों की भीड़, बदसूरत नए निर्माण और दिल दहला देने वाली हालत में कुत्ते और टट्टू, इसकी एक बार की पौराणिक आकर्षण को धुंधला कर देते हैं।

लेकिन शानदार हरी-भरी और घुमावदार पहाड़ी सड़कें, शांत मठ, आकर्षक विचित्र चाय के बागान, मित्रवत स्थानीय लोग, और दुनिया की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला का दृश्य, इन सबसे अधिक असंगत अनुभवों को पूरी तरह से मिटा देते, यदि हमारे बेहतरीन पल ग्लोबल वार्मिंग के कहर के कारण वहां नहीं बिताए गए होते।

दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर हमारी पहली सुबह सबसे शानदार नज़ारा देखने को मिला, जो हमने कभी देखा था, उगते सूरज की रोशनी में जल रहा था और दिन की तरह साफ था, यह आश्चर्यजनक था। आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि बादलों से घिरी यह पौराणिक चोटी मायावी मानी जाती है, लेकिन हाल ही में इस क्षेत्र में आए ग्लोबल वार्मिंग के कारण उच्च तापमान ने हमें इसकी एक अद्वितीय झलक दी, जिससे हमारे पास खट्टी-मीठी यादें रह गईं।

ग्लोबल वार्मिंग अब और भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप वापस आ गए हैं और अपने अनुयायियों की खुशी के लिए हमारी पहले से ही तबाह हो चुकी धरती को 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' करने का वादा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को नकारने वाले ट्रंप ने अपने पिछले राष्ट्रपति पद के खून-खराबे में सड़ांध पैदा करने वाली अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों को खत्म कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी प्राकृतिक दुनिया और सभी सही सोच रखने वाली (वास्तव में गलत सोच रखने वाली) मानवता को उनसे अस्तित्व का खतरा है।

कोई इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि जवाब तुरंत सामने नहीं आएंगे। अभी के लिए, उस हानिकारक प्रदूषण (ब्रिटिश अंग्रेजी में ट्रम्प का अर्थ) से दूर रहें जो वह हर अच्छी चीज में डालता है। धरती के अधिकांश हिस्से से अपने पैरों के निशान मिटा दें ताकि आपको भी दोषी न ठहराया जाए। फिर? फिर से जीवंत हो जाओ, फिर से संगठित हो जाओ और फिर से स्थापित हो जाओ, आगे की लड़ाई की शर्तें।

श्रेया सेन-हैंडली पुरस्कार विजेता मेमोयर्स ऑफ माई बॉडी, लघु कहानी संग्रह स्ट्रेंज और यात्रा वृत्तांत हैंडल विद केयर की लेखिका हैं। उनका ट्विटर और इंस्टा हैंडल @shreyasenhan है।

सुभानी

बुश, ओबामा, ट्रम्प, बिडेन विरासत: अफ़गानिस्तान

मनीष तिवारी
संघ का राज्य

2.31 ट्रिलियन डॉलर 2001-2022 के बीच युद्ध पर अकेले अमेरिका ने खर्च किए अफ़गानिस्तान। इस अवधि के दौरान लगभग 200,000 लड़ाके और नागरिक मारे गए। लगभग 200,000 लोग अपंग और घायल हो गए। यह सब इस तरह हुआ।

अलकायदा को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम, जो 7 अक्टूबर 2001 को शुरू हुआ। यह 11 सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था।

2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के साथ ही बुश-43 प्रशासन के लिए अफ़गानिस्तान एक दिखावा बन गया। 2009 में जब बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद संभाला, तब तक अमेरिकी रणनीतिक समुदाय के लिए यह स्पष्ट हो चुका था कि प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान कहीं नहीं जा रहा था।

11 फरवरी 2009 को, शपथ ग्रहण के 22 दिन बाद, ओबामा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति की अंतर-एजेंसी नीति समीक्षा की अध्यक्षता करने के लिए, लगभग तीन दशकों से केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुभवी विश्लेषक, ब्रूस रीडेल को नियुक्त किया था।

27 मार्च 2009 को ब्रूस रीडेल ने समीक्षा के परिणाम के बारे में मीडिया को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, "मैं यहाँ एक या दो मुख्य शीर्षकों को ही सामने रखूँगा। मुझे लगता है, जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मिशन का एक लक्ष्य और एक स्पष्ट, संक्षिप्त लक्ष्य हो। और वह लक्ष्य, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया, अल कायदा को बाधित, नष्ट और पराजित करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उनके सुरक्षित ठिकाने अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा न बन सकें।" जैसा कि उन्होंने कहा, अल कायदा पिछले सात वर्षों में खुद को फिर से खड़ा करने में सफल रहा है, और यह फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका की मातृभूमि और दुनिया भर में अमेरिकी प्रभाव और हमारे सहयोगियों के लिए एक खतरा है।

दुनिया भर में अलकायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों के एक बहुत ही परिष्कृत सिंडिकेट के भीतर काम करता है...

अब तक हमारी नीति अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को दो देशों के रूप में देखती है, लेकिन हमारी कूटनीति के लिए एक संचालन का क्षेत्र है, और हमारी समग्र नीति के लिए एक चुनौती है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, हम पाकिस्तानी सरकार के साथ गहन रूप से जुड़ने जा रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बढ़ाने के लिए बहुत ठोस प्रस्ताव हैं, जो कांग्रेस द्वारा पहले ही पेश किए जा चुके हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि हम सैन्य पक्ष पर क्या कर सकते हैं।

अफ़गानिस्तान की ओर से, राष्ट्रपति ने मिशन की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया है - न केवल सैन्य पक्ष पर, बल्कि मैं नागरिक पक्ष पर भी ज़ोर देना चाहता हूँ। अब, पहली बार, हम उस तरह का नागरिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं जिसकी इस मिशन को हमेशा से ज़रूरत थी।"

समीक्षा से मुख्य निष्कर्ष यह निकला कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की भागीदारी घटने के बजाय बढ़ने वाली है। इसके परिणामस्वरूप अफ़गानिस्तान में 30,000 सैनिकों की वृद्धि हुई।

जनरल मैकक्रिस्टल के नेतृत्व में अमेरिकी सेना यही चाहती थी और अन्य लोगों के अलावा ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एडमिरल माइक मुलेन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल डेविड पेट्रायस का समर्थन भी। एक व्यक्ति जिसने इस उछाल का कड़ा विरोध किया, वह तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बिडेन थे, जिन्होंने सोचा था कि अमेरिकी डीप स्टेट ने एक नए राष्ट्रपति को 'बाहर' विकल्प के बजाय 'अंदर' विकल्प पेश करके घेर लिया है।

ओबामा अपने आठ साल के राष्ट्रपतित्व काल में अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाए। हालाँकि 28 दिसंबर 2014 को अमेरिका और नाटो अधिकारियों ने काबुल स्थित अपने मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया था।

अलकायदा को ख़त्म करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम, जो 7 अक्टूबर 2001 को शुरू हुआ। यह 11 सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था।

अफ़गानिस्तान में उनकी औपचारिक भागीदारी का अंत हो गया, लेकिन समापन अभियान में पर्याप्त छूट थी, जिससे यह सामान्य व्यवसाय जैसा ही रहा। हवाई हमले और सहायता मिशन, शिकार, ट्रैक और मारने के कामों के लिए ड्रोन और विशेष ऑपरेशन बलों का उपयोग का मतलब था कि अमेरिकी और नाटो सेनाएँ अफ़गानिस्तान में सक्रिय रूप से लगी रहीं।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान अफ़गानिस्तान में अपने पूर्ववर्तियों द्वारा निर्धारित मार्ग का ही पालन किया। 21 अगस्त, 2017 को वर्जीनिया के अर्लिंग्टन में फोर्ट मायर सैन्य अड्डे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैं अमेरिकी लोगों की हताशा को साझा करता हूँ... मैं एक ऐसी विदेश नीति पर उनकी हताशा को भी साझा करता हूँ जिसने बहुत अधिक समय, ऊर्जा, धन - और, सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन - को हमारे अपने स्वरूप में देशों के पुनर्निर्माण की कोशिश में खर्च किया है, बजाय इसके कि हम अपने सुरक्षा हितों को अन्य सभी विचारों से ऊपर रखें।" फिर उन्होंने एक चेतावनी दी: "मेरी मूल प्रवृत्ति बाहर निकलने की थी, और ऐतिहासिक रूप से मैं अपनी प्रवृत्ति का पालन करना पसंद करता हूँ... मैंने सुना है कि जब आप ओवल ऑफ़िस की डेस्क के पीछे बैठते हैं तो निर्णय बहुत अलग होते हैं।"

अंततः ट्रम्प ने अफगानिस्तान में 3,000 सैनिक भेज दिए, जिससे कुल संख्या 14,000 हो गई।

अफ़गानिस्तान में दलदल को और भी बदतर होते देख राष्ट्रपति ट्रम्प ने तालिबान के साथ समझौता करने का फ़ैसला किया। वही लोग जिनका अमेरिका ने इतनी शिद्दत से पीछा किया था, उन्हें दुनिया भर के "ब्लैक साइट्स" में बेअसर कर दिया था और यहाँ तक कि उन पर अत्याचार भी किया था। उनमें से कई कुख्यात ग्वांतानामो बे जेल में बंद थे।

उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में पूर्व अमेरिकी राजदूत जालमी खलीलजाद को अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने का काम सौंपा।

कतर राज्य द्वारा तालिबान को सहायता प्रदान की गई। लंबी बातचीत के बाद अमेरिका ने 29 फरवरी, 2020 को दोहा में तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक था "अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के बीच अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए समझौता, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और जिसे तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जाना जाता है"। यह पहली बार नहीं था कि अमेरिका ने एक गैर-राज्य अभिनेता के साथ एक संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जहां अमेरिका बाहर निकलना चाहता था।

27 जनवरी, 1973 को अमेरिका ने पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि वियतनाम से वापसी का रास्ता साफ हो सके। इस समझौते पर वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य (उत्तरी वियतनाम), वियतनाम गणराज्य (दक्षिण वियतनाम), संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण वियतनाम गणराज्य की अनंतिम क्रांतिकारी सरकार (पीआरजी) ने हस्ताक्षर किए थे, जो दक्षिण वियतनामी कम्युनिस्टों का प्रतिनिधित्व करती थी।

दोहा समझौते के ठीक बाद अफ़गानिस्तान की बात करें तो कोविड-19 ने दुनिया को थम सा दिया। दोहा समझौते के कई हिस्से खास तौर पर अंतर-अफ़गान संवाद से जुड़े प्रावधान लागू नहीं किए गए। 20 जनवरी, 2021 को ट्रंप की जगह बिडेन ने ले ली। बिडेन ने थके हुए समझौते को जारी रखने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अमेरिकी विदेश नीति को संभालने का लंबा अनुभव था और इस तथ्य को देखते हुए कि वह 2009 में ही अफ़गानिस्तान में अमेरिकी भागीदारी को समाप्त करना चाहते थे।

15 अगस्त 2021 को अमेरिका ने बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियों में आखिरकार अफगानिस्तान से वापसी कर ली। इसकी तुलना 30 अप्रैल 1975 को साइगॉन से अमेरिका की वापसी से की गई।

दोहा समझौते पर हस्ताक्षर होने के लगभग पांच साल बाद, तालिबान काबुल में स्थापित हो चुका है और समझौते के मूल लेखक ट्रम्प व्हाइट हाउस में वापस आ गए हैं।

अब आगे क्या होगा?

मनीष तिवारी तीसरी बार लोकसभा सांसद और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं।

पत्र

बुलडोजर न्याय

हालांकि बहुत देर से ही सही, लेकिन यह सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अब योगी आदित्यनाथ द्वारा परिकल्पित और कार्यान्वित किए गए क्रूर बुलडोजर न्याय पर रोक लगाने के लिए आगे आया है। सभी समझदार सोच वाले लोगों ने 'आरोपी' के आवासों और व्यावसायिक परिसरों पर बुलडोजर चलाने की क्रूर कार्रवाई पर शोर मचाया, जिससे उनके परिवार बेघर हो गए। सर्वोच्च न्यायालय को केवल बुलडोजर न्याय पर रोक लगाने के साथ ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उन पीड़ितों को उचित मुआवज़ा देने का आदेश भी देना चाहिए, जिन्हें अपने आवासों के साथ-साथ व्यावसायिक स्थानों को भी ढहाए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

Tharcius S. Fernando

अनुच्छेद 370

हाल के दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान नेता अपनी पार्टी के मुद्दों और नीतियों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत, वे व्यक्तिगत हमलों और नफरत पर ध्यान केंद्रित करने पर तुले हुए हैं, जिसके कारण राजनीतिक स्तर गिर रहा है।

यह जानना दुखद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, भले ही दिवंगत प्रधानमंत्री सुश्री सोनिया गांधी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठायें।

इंदिरा गांधी स्वर्ग से उतरी हैं। शाह को मजबूत और वैध कारणों से इस बात को उचित ठहराना चाहिए था। इसके बजाय, उन्होंने बेवजह दिवंगत प्रधानमंत्री का नाम घसीटा है।

यह अच्छी बात नहीं है और उनके पद के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है।

एम. गोविंदराज गुडियाथम

सहनशक्ति में सुधार

जबकि अधिकांश भारतीय खिलाड़ी अपने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, यह देखना परेशान करने वाला है कि हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कम होता जा रहा है। हमें लगता है कि वे अपने विरोधियों को हराने की आदत भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और साथ ही दूर तक जाने की हिम्मत भी खो दी है। अब समय आ गया है कि वे अपनी सहनशक्ति को बेहतर बनाने के लिए तीन सेट खेलें, जो एक घंटे से भी अधिक समय तक चल सकते हैं। अगर वे ऐसा करने में सक्षम हैं, तो हमें विश्वास है कि वे अपनी लय वापस पा लेंगे और खिताब जीतना शुरू कर देंगे।

एन. महादेवन चेन्नई

अपने पत्र
chennaidesk@deccanmail.com पर भेजें

कमल डावर

पश्चिम में 'खालिस्तानी' शरारत से लड़ें: भारत को अमेरिका और अन्य देशों से संपर्क करना चाहिए

पाकिस्तान के दिवंगत सैन्य तानाशाह जनरल जिया-उल-हक ने अपने देश को जो अमर और भयावह विरासत दी, उनमें से एक भारत के रणनीतिक सीमावर्ती राज्यों पंजाब और जम्मू-कश्मीर में संकट पैदा करने की उनकी "के-2" एक रणनीति थी। इस दुष्ट नीति को लागू करने के लिए "भारत को हज़ार घाव देकर लहूलुहान करना" को हथियार बनाया गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में 1980 के दशक में यह कुछ हद तक सफल भी रहा, जब तक कि इसे देशभक्त सिखों ने खुद ही खत्म नहीं कर दिया। जम्मू-कश्मीर में, पाकिस्तान की शरारतें अभी भी जारी हैं, बीच-बीच में आतंकवाद के साथ-साथ, हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों दोनों के लिए घटनाओं और हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में फिर से उछाल का श्रेय श्रीनगर में सफल विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता संभालने वाली नई सरकार को दिया जा सकता है, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया होगा। यह तो तय है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में माहौल, शांति और प्रगति को बिगाड़ने के प्रयास जारी रखेगा।

हाल ही में, कुछ पश्चिमी देशों, विशेषकर कनाडा में, "खालिस्तानी" शरारतें फिर से उभरी हैं।

पिछले कुछ महीनों से खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों में खुलकर सामने आ रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में शांतिपूर्ण पूजा करने वालों की भीड़ पर खालिस्तानी गुंडों ने हमला किया था, जबकि रविवार को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में भी टकराव की स्थिति बनी। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए सिख फॉर जस्टिस नामक आतंकवादी संगठन के गुरपतवंत सिंह पन्नून ने कथित तौर पर इन दोनों हमलों की साजिश रची थी। कनाडा की पुलिस पर इन हिंसक भीड़ के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है क्योंकि वह उग्र खालिस्तानी समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही। लेकिन भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गिरावट को देखने वालों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भारत विरोधी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अगुआई वाली कनाडा सरकार ने पिछले कुछ सालों में कनाडा के हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की हरकतों और कनाडा में पूजा स्थलों को अपवित्र करने वाली खालिस्तानी भीड़ की निंदा नहीं की है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को भी गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ महीनों में, इन "खालिस्तानी" कट्टरपंथियों ने भारतीय ध्वज को फाड़ने और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे। की प्रशंसा करने की हिम्मत की है।

जैसा कि सर्वविदित है, श्री ट्रूडो, जो अगले वर्ष होने वाले कनाडा के आम चुनाव में लगभग निश्चित हार का सामना कर रहे हैं, अपनी वोट बैंक रणनीति के तहत "खालिस्तानियों" को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, जब हम भारत में कभी-कभी अपने राजनेताओं पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, जो लोगों के हितों से परे है, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे राजनेता अच्छी संगति में हैं! श्री ट्रूडो, अपने देश के दीर्घकालिक हितों की परवाह किए बिना, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निकट भविष्य में भारत-कनाडा संबंध ठीक न हो सकें। हालाँकि, कुछ कनाडाई विपक्षी नेताओं ने इन "खालिस्तानी" चरमपंथियों पर लगाम लगाने में श्री ट्रूडो की स्पष्ट निष्क्रियता की निंदा की है। पूर्व सांसद और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मैक्सिम बर्नियर ने कहा है कि "यह आत्मसंतुष्टि बताती है कि इस देश में 'खालिस्तानी' चरमपंथ क्यों बढ़ता जा रहा है", और उन्होंने कहा कि हालांकि "खालिस्तानी समर्थक" समर्थक कनाडाई सिखों में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनकी मुखर और आक्रामक रणनीति ने समुदाय के भीतर बहुसंख्यक आवाज़ों को प्रभावी ढंग से दबा दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी, जो दुनिया के अधिकांश नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत तालमेल के लिए जाने जाते हैं, विदेश नीति पर शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं और इसे अपने ऊपर छोड़ देते हैं। विदेश मंत्री को ऐसा करने के लिए कहा गया है।

हालांकि, इस मामले में, श्री मोदी ने कनाडा में मंदिर पर हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है और श्री ट्रूडो की सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे "हमारे राजनयिकों को डराने के कायराना प्रयासों" की आलोचना की है। आश्चर्यजनक रूप से, कनाडा सरकार ने एक नामित आतंकवादी, कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का संकेत देते हुए कोई ठोस सबूत देने में विफल रही है, लेकिन भारत पर उसी का आरोप लगाना जारी रखा है।

कुछ विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि निज्जर की हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराने की रणनीति में कनाडा अकेला नहीं है और कहीं न कहीं भारत का "रणनीतिक साझेदार" अमेरिका भी भारत को शर्मिंदा करने में शामिल है। उनका दावा है कि अमेरिका इस बात से नाखुश है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने उसका खुलकर समर्थन नहीं किया और ईरान और रूस से तेल की आपूर्ति जारी रखी। भारत के पूर्वोत्तर में हाल की घटनाएं और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल भी अमेरिका की समग्र रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है। अमेरिका वैसे भी अपनी विदेश नीति में भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" की स्थिति का कभी भी समर्थन नहीं करता है।

भारत को अब अपने उपायों में तेजी लानी होगी

पश्चिमी देशों, खासकर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में "खालिस्तान" के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए। अमेरिका में आने वाले ट्रम्प प्रशासन पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित "खालिस्तानी" संगठनों द्वारा अलगाववाद और हिंसा पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उसे दृढ़ता से प्रभावित करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली को चाहिए कि वह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित सिख शामिल हों, ताकि वे इन देशों का दौरा करें और "खालिस्तान" समर्थकों को समझाएं कि किस प्रकार आईएसआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनका शोषण किया जा रहा है।

हिंदू और सिख धर्मों की समानता और सदियों पुराने बंधन, सिख गुरुओं के हिंदू भाइयों के लिए उनके मूल्य और बलिदान सभी को प्रभावित करना चाहिए। यह अलग बात है कि पश्चिम में "खालिस्तानियों" का नेतृत्व करने वाले लोग आईएसआई या चीन के पे-रोल पर हैं। यह संदेश निश्चित रूप से सिख प्रवासियों तक पहुंचेगा। इसके अलावा, भारत की खुफिया एजेंसियों को पंजाब के अंदर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि इस देश के दुश्मनों द्वारा किसी भी तरह की शरारत को रोका जा सके।

लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं और भारत के पहले सैन्य प्रमुख थे।
रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं और एक रणनीतिक विश्लेषक हैं।

संपादक: कौशिक मित्तर, मुद्रक एवं प्रकाशक: के. सुधाकर; आर. मोहन निवासी संपादक डेक्कन क्रॉनिकल कार्यालय यहां स्थित हैं: चेन्नई: एसपी 3 डेवलप्ड प्लॉट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600032। फोन: (044) 22254750, 222547451 कोयंबटूर: नंबर 2/22 सेंगलीपलायम रोड, एनजीजीओ कॉलोनी पोस्ट, कुरुदमपलायम गांव, कोयंबटूर-641022। फोन: (0422) 2231255, 2231256 हैदराबाद: 36, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद 500 003। फोन: (040) 27803930-4। फैक्स: (040) 27805256. विशाखापत्तनम: सर्वे नंबर 1/3 ए बीच रोड, कैलासगिरी रोपवे के पास, सेक्टर-9 एमवीपी कॉलोनी, विशाखापत्तनम - 530 017. फोन: (0891) 2552333/2552334, फैक्स (0891) 2755285 विजयवाड़ा: नंबर सी 3 और 4, पटामाता, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ऑटो नगर, विजयवाड़ा (एपी)। फ़ोन: (0866) 2555284/2555287, फ़ैक्स (0866) 2555234 राजमुंदरी: वेमागिरी, धवलेश्वरम रोड, राजमुंदरी 533125। फ़ोन: (0883) 2417208, 2417618 अनंतपुर: थापोवन कॉलोनी, बैंगलोर बाय-पास रोड, अनंतपुर 51500 4. फ़ोन: (08554) 276903, फैक्स: 08554-276904 नेल्लोर: सर्वे नंबर 527/2, बुर्राणपुर गांव, वेंकटचलम (एम), चेमुडुगुंटा पंचायत, नेल्लोर। फोन: (0861) 2348581/82, टेलीफैक्स (0861) 2348580 करीमनगर: मकान नं. 1-21-12/1, चेरलभुटकुर रोड, मुगुधुमपुर गांव, करीम नगर - 505186 फोन: 9121181123